चिंतन

सियासी लाभ के लिए चुनाव आयोग को बदनाम न करें

स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं किसी भी मजबूत लोकतंत्र की नींव होती हैं। लोकतंत्र तभी जिंदा रह सकता है जब ये संस्थाएं निष्पक्ष और पूर्ण आजादी से फैसले लें। यही कारण था कि हमारे संविधान में देश की संस्थाओं को आजाद रखने के लिए अनेक प्रावधान किए गए बल्कि अधिकार भी दिए गए। ऐसी ही एक संस्था है चुनाव आयोग। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में चुनाव एक ऐसी बुनियाद है, जिस पर लोकतंत्र की इमारत टिकी हुई है। इस बुनियाद को बनाए रखने में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से जुड़े सिद्धांत और प्रक्रियाएं अहम भूमिका निभाती हैं। इसे चुनाव आयोग ने बाखूबी निभाया भी है। 400 से अधिक राज्य विधानसभा चुनाव, 16 राष्ट्रपति चुनाव, 16 उपराष्ट्रपति चुनाव और 17 राष्ट्रीय चुनाव को सफलतापूर्वक करवाना सामान्य बात नहीं है, लेकिन बीते कुछ दिनों से आयोग को ही कठघरे में खड़ा करने के प्रयास हो रहे हैं, उसकी निष्पक्षता पर उंगली उठाई जा रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। वे लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ रहे हैं। यहां तक कि वे आयोग के अधिकारियों को चेतावनी देने से भी नहीं चूक रहे। यह ठीक है कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों का कड़ा प्रतिवाद करने के साथ यह कहकर उन्हें बेनकाब भी किया कि वे किस तरह अपने आरोपों का जवाब सुनने को उसके समक्ष उपस्थित नहीं हुए। चुनाव आयोग ने बार-बार उन्हें बुलाया, लेकिन लगता है कि वे संवैधानिक संस्था को बदनाम करने पर ही आमादा हैं। राहुल गांधी के साथ-साथ बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तपस्वी यादव भी चुनाव आयोग को निशाने पर ले रहे हैं। वे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के सत्यापन से नाराज हैं। जबकि बिहार में मतदाता सूची के सत्यापन की कार्रवाई अनिवार्य है, लेकिन राजनीतिक दलों द्वारा आयोग की इस कार्रवाई के खिलाफ तरह-तरह से भ्रामक और गलत प्रचार किया जा रहा है। यह ठीक है कि चुनाव आयोग मतदाता सूची के सत्यापन संबंधी फर्जी पोस्ट एवं वीडियो को खोज-खोज कर उन्हें गलत बता रहा है और इसी के साथ सच्चाई भी बयान कर रहा है, लेकिन इसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। चुनाव आयोग को ऐसे भ्रामक वीडियो एवं पोस्ट करने वालों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए। यदि इस तरह की फर्जी न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो शरारती तत्वों का दुस्साहस ही बढ़ेगा। अब तपस्वी यादव को ही लें, उन्होंने पत्रकारवार्ता करके ऐलान कर दिया कि मतदाता सूची से उनका और उनकी पत्नी का नाम काट दिया गया है। हद तो तब हो गई जब तेजस्वी ने अपने वोटर कार्ड का नंबर भी बता दिया। इसके तुरंत बाद चुनाव आयोग ने न केवल इसका खंडन किया बल्कि अब उन्हें नोटिस भेजा है। इसमें पूछा गया है कि उनके पास वोटर कार्ड के दो ईपिक नंबर कैसे आए। बिहार की दीपा विधानसभा के निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी ने नोटिस में कहा है कि आपके द्वारा ईपिक संख्या आएएबी 2916120 दिखाया गया, जो आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया गया है। इससे बिलकुल साफ है कि उनका इरादा केवल चुनाव आयोग को बदनाम करना का है, जो कतई लोकतंत्र के हित में नहीं है। सभी राजनीतिक दलों को चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी संवैधानिक संस्थाओं पर कोई आंच न आए। अगर ये स्वतंत्र नहीं रह पाईं तो लोकतंत्र भी नहीं रह पाएगा।

सियासत
राजकुमार सिंह

विपक्षी एकता पर भारी कांग्रेस-आप टकराव

संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले आप का 'इंडिया' गठबंधन से अलगाव बताता है कि भाजपानीत राजग के चुनावी मुकाबले के बड़े लक्ष्य के साथ हुई विपक्षी एकता परस्पर दलगत हितों के टकराव के ग्रहण से नहीं बच पा रही। वर्ष 2023 के मध्य में बने दो दर्जन विपक्षी दलों के गठबंधन 'इंडिया' से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जदयू और जयंत चौधरी के रालोद की विदाई पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले ही हो गयी थी। जाहिर है, उस अलगाव के दलगत टकराव के अलावा भी कुछ कारण रहे होंगे, लेकिन हाल में आप के 'इंडिया' गठबंधन से अलग होने के पीछे तो उसका कांग्रेस से टकराव ही एकमात्र कारण है। बेशक पहले दिल्ली और फिर पंजाब की सत्ता छीनने वाली आप से कांग्रेस का दलीय हितों का टकराव अस्वाभाविक नहीं, पर यह तो 'इंडिया' गठबंधन में उनके साथ आने से पहले भी सबको पता था।

दिल्ली पर लगातार 15 साल राज करने वाली कांग्रेस अगर वहां विधानसभा में शून्य हो गयी तो उसमें सबसे अहम भूमिका आप की ही रही। गुजरात और गोवा में भी आप की चुनावी मौजूदगी ने कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसके बावजूद 'इंडिया' गठबंधन के बैनर तले ये दोनों दल साथ आये तो इसलिए कि भाजपानीत राजग को विपक्षी एकता बिना चुनौती दे पाना संभव नहीं। तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद 'इंडिया' गठबंधन किसी हद तक वह लक्ष्य हासिल भी कर पाया, जब 2019 के लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर 303 सीटें जीतने वाली भाजपा 2024 में 240 सीटों पर रुक गयी और सरकार के लिए राजग के अपने सहयोगियों पर उसकी निर्भरता बढ़ गयी। निश्चय ही गठबंधन का सबसे ज्यादा लाभ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को हुआ, जो क्रमशः 52 से 99 और पांच से 37 सीटों पर पहुंच गयीं। ध्यान रहे कि कांग्रेस और आप, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और चंडीगढ़ में तो लोकसभा चुनाव मिलकर लड़े, लेकिन पंजाब में एक-दूसरे के विरुद्ध। पंजाब में आप प्रचंड बहुमत से सत्तारूढ़ दल है, जबकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल। ऐसे में मिलकर चुनाव लड़ने से कार्यकर्ताओं और मतदाताओं में तो भ्रम की स्थिति बनती ही, दोनों दलों की साख पर भी सवालिया निशान लग जाता। वैसे दिल्ली में दोनों मिलकर भी भाजपा को फिर सभी सात सीटें जीतने से नहीं रोक पाये। हां, हरियाणा में कांग्रेस 10 में से पांच सीटें जीतने में सफल हो गयी। चंडीगढ़ से भी कांग्रेस के मनीष तिवारी जीते।

कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन का आप को ज्यादा लाभ नहीं हुआ, लेकिन दोनों के बीच तल्खियां बढ़ीं चंद महीने बाद हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव से। कांग्रेस-आप में सीटों के बंटवारे पर बातचीत तो हुई, पर सिरे नहीं चढ़ पायी। नतीजतन आप ने 90 में 88 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिये। आप को तो दो प्रतिशत मत भी नहीं मिल पाये, लेकिन सत्ता की दौड़ में भाजपा से कांग्रेस एक प्रतिशत से भी कम मतों से पिछड़ गयी। आश्चर्य नहीं कि उन तमाम नतीजे से कांग्रेस और आप के बीच बढ़ीं तल्खियां दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक-दूसरे के विरुद्ध मोर्चेबंदी तक पहुंच गयीं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी खाता खोलने में नाकाम रही। कांग्रेस ने इस बार जो चुनावी मोर्चाबंदी की, वह भाजपा के बजाय आप के विरुद्ध ज्यादा नजर आयी। दोनों के

बीच कटुता इतनी बढ़ी कि आप ने कांग्रेस को 'इंडिया' गठबंधन से बाहर निकालने की मांग तक कर डाली। आप से हिसाब चुकता करने का कांग्रेस का दांव कारगर रहा और 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में भाजपा की वापसी हो गयी। मत प्रतिशत और सीटों का गणित संकेत देता है कि अगर कांग्रेस-आप मिलकर लड़े होते तो शायद भाजपा की सत्ता में वापसी इतनी आसान नहीं होती। अरविंद केजरीवाल की आप ने जिस दिल्ली से सत्ता का सफर शुरू करते हुए सबसे कम समय में राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल किया, वहीं वह सत्ता से पैदल हो गयी। ऐसे में आप के पास भावी चुनावी राजनीति में गंवाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, जबकि वह गुजरात, गोवा समेत कई राज्यों में कांग्रेस का चुनावी गणित बिगाड़ सकती है।

हालांकि आप सांसद संजय सिंह द्वारा 'इंडिया' गठबंधन की कार्यशैली पर उठाये गये सवाल अपनी जगह जायज हैं, लेकिन अलगाव की असली वजह कांग्रेस से कटुता निर्णायक मोड़ पर पहुंच जाना ही है। आप सांसद संजय सिंह ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी संसदीय मुद्दों पर टीएमसी और डीएमके जैसे विपक्षी दलों के साथ समन्वय बनाए रखेगी और उनका समर्थन करेगी, जैसा कि ये दल आप का समर्थन करते हैं। निश्चय ही आप की उपस्थिति उन राज्यों में भाजपा की मददगार साबित होगी, जहां उसका कांग्रेस से सीधा मुकाबला रहा है। दरअसल भाजपा या उसकी अगुवाई वाले गठबंधन राजग के विरुद्ध जितने ज्यादा दल चुनाव मैदान में होंगे, विरोधी मत उतने ही ज्यादा बंट जायेंगे। भाजपा विरोधी मतों के इस बिखराव से बचने के लिए ही विपक्षी गठबंधन की कवायद हुई थी, लेकिन दो साल में ही गाड़ी पटरी से उतरती नजर आ रही है।

बेशक गठबंधन की सफलता सभी घटकों के सहयोग, समन्वय और समझदारी पर निर्भर करती है, लेकिन सबसे बड़े दल के नाते इसमें कांग्रेस की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। याद करिए कि जुलाई, 2023 में बनने के बाद से 'इंडिया' गठबंधन की कितनी बैठकें हुईं हैं? संयोजक तो दूर, आज तक सचिवालय या संगठनात्मक ढांचा नहीं बन पाया। दो साल में न तो साझा न्यूनतम कार्यक्रम बना और न ही कभी संयुक्त चुनाव प्रचार नजर आया। हां, संसद में अवश्य कभी-कभी तालमेल दिखा, पर कुछ मुद्दों पर मतभेद भी छिपे नहीं रहे हैं। ऐसे में यह सवाल तो उठेगा ही कि आखिर 'इंडिया' गठबंधन जमीन पर क्यों नहीं उतर पाया? विपक्षी गठबंधन जब जमीन पर ही नजर नहीं आयेगा तो जनता उसके विकल्प बन सकने की क्षमता पर विश्वास कैसे करेगी? विडंबना यह भी है कि कांग्रेस अकसर अपने दलीय हितों के हिसाब से विचार और निर्णय करती नजर आयी है। आप समेत उत्तर भारत के ज्यादातर छोटे दलों ने कांग्रेस के ही परंपरागत जनाधार में सेंधमारी से अपना जनाधार बनाया है। मुद्दे भी कमोबेश समान हैं।

कांग्रेस की दुविधा यह है कि अपने पुनरुत्थान के लिए इन दलों से जनाधार वापस छीनना जरूरी है, जबकि उनसे हाथ मिलाये बिना भाजपा का चुनावी मुकाबला मुश्किल है। इस जटिल राजनीतिक समीकरण में संतुलन पर ही कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' का चुनावी भविष्य निर्भर करता है। आप के अलगाव से उजागर विपक्ष के अंतर्विरोध निश्चय ही केंद्र समेत ज्यादातर राज्यों में सत्तारूढ़ भाजपा और उसकी अगुवाई वाले राजग के लिए उत्साहवर्धक हैं। जाहिर है, लगातार दो लोकसभा चुनाव हार कर एकता की राह पर चले विपक्ष में बिखराव उसके अपने भविष्य के लिए सुखद संकेत नहीं है। अगले लोकसभा चुनाव तो 2029 में होंगे, लेकिन उससे पहले होने वाले विधानसभा चुनावों के परिणामों का विपक्षी मनोबल पर ही नहीं, मतदाताओं के मन पर भी दूरगामी असर पड़ेगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये उनके अपने विचार हैं)
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले आप का 'इंडिया' गठबंधन से अलगाव बताता है कि भाजपानीत राजग के चुनावी मुकाबले के बड़े लक्ष्य के साथ हुई विपक्षी एकता परस्पर दलगत हितों के टकराव के ग्रहण से नहीं बच पा रही। आप के अलगाव से उजागर विपक्ष के अंतर्विरोध निश्चय ही केंद्र समेत ज्यादातर राज्यों में सत्तारूढ़ भाजपा और उसकी अगुवाई वाले राजग के लिए उत्साहवर्धक हैं। लगातार दो लोकसभा चुनाव हार कर एकता की राह पर चले विपक्ष में बिखराव उसके अपने भविष्य के लिए सुखद संकेत नहीं है। अगले लोकसभा चुनाव तो 2029 में होंगे, लेकिन उससे पहले होने वाले विधानसभा चुनावों के परिणामों का विपक्षी मनोबल पर ही नहीं, मतदाताओं के मन पर भी दूरगामी असर पड़ेगा।

व्यापार समझौता
विकेश कुमार बडोला

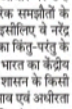

ट्रंप की आक्रामक नीतियों में उलझे द्विपक्षीय संबंध

अपने दूसरे कार्यकाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक नीतियों ने दुनिया में उलझन बढ़ा दी है। पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर भारत के प्रहार के बाद तो ट्रंप भारत के प्रति भी नाटकीय ढंग से अविश्वसनीय, हास्यास्पद तथा अनर्गल वक्तव्य देने लगे हैं। गत सवा दो माह में उन्होंने भारतीय गरिमा को अपने अनेक अप्रत्याशित वक्तव्यों से खंडित किया है। राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिकी फर्स्ट की अपनी चुनावी नीति को धरातल पर क्रियान्वित करने में उन्हें जो भी कठिनाइयां हो रही हैं, उसकी प्रतिक्रिया वे भारत समेत विश्व के भिन्न-भिन्न देशों को आयात-निर्यात शुल्क बढ़ाने की धमकियां देकर, शुल्क वृद्धि करके कर रहे हैं। पाकिस्तान स्थित अपनी सामरिक अवसंरचनाओं को भारत के प्रहार से हुई अधिक हानि के बाद वे भारतीय प्रधानमंत्री से रुष्ट हैं। जहां नरेंद्र मोदी भारतीय लोकतंत्र की आधिकारिक अौपचारिकताओं से बंधकर चुपचाप भारतीय हितों का संरक्षण कर रहे हैं, वहीं ट्रंप भारत के संदर्भ में व्यापारिक समझौतों को भारतीय व्यापार मंत्रियों व प्रतिनिधियों के व्यापार-मंथन के आधार पर नहीं, अपितु नरेंद्र मोदी के साथ आमने-सामने बैठकर चुटकियों में एक संकेत पर अंतिम रूप दे देना चाहते हैं। चूंकि अमेरिकी प्रधान स्वयं में एक व्यापारी हैं, उनके पास अंतरराष्ट्रीय व्यापार का वर्षों पुराना अनुभव है तथा उस आधार पर उन्हें अमेरिका की ओर से अन्य देशों के साथ होने वाले व्यापारिक समझौतों के अमेरिकी हित में निकलने वाले निष्कर्ष भलीभांति ज्ञात हैं, इसीलिए वे नरेंद्र मोदी से भी अपेक्षा कर रहे हैं कि वे उनके अनुसार समझौते का किंतु-परंतु के बिना यथाशीघ्र निस्तारण कर दें। वे भूल रहे हैं कि इस समय भारत का केंद्रीय शासन एक सुशासन प्रणाली के नियम से बंधा हुआ है। ऐसे शासन के किसी भी कार्य, समझौते अथवा निर्णय में भ्रष्टाचार, अनाधिकृत प्रभाव एवं अधीरता का आचरण नहीं है। ट्रंप अपनी बढ़ती आयु तथा इस भय से कि संभवतः अब तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकेंगे, अमेरिकी फर्स्ट की नीति अंगीकार कर जैसे-तैसे अमेरिका के प्रभाव को बढ़ा व विशाल कर देना चाहते हैं। इस आवेश में वे अपने प्रथम कार्यकाल की उन नीतियों को भी भूल चुके हैं, जिनमें उन्होंने इस्लामिक आतंक को कुचलने के लिए व्यापक कार्य किये थे तथा इसी प्रभाव में मोदी की उनसे मैत्री स्थापित हुई थी। वे जैसे-तैसे इस समय की अपनी राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति कर लेना चाहते हैं। उनके साथ का अथवा उनके कार्यालय का कोई भी अन्य पदाधिकारी, यहां तक कि उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस भी, अमेरिका की ओर से वक्तव्य देने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ट्रंप को अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति के रूप में अपना प्रभाव इतना अधिक व्यापक कर देना है कि वे उस आधार पर रूस-यूक्रेन समेत दुनिया के अन्य देशों के मध्य हुए या होते आ रहे युद्धों को समाप्त करने का महत्ती श्रेय लेना चाहते हैं। इस महत्वाकांक्षा के पूर्ण होने पर उन्हें नोबल पुरस्कार प्राप्त करने की अभिलाषा भी है। इतना सब उनके पक्ष में उनके अनुसार होने के लिए उनके पास राष्ट्रपति के रूप में मात्र दो-ढाई वर्ष का ही समय शेष है। अतः वे भारत के संदर्भ में, मोदी के संबंध में भी अपने चिरपरिचित मैत्रीपूर्ण व्यवहार से विमुख हो चुके हैं। उन्हें किसी भांति, चाहे भारत तथा मोदी को हो रुष्ट क्यों न करना पड़े, अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करनी हैं। वे अपनी राजनीतिक एवं व्यापारिक चतुरता दिखाते हुए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि भारत को, विशेषकर उनकी शर्तों पर व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में देर करने वाले मोदी को, नीचा दिखाया जाए। इसके लिए उन्होंने भारत-पाक युद्ध को रुकवाने के लिए युद्ध को पचास से अधिक बार श्रेय दे दिया है। वे रूस के साथ भारत की सामरिक-व्यापारिक मैत्री के लिए भी भारत को अनेक धमकियां दे चुके हैं। चूंकि भारत सुशासन के साथ उभरती हुई एक वैश्विक शक्ति बन रहा है, इसीलिए वह अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करते हुए अमेरिकी प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर लगा हुआ है। भारत को मृत अर्थव्यवस्था बताने वाले तथा पाकिस्तान में तेल स्रोत ढूंढ उसे समृद्ध कर एक दिन भारत को भी उससे तेल खरीदने के लिए विवश कर देने वाले, ट्रंप के नवीनतम वक्तव्यों ने अंततः भारत को प्रतिक्रिया के लिए विवश कर ही दिया है। परिणाम में भारत ने अमेरिका के एफ-35 फाइटर जेट्स को खरीदने के बारे में पूर्व के अनेक किंतुओं-परंतुओं के बाद अब अंतिम रूप से उन्हें निकट भविष्य में नहीं खरीदने की घोषणा कर डाली है। इसके प्रत्युत्तर में ट्रंप ने भारत पर एक अगस्त से लागू होने वाले 25 प्रतिशत शुल्क आरोपण नियम को अब आठ अगस्त तक के लिए टाल दिया है।

(लेखक उत्तरांचल पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

मन से तय होती है जीवन की सही दिशा

संकलित
दर्शन

अकसर समस्याओं में लोग दूसरों को पुकारते हैं जबकि यदि लोग अपने मन को अंतर्मुख करें, तो समाधान उन्हें अपने में ही मिल जाएगा। बस कुछ समय निकाल कर खुद के अंदर झांकने की जरूरत होती है। कहते हैं कि मन से जीवन की दिशा तय होती है, लेकिन ये बड़ा चंचल होता है। इसे समझना आसान नहीं है। मन को दुखी न करो : हमेशा उन विचारों को दूर करने की कोशिश करें जो मन को दुख पहुंचाने वाले हैं। उन बातों को भी मन पर बिलकुल हावी न होने दें जो आपके अंदर नकारात्मकता भरती हैं। मन को पकड़ाकर न बैठो : अकसर मन इधर-उधर भागने लगता है। ऐसे में उसे भागने दो। उसे जबरदस्ती पकड़ाकर रोकने की कोशिश न करो। इसके बाद इसके पीछे जाओ और इसे वापस ले आओ। वह कहते हैं कि इनसान स्वयं अपने मन को खुश रखने के लिए जिम्मेदार है। ऐसे में उसे यह दृढ़ संकल्प करना जरूरी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी व्यक्ति मेरी खुशी नहीं छीन सकता। जीवन को एक सही दिशा देने में मन की विशेष भूमिका होती है। जीवन में ऐसा कुछ नहीं है, जिसके प्रति बहुत गंभीर रहा जाए। वह हाथी में खेलने के लिए एक गेंद है। इसे पकड़े मत रहो। इंसानी जीवन में इच्छा को कभी भी खुद पर हावी न होने दो। इच्छा हमेशा अकेले में शब्द पर लटकती रहती है। ऐसे में जब इंसान में का त्याग कर देता है, तब इच्छा भी समाप्त हो जाती है। जीवन को लेकर गहराई से सोचिए। अतीत में बहुत सी समस्याएं आईं थीं, जो आज नहीं हैं। वे आईं और चली गईं।

ऊर्जा के नाश को रोकता है माथे का तिलक

संकलित
प्रेरणा

भारतीय संस्कृति में तिलक धारण करने का धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से विशेष महत्व रहा है। प्राचीन काल में तीर्थों की पवित्र मिट्टी (शुचितम मृत्तिका) तिलक के रूप में माथे पर लगाई जाती थी। धीरे-धीरे इस मृत्तिका का स्थान चंदन, गोपीचंदन, कुमकुम, भस्म या केसर ने ले लिया। तिलक धारण करने के इन सभी रूपों का उद्देश्य केवल बाह्य सज्जा नहीं, बल्कि अंतरिक चेतना का जागरण है। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो तिलक या टीका लगाने से मस्तिष्क के अग्र भाग में स्थित तंत्रिकाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे तनाव कम होता है और मन एकाग्र होता है। तिलक का स्थान मस्तक के उस भाग पर होता है, जिसे 'आज्ञा चक्र' कहा जाता है। यह स्थान निर्णय क्षमता, स्मृति और विवेक का केंद्र होता है। जब इस स्थान पर चंदन या भस्म लगाया जाता है, तो वह मानसिक शीतलता, आत्म-संयम और आस्था का संचार करता है। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि मनुष्य की दोनों भृकुटियों के मध्य में मुख्य महत्वपूर्ण नर्व पॉइंट होता है। तिलक उस जगह लगाने से एकाग्रता रखने में मदद मिलती है। तिलक का व्यवहार ब्राह्मणों या सनातन भारतीय समाज के अन्य वर्गों तक ही सीमित नहीं रहा है। क्षत्रिय राजा के जीवन में तिलक धारण करने को विशेष महत्व दिया जाता था। भगवान श्री रामचंद्र चंदन का तिलक लगाया करते थे। आज भी आप किसी देवालय में जाएं तो पंडित सर्वप्रथम आपके माथे पर तिलक ही लगाएगा।

गणेशोत्सव की तैयारी

देशभर में गणेशोत्सव की तैयारी चल रही है। कोलकाता में भगवान गणेश की प्रतिमा को अंतिम रूप देता एक कलाकार।

आज की पाती

सेजबहार का हाल-बेहाल

सेजबहार हाउसिंग बोर्ड कालोनी का हाल-बेहाल है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने मकान बेचकर इतिश्री कर ली। अब सप्लाई के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाते रहो। अफसर मस्त हैं। जवाबदारी लेने को कोई तैयार नहीं। रजिस्टर में शिकायतें लिखवाकर कर्मचारी औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। दो महीने बीतने के बाद भी शिकायतों का कोई निराकरण नहीं हो पा रहा है। रात में अंधेरे से भी कालोनीवासी परेशान हैं। स्ट्रीट लाइट महीने में कुछ दिन ही जलती है। जलकर और मेंटनेंस का पैसा लेकर हाउसिंग लोगों को सुविधाएं देने में असफल है। -शाहीन बेगम, रायपुर

ट्रेंड

ये नया भारत है

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से जिन्हें परेशानी हो रही है, उन्हें पता नहीं धरती से ही बताना चाहता हूं कि ये नया भारत है। ये बाबा भोलेनाथ को पूजने के साथ देश के दुश्मनों के ताबूत में कीलें ठोकने वाला भी बन जाता है।
-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

जयंती पर नमन

'हम वहाँ थे, जहां हो नहीं है और जहां होने अभी, वह अत्यन्तिम पन्थ अनूठा' राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जी की लेखनी का तेज था। संस्कृति, साहित्य और राष्ट्रनिष्ठा से समृद्ध उनकी रचनाकार्य स्वभाव: युवों तक हमें समर्पित करती रहेंगी। राष्ट्रकवि को उनकी पावन जयंती पर सादर नमन!
-योगी आदित्यनाथ, सीएम, उप्र

सड़कें बद से बदतर

उप्र में भाजपा की डिग्री सरकार जो 'गड्ढा मुक्ति' के नाम पर अरबों का जो पंड बिखाया था, वो आजकल्हों की जेब के गड्ढे तो नहीं बना सकी। सड़कें बद से बदतर हो गयी। आजा जाने से सड़क बन जाए।
- अखिलेश यादव, सपा सांसद

वाणी का सदुपयोग

वाणी का अविवेकी प्रवाह वह बवंडर सीधे को लताड़ वार देता है और वाणी का संयमी को लिटा देता है। वाणी और वाणी पर नियंत्रण, इसका सदुपयोग बरसे हम अग्नी बत्ती और रुसी वो रखा वार लगाते है।
- आशुतोष राणा, अभिनेता

करंट अफेयर

विचारधारा से आमदनी तक कश्मीर में नया सोशल मीडिया खेल

सुरक्षा एजेंसियों ने कश्मीर घाटी में कुछ युवाओं के बीच अलगाववादियों और आतंकवादियों का महिमामंडन करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने के एक नये चलन का खुलासा किया है। इसके पीछे का कारण वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं, बल्कि फॉलोवर बढ़ाने और विज्ञापनदाताओं से धन कमाने की एक सोची-समझी रणनीति है। श्रीनगर पुलिस कहरुवा का मुकाबला करने के लिए सोशल मीडिया साइट पर नजर रखने का हरसंभव प्रयास कर रही है। श्रीनगर पुलिस को इस प्रक्रिया का पता तब चला जब उसने ऐसे अकाउंट से जुड़े कुछ युवाओं को हिरासत में लिया। युवाओं ने पूछताछ के दौरान, कथित तौर पर स्वीकार किया कि भड़काऊ तस्वीरों -जैसे कि प्रतिबंधित हिजबुल मुजाहिदीन के मारे गए आतंकवादी बुरहान वानी की तस्वीर - का इस्तेमाल फॉलोवर का एक बड़ा आधार हासिल करने के लिए एक सोची-समझी रणनीति थी। युवाओं ने बताया कि इससे वे बाद में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर विज्ञापनदाताओं से विज्ञापन हासिल करके उससे पैसे कमाने में सक्षम हो सके। अधिकारियों ने बताया कि बड़ी संख्या में फॉलोअर, विशेषकर सीमापार और विदेशों से, हासिल करने के बाद, अकाउंट संचालक इन तस्वीरों को पहाड़ों या चिनार के पेड़ों जैसी तस्वीरों से बदल देते थे।

ऑफ बीट

भक्त को बचाने स्वयं प्रकट हुए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग

गुजरात के द्वारका धाम से करीब 16 किलोमीटर दूर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ये भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों में दसवें ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। माना जाता है ये मंदिर करीब 2500 साल पुराना है। पौराणिक मान्यता और कथा-भगवान शिव का एक अनन्य भक्त सुप्रिय नामक व्यापारी था। जिसे एक दिन दारुक नाम के राक्षस ने कारागार में बंद कर दिया और तरह-तरह के कष्ट दिए, लेकिन वह अपनी भक्ति पर अटल रहा। आखिर में दारुक ने एक दिन जब वह पूजा में मग्न था, उस पर अत्यंत क्रोध करना शुरू कर दिया, लेकिन वह अपने आराध्य भगवान शिव से प्रार्थना करता रहा, आखिर में भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में कारागार में प्रकट हुए और सुप्रिय को पाशुपतास्त्र दिया ताकि वह अपनी रक्षा कर सके। इस अस्त्र से सुप्रिय ने राक्षस दारुक तथा उसके अनुचरों का वध कर दिया। उसी समय से भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मंदिर परिसर में भगवान शिव की पद्मासन मुद्रा में एक 80 फुट की विशालकाय मूर्ति है। गर्भगृह में पुरुष भक्त धोती पहनकर ही प्रवेश कर सकते हैं, वह भी तभी जब उन्हें अभिषेक करवाना है। शिवपुराण के अनुसार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद उसकी उत्पति और माहात्म्य संबंधी कथा सुनने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

हिन्दुस्तान 1936

दिल की उम्र

हंसते-खेलते लोगों के दिल अचानक थमने की खबरें जब सवालों के अंबार लगा रही हों, तब शिकागो के शोधार्थियों का 'हार्ट एज' या हृदय की उम्र मापने की कोशिश सुखद ही कही जाएगी। यह प्रयास हृदय-संबंधी रोगों से बचाव का एक अहम आधार बन सकता है। *जेएएमए कार्डियोलॉजी* में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया है कि नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी फीनबर्ग स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधार्थियों ने 30 से 79 वर्ष की उम्र के करीब 14,000 लोगों के दिल का अध्ययन करके हृदय-संबंधी जोखिमों को आंकने की कोशिश की है। इसके लिए उन्होंने पारंपरिक उपायों के बजाय नई तकनीक का सहारा लिया। अध्ययन के मुताबिक, जहां महिलाओं के दिल की उम्र उनकी वास्तविक आयु से चार वर्ष अधिक होती है, तो वहीं पुरुषों के मामले में यह अंतर सात वर्ष अधिक होता है। गौरतलब है, शोध में शामिल लोगों का हृदय-संबंधी रोगों का कोई इतिहास नहीं है। इन शोधार्थियों ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (प्रिवेंट रिस्क एज कैलकुलेटर) विकसित किया है, जिसकी मदद से हर कोई अपने दिल का हाल जान सके। इस कैलकुलेटर को उम्र, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर जैसी कुछ जरूरी सूचनाएं देकर कोई भी आसानी से जान सकता है कि उसके दिल की उम्र क्या है?

जाहिर है, इससे हृदय-संबंधी भावी खतरों का अनुमान लगाने में मदद मिल सकेगी। दरअसल, हममें से कई लोग ऐसे हैं, जिनको दिल से जुड़े जोखिम कम करने के लिए दवा लेनी चाहिए, पर जानकारी के अभाव में वे ऐसा नहीं कर रहे। ऐसे आंकड़े भी हैं, जो बताते हैं कि दुनिया भर में तकरीबन 39 फीसदी युवाओं में कोलेस्ट्रॉल का स्तर तय मानक से अधिक है और उनमें से अनेक इससे अनजान हैं। ऐसे में, इस कैलकुलेटर की मदद से न सिर्फ आसानी से अपने दिल का हाल समझ सकते हैं, बल्कि बचाव के उपाय भी किए जा सकते हैं। इसका फायदा जन-स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी उठाया जा सकता है और लोगों को हृदय संबंधी रोगों के प्रति जागरूक किया जा सकता है। इस अध्ययन की अगुवाई करने वाली वरिष्ठ चिकित्सक सादिया खान यह स्पष्ट करती हैं कि हार्ट-एज कैलकुलेटर चूंकि अगले दस साल की 'भविष्यवाणी' करता है, इसलिए अगर असली उम्र और दिल की आयु में पांच वर्ष या इससे अधिक का अंतर दिखता है, तो डॉक्टर के पास जाना ही बेहतर है। इससे हम कई खतरों से बच सकेंगे।

'हार्ट एज' मापने की बेशक अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि ये खतरे की सीमित पहचान करते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल लोग सचेत होने के लिए कर सकते हैं।

ऐसे प्रयासों की आज कितनी जरूरत है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में अभी जितनी मौतें हो रही हैं, उनमें हृदयाघात या दिल संबंधी दूसरे रोगों से मरने वालों की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत है। माना जाता है कि दुनिया भर में हर साल 1.79 करोड़ लोग हृदय-रोगों से दम तोड़ते हैं। भारत में ही पिछले दिनों जारी 'सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम' सर्वे में पाया गया है कि 2019-21 के दौरान गैर-संचारी रोगों से होने वाली कुल मौतों में करीब 30 प्रतिशत मौतें हृदय संबंधी बीमारियों के कारण हुईं। इतना ही नहीं, अब तो आम लोगों में यह धारणा भी पनपने लगी है कि कोरोना महामारी ने उनके दिल को खासा नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में, 'हार्ट एज' मापने जैसे प्रयास हमें अपने सेहतमंद भविष्य के लिहाज से कुछ आश्वस्त कर सकते हैं। इस तरह के कैलकुलेटर की बेशक अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि ये खतरे की सीमित पहचान करते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल लोग समय रहते सचेत होने के लिए कर सकते हैं। वैसे भी, सजग रहकर ही हम अपने व अपनों के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल कर सकते हैं।

टैरिफ से भी ज्यादा तनाव थोपते ट्रंप

यहां सुनें वर्जन

आलोक जोशी | वरिष्ठ पत्रकार

डोनाल्ड ट्रंप आए दिन भारत को धमकी देते हैं। उनकी नजर भारत के विशाल बाजार पर है, जो वह खोना नहीं चाहते। वह तनाव बढ़ा कर अपना काम निकालना चाहते हैं।

लंबी खींचतान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ, यानी सीमा शुल्क लगाने का एलान कर ही दिया। हालांकि, बाद में इसे एक हफ्ते में लागू करने की घोषणा की गई, मगर 25 फीसदी शुल्क और रूस से आयात पर जुर्माना हमारे लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। भारत के ज्यादातर व्यापार संगठन, कारोबारी और विशेषज्ञ भी 15 से 20 प्रतिशत टैरिफ की उम्मीद पाल रहे थे। और, उसमें भी उन्हें उम्मीद थी कि थोड़ी सौदेबाजी के बाद कई चीजों पर छूट मिल सकती है। फिलहाल ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा।

ट्रंप ऐसा कर सकते हैं, इसकी आशंका तो थी, मगर इतना और इस अंदाज में करेंगे, यह शायद कम लोगों ने सोचा था। जाहिर है, इस खबर से हड़कंप मच गया और इतने पर ही बस नहीं। ट्रंप ने दो और कारनामे किए। भारतीय समय के मुताबिक, गुरुवार की सुबह उन्होंने एक्स पर फिर अपनी पोस्ट डाली, 'मुझे परवाह नहीं है कि भारत रूस के साथ क्या करता है। वे दोनों मिलकर अपनी मरी हुई अर्थव्यवस्थाओं को गर्त में ले जा सकते हैं, मुझे क्या!' और, दूसरा दांव उन्होंने यह चला कि पाकिस्तान के साथ एक सौदा भी कर डाला। ट्रंप ने भारत को चिढ़ाने के अंदाज में दूध सोडाल पर लिखा- 'हमने एक करार किया है, जिसके तहत पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर पाकिस्तान के विशाल तेल भंडार के विकास का काम करेंगे। हम उस कंपनी का चुनाव कर रहे हैं, जो इस साझेदारी को आगे बढ़ाएगी। कौन जाने, आगे उठाया जा सकता है कि तेल बेचने लगे।' मतलब साफ है, भारत के सामने वह पाकिस्तान की पीठ पर हाथ रखने का दांव खेल रहे हैं। अमेरिका यही तो दशकों से करता आया है।

आखिर ट्रंप के इस हाव-भाव के पीछे क्या वजह हो सकती है और अब इसके आगे का रास्ता क्या है? भारत को दोस्त बताने के पीछे ट्रंप की मंशा साफ है। उनकी नजर भारत के विशाल बाजार पर है, जो वह किसी कीमत पर खोना नहीं चाहते। अमेरिका में भारतवंशियों का एक बड़ा समुदाय भी है, जिसे नाराज करना अब शायद वहां भी किसी राजनेता के लिए महंगा सौदा है। भारतीय और अमेरिकी अधिकारियों के बीच व्यापार-वार्ता के कई दौर इस बात के सबूत हैं कि दोनों ही पक्ष इस मामले को महत्वपूर्ण मानते हैं। अमेरिका दुनिया भर में अपना माल बेरोक-टोक बेचना चाहता है और बदले में दूसरे देशों को टैरिफ में कुछ रियायत का चारा डाल रहा है। मगर अब एक चीज साफ दिख रही है। भारत अमेरिका को एकदम खुला मैदान देने को राजी नहीं है, खासकर दुग्ध और कृषि उत्पादों के मामले में। साफ है कि अमेरिका की मंशा पूरी नहीं हो पा रही है। ट्रंप का आक्रामक अंदाज और पाकिस्तान का इस्तेमाल इसका साफ संकेत है।

टैरिफ के एलान के बाद से जितने भी जानकारों की राय सामने आई है, टैरिफ के असर पर बात करने से पहले उन सभी का यह मानना है कि यह ज्यादा दिन का मामला नहीं है, ट्रंप सौदेबाजी में भारत पर दबाव बनाने के लिए यह पैंतरा आजमा रहे हैं और जब समझौता हो जाएगा, तो तस्वीर बदल जाएगी। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो भारत की कंपनियों को या अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हो सकता है, इस पर अलग-अलग राय हैं। कुछ जानकार मानते हैं कि जीडीपी पर आधे प्रतिशत तक का असर दिख सकता है। मगर बाजार के एक बड़े खिलाड़ी ने मजाकिया अंदाज में हिसाब जोड़कर दिखाया कि भारत अमेरिका को जो निर्यात करता है, वह भारत के जीडीपी का करीब-करीब दो प्रतिशत होगा। अगर इसमें 10 प्रतिशत की गिरावट आई, तो वह होगा, जीडीपी का 0.2 प्रतिशत। अभी भारत की विकास दर छह प्रतिशत से ऊपर है। यानी, इस घाटे से पार पाने के लिए बारह दिन के बराबर ज्यादा काम करना पड़ेगा।

हालांकि, कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जीडीपी बढ़ने की रफ्तार कम से कम 0.4 प्रतिशत तक गिर सकती है। वैसे, समझौता हो भी गया, तो उसमें कितनी रियायत मिल सकेगी, कहना मुश्किल है। मगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में तीन प्रतिशत की शोध आने पर ढोल-ताशे के साथ अपनी पीठ थपथपाने वाले डोनाल्ड ट्रंप साढ़े छह प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था को आखिर 'मरी हुई अर्थव्यवस्था' किस हक से कह सकते हैं? भारत सरकार ने इस मामले में संयम और बड़प्पन दिखाया है। मगर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बाकायदा गिनाया है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह तमाम बाधाओं के बावजूद तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने व्यापार समझौते की राह में आ रही अड़चनों का जिक्र भी किया और बताया कि केंद्र सरकार किन-किन वर्गों के हितों की रक्षा के लिए डटी हुई है। मगर साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि भारत एक ऐसा समझौता चाहता है, जिसमें दोनों देशों का फायदा हो।

उधर, अमेरिकी वाणिज्य मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि बातचीत का भविष्य अब भारत के हाथों में है, हमारी टीम तो भारत से हताश हो गई है। इस हताशा का ही असर ट्रंप के फैसले और उनके अंदाज में दिख रहा है। इसमें पाकिस्तान का सहारा लेना ही दिखा रहा है कि वह हताशा के किस चरण तक पहुंच चुके हैं। हालांकि, उनके उस बयान की काफी चीर-फाड़ भी हो चुकी है और माना यही जा रहा है कि पाकिस्तान ने या अमेरिका की पाक समर्थक लॉबी ने डोनाल्ड ट्रंप को झांसा दे दिया है। पाकिस्तान में तेल खोजने की अनेक कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं और अगर वास्तव में इतना बड़ा तेल भंडार उसके पास होता, जिसके ख्वाली पुलाव ट्रंप पका रहे हैं, तो वहां पेट्रोल 250 रुपये लीटर क्यों बिक रहा होता?

शेयर बाजार ने भी शुरुआती झटके के बाद टैरिफ का असर करीब-करीब झाड़ फेंका। ज्यादातर लोगों की राय यही है कि कुछ दिन की सौदेबाजी के बाद भारत और अमेरिका के बीच एक बेहतर समझौता होने के आसार अभी खत्म नहीं हुए हैं। यह उम्मीद इस बात पर भी टिकी हुई है कि इन टैरिफों की कीमत अमेरिकी उपभोक्ताओं को ही चुकानी है, क्योंकि उन्हें ही महंगा सामान खरीदकर यह ड्यूटी भरनी होगी। इसलिए भी जानकार मानते हैं कि ट्रंप बहुत लंबे समय तक किसी भी देश पर बहुत ऊंचा टैरिफ लगाकर नहीं रख सकते।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

सबसे ज्यादा इंसानों वाले देश भारत में बाघ भी सबसे ज्यादा

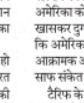

यहां सुनें वर्जन

साकेत बडोला | निदेशक, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान

दुनिया में बाघों की लगातार घटती संख्या और निरंतर सिकुड़ते आवास को देखते हुए साल 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में पहला वैश्विक बाघ सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें 13 बाघ रेंज देशों के सर्वोच्च प्रतिनिधियों ने अपने लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किया। यह लक्ष्य था- वर्ष 2012 तक विश्व में बाघों की संख्या को दोगुना करना। बढ़ती जनसंख्या के दबाव में यह लक्ष्य असंभव तो नहीं, लेकिन मुश्किल अवश्य जान पड़ रहा था। मगर बाघ संरक्षण को दिशा में किए गए वैश्विक और सामूहिक प्रयासों से अविश्वसनीय-सा लगने वाला यह लक्ष्य हासिल कर लिया गया।

इस उपलब्धि में भारत का खासा योगदान रहा है। हमने तय समय से पहले ही बाघों की संख्या दोगुनी करने में सफलता हासिल कर ली थी। आज आलम यह है कि दुनिया के 70 प्रतिशत जंगली बाघों का घर भारत ही है। यह घटनाक्रम बताता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाघ के बारे में बात करने की हमारे लिए कितनी प्रासंगिकता है! विश्व की सर्वाधिक आबादी वाले देश भारत में बाघों की इतनी बड़ी संख्या होना किसी आश्चर्य से कम नहीं है।

बाघ के बारे में बात करना हमारे लिए कितना प्रासंगिक है, यह इसी से सिद्ध होता है कि दुनिया के 70 प्रतिशत जंगली बाघ भारत में हैं।

दरअसल, भारतीय संस्कृति में वनों व वन्य-जीवों से लगाव, सरकारों द्वारा इस संबंध में किए गए प्रयास, वनकर्मियों के समर्पण और प्रकृति के प्रति देशवासियों के अनुराग के कारण ही हम यह सफलता पा सके हैं। हमारे यहां साल 1973 में ही 'प्रोजेक्ट टाइगर' के नाम से बाघों के संरक्षण को लेकर दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण कार्ययोजना शुरू की गई, जिसके तहत देश के नौ क्षेत्रों का 'टाइगर रिजर्व' के रूप में चयन किया गया। इस योजना की अभूतपूर्व सफलता आज दुनिया में किसी भी संरक्षण-योजना में बतौर उदाहरण पेश की जाती है। इसी योजना से देश में बाघों की संख्या 2022 में बढ़कर 3,682 हो गई, जो 2006 में 1,411 थी। अब तो टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़ाकर 50 से ज्यादा कर दी गई है।

टाइगर रिजर्व के रूप में संरक्षित क्षेत्र न सिर्फ बाघों की सुरक्षित रिहाइश बन चुके हैं, बल्कि ये अन्य संकटग्रस्त वन्य-जीवों के लिए भी महत्वपूर्ण शरणस्थली साबित हो रहे हैं। देश की 300 से अधिक नदियों के उद्गम स्थल भी इन्हीं संरक्षित क्षेत्रों में स्थित हैं। इस तरह, देश में बाघों के संरक्षण का प्रयास न सिर्फ सफल रहा, बल्कि देश की जैव-विविधता एवं स्वच्छ जल के संरक्षण में भी खासा मददगार साबित हुआ।

बाघ संरक्षण की सफलता के साथ कई अन्य उपलब्धियां भी हैं। जैसे, भारत द्वारा प्रत्येक चार वर्ष पर की जाने वाली बाघों की गणना को उसके वृहद एवं विस्तृत स्वरूप के कारण 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड' में शामिल किया गया है। जंगली बाघों की गिनती में श्रेष्ठतम तकनीक का प्रयोग भी विस्मित करने वाला है। इस काम में पारिस्थितिकी मॉनिटरिंग के लिए मोबाइल एप का उपयोग, बाघों की तस्वीर पाने के लिए जंगलों में स्वचालित कैमरों का प्रयोग और प्राप्त तस्वीरों के विश्लेषण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल खासा उल्लेखनीय है। बाघों की गिनती की यह प्रक्रिया हमने खुद विकसित की है, जो प्रत्येक भारतवासी के लिए गर्व का विषय है। दिलचस्प बात यह भी है कि बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों व उनके आवासों के संरक्षण के लिए जिस 'इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस' का गठन किया गया है और जिसमें संसार के तमाम देशों द्वारा किए गए प्रयासों व अनुसंधानों को समेटा गया है, उसका एक महत्वपूर्ण मकसद बाघ संरक्षण में भारत को मिली सफलता का लाभ उठाना भी है।

हर साल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए 29 जुलाई को एक विशेष दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस बाघों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने, उनके आवास के संरक्षण व विकास के लिए नए सिरे से प्रयास करने और बाघों की घटती संख्या पर वैश्विक स्तर पर विमर्श करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। चूंकि पारिस्थितिकी तंत्र का यह शीर्ष शिकारी जीव जैव-विविधता का संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लिहाजा बाघ संरक्षण, मात्र एक संकटग्रस्त प्रजाति का संरक्षण न होकर पृथ्वी पर मानव जीवन के संरक्षण और संवर्द्धन का भी प्रयास है। इसलिए हमें समग्रता में वन्य-जीवन को देखने का नजरिया भी विकसित करना होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

नया कहां से आएगा

पुरानी कहावत है, 'ओल्ड इज गोल्ड।' जो पुराना है, वह सोना है; यानी सोने जैसा कीमती है। सोना एक चमत्कारी धातु है, वह कभी पुरानी नहीं पड़ती, कीमत भले ही कम ज्यादा हो, लेकिन उसका महत्व बना रहता है। पुराना सोना होने का अर्थ है कि जो कुछ भी पुराना है, वह सोने जैसा ही बहुमूल्य है। यह कहावत आज तक सही थी, इसीलिए चल रही थी। लेकिन अब पहली बार, पुराना सोना यानी कीमती नहीं रहा। समय इतना बदला है कि आज नए का स्वीकार और नए का सम्मान करना जरूरी हो गया है। आपने देखा होगा, आजकल हर विज्ञापन में लिखा होता है 'नया'; तभी लोग खरीदते हैं।

कंप्यूटर के कारण अब चीजें बड़ी जल्दी पुरानी पड़ जाती हैं। समय की गति बदल गई है। हर साल मोबाइल का नया मॉडल, कंप्यूटर के नए रूप, नए आविष्कार, नए विचार पैदा हो रहे हैं। जमाने की पूरी हवा ही बदल गई है। इसे 'ब्रेन वॉशिंग' कहते हैं। मस्तिष्क की नसें, बुद्धि के केंद्र, जो आज तक सोए पड़े थे, वे जाग रहे हैं। इसलिए लोग सब कुछ नया चाहते हैं। और सब कुछ, अतिशीघ्र। कोई भी रुकने को तैयार नहीं है।

इसीलिए अब पुराना बोझ बन गया है। इसके बीच ओशो एक नए मनुष्य का और स्वर्णिम भविष्य का संदेश लेकर अवतरित हुए। उनकी नजर में समूचा अतीत मानवता की छाती पर एक बोझ बन गया है। उसे जल्दी से जल्दी त्यागने की जरूरत है। हम समय के चौराहे पर खड़े हैं, यहां से पीछे जाने का कोई उपाय नहीं है। अब भूतकाल स्वर्णिम नहीं है, भविष्य स्वर्णिम है। लेकिन उसे स्वर्णिम बनाने के लिए भूतकाल को पूर्णतया छोड़ना होगा। नई पीढ़ी के लिए, नौजवानों के लिए अतीत को त्यागना एक बड़ी जिम्मेदारी है।

ओशो ने गुहार लगाई है कि जागो, नए मनुष्य में मानवता का भविष्य समाया हुआ है। पुराना मनुष्य मरने के लिए बाध्य है। परमाणु हथियार और सभी विनाशकारी उपाय वैश्विक आत्महत्या की तैयारी हैं। दुनिया के बुद्धिमान लोगों पर निर्भर है कि वे पुराने मनुष्य से, उसकी सोच से, उसके धर्म की अवधारणा से नाता तोड़ लें। अतीत में धर्म सिखाते थे कि दुनिया को त्याग दो। मैं तुम्हें संसार से प्रेम करना सिखाता हूं, ताकि इसे बचाया जा सके। नया मनुष्य पुराने में कोई परिष्कार नहीं है।

नया मनुष्य पुराने की मृत्यु की घोषणा है, और बिल्कुल नए मनुष्य के जन्म का अर्थ है- राष्ट्र, धर्म, जेंडर, रंग या क्षेत्र के भेदभाव से मुक्त मनुष्य। नया मनुष्य अखंड मानवता का घोषणा-पत्र है।

नया मनुष्य पुराने की मृत्यु की घोषणा है, और एक बिल्कुल नए मनुष्य का जन्म है- बिना किसी राष्ट्र के, बिना किसी धर्म के, बिना किसी पुरुष और महिला, काले और गोरे, पूर्व और पश्चिम या उत्तर और दक्षिण के भेदभाव के। नया मनुष्य एक अखंड मानवता का घोषणा-पत्र है। यह दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी क्रांति है। नया कहां से आएगा? आपके भीतर से, आपके रूपांतरण से पैदा होगा। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है।

अमृत साधना

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 04 अगस्त, 1950

नागरिक स्वतंत्रता की शर्त

भारत में सरकार नागरिक स्वतंत्रता पर कुठाराघात कर रही है, ऐसा आरोप संसद में पं. हृदयनाथ कुंजरू ने किया था। यह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने उसका कराया जवाब दिया है कि जो थोड़े-से व्यक्ति उपद्रव करने के लिए नागरिक स्वतंत्रता की आवाज उठाते हैं, उनके लिए करोड़ों व्यक्तियों की सुरक्षा खतरे में नहीं डाली जा सकती। यह जवाब बड़ा उद्धत मालूम पड़ता है, परन्तु इस संबंध में बोलते हुए सरदार पटेल ने जो बातें प्रकट कीं, वे यदि गलत नहीं हैं, तो इससे हमें आश्वस्त होना चाहिए और कामना करनी चाहिए कि सरकार अपने इस रुख पर दृढ़ रहे।

सरदार ने अपने खरे ढंग से बताया है कि नागरिक स्वतंत्रता के हिमायती होते हुए भी अवरोधक नजरबन्दी का जो कदम सरकार को उठाना पड़ रहा है, उसका कारण यही है कि वह देश में सांप्रदायिकता, भाषाई प्रांतों के प्रतिपादन जनित पार्थक्यता, हिंसात्मक विद्रोह या कुल-जलूल प्रचार द्वारा अशान्ति को पनपने देकर सद्व्यवस्थित गणराज्य को खतरे में नहीं पड़ने देना चाहती। इस सिलसिले में उनका यह रहस्योद्घाटन चौंकाने वाला है कि जिस गुटने महात्मा गांधी की हत्या की, वह उतने पर ही संतुष्ट नहीं हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री नेहरूजी की भी हत्या करना चाहता है। नेहरूजी की हत्या के षड्यंत्र की उड़ती चर्चाएं तो पहले भी सुनने में आईं, परन्तु अब अधिकृत सूत्र से यह बात सामने आई है, जिससे सारे राष्ट्र का व्यग्र हो जाना स्वाभाविक है।

...नेहरूजी की हत्या के षड्यंत्र की बात सरदार ने कुछ ऐसे ढंग से कही है कि जिससे हिन्दू महासभाई लोगों से उस षड्यंत्र का संबंध भासित होना अस्वाभाविक नहीं। साथ ही हिन्दू राज्य के प्रतिपादकों को भी खतरे के रूप में उन्होंने उल्लेख किया है। इस सबसे हिन्दू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कुछ धारणाएं जो बनी हुई हैं, उन्हें बल मिलना स्वाभाविक है। इन संस्थाओं को अपने कार्यों द्वारा यह प्रमाणित करना चाहिए कि यह बात सत्य नहीं है... । भाषाई राज्यों की मांग को एक समय स्वयं कांग्रेस ने भी उठाया था, परन्तु आज जिस तरह वह उठाई जा रही है- खासकर मास्टर तारासिंह जिस तरह पंजाबी भाषी पृथक प्रांत के नाम पर सिखिस्तान की आवाज उठा रहे हैं- वह सचमुच खतरनाक है, यह मानना ही होगा।

गिने-चुने रह गए पुस्तकालयों के दिन

अनुलोम-विलोम

पुस्तकालय

एक समय था, जब किताबें सांस लेती थीं, जब उनके पन्नों की सरसराहट में जीवन की धड़कनें सुनाई देती थीं। पुस्तकालयों की खामोशी में न जाने कितने सपने जन्म लेते थे, कितने विचार पंख लगाकर उड़ान भरते थे। वह दौर था, जब किताबें सिर्फ कागजों का ढेर नहीं, बल्कि आत्मा की खुराक थीं। मगर आज, जब उंगलियां स्क्रीन पर नाच रही हैं और आंखें डिजिटल चमक में डूब गई हैं, तब किताबें चुपके-चुपके एक कोने में सिमटने लगी हैं। उनकी आवाज अब धीमी पड़ चुकी है और उनके साथ-साथ हमारी संवेदनाएं, सोच और मानवता भी कहीं खोती जा रही है। यह सिर्फ पुस्तकालयों का दर्द नहीं, यह उस सभ्यता का दर्द भी है, जो किताबों की गोद में पली-बढ़ी है और अब डिजिटल दुनिया की आंधी में बिखर रही है।

एक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में 18 से 24 वर्ष के आयु-वर्ग वाले 70 प्रतिशत से अधिक युवा किताबों के बजाय सोशल मीडिया और ऑनलाइन कंटेंट को प्राथमिकता देते हैं। यह महज एक संख्या नहीं, बल्कि उस बदलते परिदृश्य की कहानी है, जहां किताबें प्रासंगिक नहीं मानी जातीं। यही कारण है कि आज पुस्तकालय वीरान पड़े हुए हैं। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जैसे संस्थान में, जो कभी किताब-प्रेमियों का बड़ा तीर्थस्थल था, अब आगंतुकों की संख्या लगातार घट रही है। रिपोर्ट बताती है कि भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों की संख्या पिछले दो दशकों में 20 प्रतिशत तक घट गई है और जो बचे हैं, उनमें से कई रखरखाव और संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। वे अब उपेक्षा और उदासीनता के प्रतीक बन गए हैं।

इन सबके लिए नई पीढ़ी को दोष देना आसान है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमने उन्हें किताबों की दुनिया से जोड़ने की कोशिश की? आज जन्म लेते ही बच्चे टैबलेट और स्मार्टफोन की चमक में खो जाते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे (2022) के अनुसार, भारत में 10 से 18 वर्ष के आयु-वर्ग वाले 65 प्रतिशत बच्चे रोजाना तीन घंटे से अधिक समय स्क्रीन पर बिताते हैं। कहानियां अब दादी-नानी से नहीं, यू-ट्यूब से सुनी जाती हैं। शिक्षक ऑनलाइन नोट्स और पीडीएफ लिंक भेजने में व्यस्त हैं। और अभिभावक? वे भी बच्चों के साथ स्क्रीन टाइम में हिस्सेदार बन गए हैं। इस दौड़ में किताबें कहीं पीछे छूट गई हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट बता रही है कि दुनिया भर में पुस्तकालयों का उपयोग 1990 के दशक की तुलना में 40 प्रतिशत तक कम हो गया है। यह आंकड़ा हमें सोचने पर मजबूर करता है। अब हमें यह तय कर ही लेना चाहिए कि अगली पीढ़ी को हम क्या देना चाहते हैं?

आरके जैन 'अरिजीत', टिप्पणीकार

किताबों को लेकर थमा नहीं आकर्षण

यह कहना गलत होगा कि आज पुस्तकालयों के दिन लद गए हैं। वास्तव में, पठन-पाठन को लेकर युवाओं में रुचि फिर से बढ़ने लगी है। यही कारण है कि वे बेशक पुस्तकालय न जा पाएं, लेकिन किताबों का डिजिटल संस्करण पढ़ने के लिए किंडल जैसी सुविधाओं का उपयोग जरूर कर रहे हैं। इसीलिए, अब कहा जाता है कि यदि आपके हाथ में मोबाइल है, तो लाखों की संख्या में पुस्तकों की कौन कहे, पुस्तकालयों की सैर की जा सकती है। बस इसके लिए गूगल पर जाइए और शब्दों के संसार में खो जाइए।

यह तो रही डिजिटल दुनिया की बात, लेकिन जिनको किताबों के हार्डबाउंड या पेपरबैक संस्करण पढ़ने होते हैं, वे अब भी पुस्तकालय जरूर जाते हैं। वहां जाकर शांति और निश्चिंतता के साथ अध्ययन करने की ललक आज भी बदस्तूर कायम है। हां, यह अलग बात है कि पुस्तकों के महंगे होने और असीमित रचना-संसार के एक जगह पर उपलब्ध न रहने से अब पुस्तकालयों का नवीन स्वरूप हमारे सामने आने लगा है। इसे अध्ययनशाला कहते हैं, जिसमें घर से अपनी पुस्तकें ले जाकर पुस्तकालय में आराम से घंटों कुर्सी-मेज पर बैठकर शांत चित्त से अध्ययन किया जा सकता है। शोर-शराबे से दूर इस तरह के अध्ययन के लिए लोग कुछ शुल्क चुकाने को भी तैयार रहते हैं। यह भी कारण है कि अब कई पुस्तकालयों को नया रूप दिया जा रहा है। लोगों में पढ़ने की ललक कितनी है, इसका एक प्रमाण हाल में प्रयागराज महाकुम्भ में भी दिखा। वहां संगम स्नान के साथ-साथ श्रद्धालु नेशनल बुक ट्रस्ट के रीडिंग लाउंज में साहित्यिक आनंद में गोते लगाते भी दिखे। अब तो शहरों से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में और छोटे-छोटे बाजार में भी पुस्तकालय/ अध्ययनशालाएं देखी जा सकती हैं, जिनसे पता चलता है कि आज भी बच्चे पुस्तकों के अध्ययन पर किस कदर भरोसा करते हैं।

हालांकि, इन सबके बावजूद दोराय नहीं है कि आज पुस्तकालयों पर दबाव पहले की तुलना में बढ़ गया है। एक तो किताबें पहले से अधिक महंगी हो गई हैं, इसके बाद एक ही स्थान पर अपने विषय और रुचि से संबंधित किताबें नहीं मिल पातीं। इन्हीं कारणों से कभी-कभी लगता है कि पुस्तकालय अब खत्म होने लगे हैं, लेकिन व्यापकता में देखें, तो ऐसा नहीं है। हर दौर में समय के अनुरूप कुछ-न-कुछ परिवर्तन होते ही हैं, हमें इसे स्वीकार करना होगा। पुस्तकालय अब जिस तरह से डिजिटल रूप में दिखने लगे हैं, उससे इसकी प्रासंगिकता और अधिक बढ़ गई है। हमें पाठकों के विवेक पर भरोसा बनाए रखना होगा।

दिनेश सिंह, चिकित्सक

गैरी कॉस्पारोव | पूर्व विश्व चैंपियन, शतरंज

पुतिन शांति प्रयासों को अस्वीकार करते आ रहे हैं और युद्ध को लंबा खींचना चाहते हैं। एकजुट दुनिया के पास पूर्ण, तत्काल और बिना शर्त युद्ध-विराम के पक्ष में सैद्धांतिक रुख अपनाकर उन्हें रोकने की पर्याप्त शक्ति है।

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • सोमवार • 4 अगस्त • 2025
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

हीरो वह होता है जो स्वतंत्रता के साथ आई जिम्मेदारियों को समझता है।
-वॉल्ट डाइज़ेन

मिसाल हो कायम

बेंगलुरु स्पेशल कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को रेप के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 48 वर्षीय एक घरेलू सहायिका ने कई दफा रेप करने का आरोप लगाया था। बीते साल उस पर चार मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से पहले मामले में दोषी ठहराया गया है। उस पर आईपीसी की धाराएं 376 (2के) (प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा रेप), 376(2)(एन) (बार-बार रेप) 354(ए) (कपड़े उतारने के लिए हमला या बल प्रयोग), 354(सी)(ताकझांक), 506 (सबूतों को गायब करना), सूचना प्रोद्यौगिकी अधिनियम की धारा 66(ई) लगाई गईं। 1632 पन्नों की चार्जशीट के साथ इलेक्ट्रॉनिक व अन्य 183 सबूत पेश किए गए। बीते साल

कर्नाटक सैक्स स्कैंडल के उछलने के बाद प्रज्वल का नाम सामने आया था, उस पर पचास से ज्यादा महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप है। पीड़ित अमूमन हासन, मैसूर व होलेनरासीपुर व करीबी इलाकों की हैं। हासन के इस सांसद के वहीं के स्टेडियम में सैकड़ों की तादाद में बिखरे मिले पेन ड्राइवों में तकरीबन तीन हजार सेक्स क्लिप व तस्वीरें मिलते ही मामले ने तूल पकड़ लिया था। कई वीडियो वह खुद बना रहा था। वीडियो वायरल होते ही वह देश छोड़ कर भाग गया। प्रधानमंत्री रहे दादा, मुख्यमंत्री रहे चाचा और मंत्री पिता का यह इंजीनियर बेटा 2019 में देश में तीसरा सबसे कम उम्र का सांसद बनने पर चर्चा में आया था। दादा के चेताने पर जर्मनी से लौटा तो एयरपोर्ट से ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पैसों और हैसियत के बल पर महिलाओं के साथ हैवानियत करने वाले की ताकत का ही भय है कि पचास में से केवल चार पीड़िताओं ने सामने आने का साहस किया। हालांकि पहले वह खुद को बेकसूर और आरोपों को झूठा बता रहा था। मगर पकड़े जाने के बाद उसने कन्नड़ टीवी चैनल को भेजे वीडियो में दादा, मां-बाप, जनता दल (सेक्युलर) के कार्यकर्ताओं व राज्य के लोगों से माफी मांगी। लोगों में अपराधियों के प्रति गुस्से के चलते मामले को दबाया नहीं जा सका। बेशक, यह न्याय प्रक्रिया की ताकत है जिसने राज्य चलाने वालों की विकृति को न सिर्फ उघेड़ा, बल्कि कमजोर वर्ग की उस स्त्री को न्याय देकर छिपी बैठीं पीड़िताओं को न्याया का भरोसा दिया है। हालांकि अभी दोषी ऊपरी अदालत जाने को स्वतंत्र है। वहां तक मामला जाने और सलाखों के पीछे जाने में सालों लग सकते हैं, जिससे बच जाना जरूरी हैं। ताकतवर दोषियों को सजा दिला कर कड़ा संदेश देना बेहद जरूरी है।

चुनाव में धांधली का दावा

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि पिछले लोक सभा चुनाव में करीब 100 सीटों पर धांधली हुई और इनमें से 15 सीटों पर धांधली नहीं हुई होती तो नरेन्द्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। कांग्रेस पार्टी के विधि, मानवाधिकार एवं आरटीआई विभाग द्वारा शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय विधिक सम्मेलन में राहुल गांधी ने दोहराया कि कर्नाटक में एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में हेरफेर के जो सबूत मिले हैं, वे एटम बम की तरह हैं। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में इस बात का

सबूत दिया जाएगा कि कैसे लोक सभा चुनाव में धांधली हुई। लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष पिछले कुछ दिनों से चुनाव में धांधली के दावे और आरोप लगा कर चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। उनका तो यहां तक कहना है कि वह तो 2014 से ही चुनाव प्रणाली को संदेह की नजर से देखते रहे हैं। उन्हें बारंबार लगा है कि प्रचंड जीत (भाजपा की) हासिल करने की क्षमता आश्चर्यजनक है। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में जो हुआ, उसने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया है। तमाम आरोपों और संदेहों के बरक्स चुनाव आयोग ने ज्यादातर मौकों पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। राहुल गांधी के ताजा दावे पर भी चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। चुनाव आयोग की चुप्पी के चलते अब विपक्ष यह बताने और साबित करने पर आमादा है कि चुनाव में धांधली को कैसे अंजाम दिया जाता है। बेशक, चुनाव आयोग के लिए प्रायः दुविधापूर्ण स्थिति दरपेश रहती है। पराजित पक्ष चुनावी धांधली का आरोप लगाने से नहीं चूकता। ऐसे में चुनाव आयोग के लिए जरूरी हो जाता है कि तमाम संदेहों और आरोपों कर माकूल और संतोषजनक प्रतिक्रिया देते हुए स्थिति को साफ करे। उसके कार्यकलाप में कहीं से भी हड़बड़ी नहीं दिखनी चाहिए। न ही यह लगना चाहिए कि वह किसी प्रकार का पक्षपात कर रहा है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि सख्ती से अपनी छवि को बनाए रखे। तभी वह चुनाव की शुचिता की अनिवार्यता को बनाए रख सकता है। जरूरी है कि चुनावी राजनीति में शिरकत करने वाले तमाम पक्षों के साथ बैठक करके उनके संदेहों का निराकरण करे। संदेहों (खासकर बेबजह के) की तो कतई कोई गुंजाइश रहने ही न पाए।

चिंता/मुनीश भाटिया

देर से मिला न्याय पीड़ा ही तो है

न्याय में देरी, न्याय से इनकार है'-यह प्रसिद्ध कथन हमारे देश की न्याय प्रणाली की सबसे ज्वलंत समस्याओं में से एक को उजागर करता है। जब कोई व्यक्ति पीड़ा और अन्याय का शिकार होता है, तो अदालत की शरण इस विश्वास के साथ लेता है कि उसे समय पर न्याय मिलेगा। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है, और केस वर्षों या दशकों तक चलता रहता है, तो उस व्यक्ति का भरोसा धीरे-धीरे न्याय प्रणाली से उठने लगता है। यही स्थिति आज भारत की अदालतों में लाखों लंबित मामलों के कारण बन चुकी है, जहां न्याय मिलना लंबे, थकाऊ और अक्सर निराशाजनक इंतजार का रूप ले चुका है।

भारत में न्यायिक प्रणाली की जमीनी सच्चाई यह है कि 5 करोड़ से अधिक मामले विभिन्न स्तरों की अदालतों में लंबित हैं। इनमें संपत्ति विवाद, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, हत्या, रेप, भ्रष्टाचार, सरकारी मामलों से जुड़े मुकदमे और व्यापारी विवाद जैसे मामले शामिल हैं। देरी के पीछे सबसे बड़ा कारण है-न्यायिक संसाधनों की कमी। भारत में प्रति दस लाख लोगों पर न्यायाधीश की सीमित संख्या है, जबकि वैश्विक मानक इससे कई गुना अधिक है। इससे न्यायाधीश एक दिन में दर्जनों मामलों की सुनवाई करते हैं, और कई बार केवल तारीखें देकर काम चलाना पड़ता है। उस पर वकीलों की हड़तालें, सरकारी गवाहों का अनुपस्थित रहना, फॉरेंसिक रिपोर्टों में देरी और बार-बार स्थगन भी प्रक्रिया को और जटिल बना देते हैं। कई सिविल अदालतों में अभी भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। फाइलों का ढेर, धीमा प्रचलित सिस्टम और पेपर-आधारित प्रक्रिया पूरे तंत्र को बोझिल बना देते हैं। जो तकनीकी समाधान उपलब्ध हैं-जैसे ई-कोर्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-फाइलिंग-उनका पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है, खासकर ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में। इस चुनौतीपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने के लिए कई कदम उठाने जरूरी हैं। न्यायपालिका में खाली पद तत्काल भरे जाएं, नई अदालतों की स्थापना भी हो, ई-फाइलिंग, ई-सम्मन, ऑनलाइन सुनवाई जैसी प्रणालियों को अधिक व्यापक बनाया जाए। मध्यस्थता, पंचायती न्याय और समझौता समितियों को प्रोत्साहित किया जाए। न्याय केवल कानूनी शब्द नहीं, बल्कि आमजन का लोकतंत्र और संविधान पर विश्वास बनाए रखने का आधार है। देर से मिला न्याय वास्तव में पीड़ित के लिए एक और पीड़ा बन जाता है।

ट्रंप का भारत को 'तोहफा'

सामयिक

विनीत नारायण

हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयातित सामान पर 25% टैरिफ और रूस से तेल और हथियारों की खरीद के लिए अतिरिक्त दंड की घोषणा की। यह कदम भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में महत्त्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है, विशेष रूप से तब जब दोनों देश एक व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। ट्रंप ने भारत और रूस को 'मृत अर्थव्यवस्था' (डेड इकॉनमी) कह कर निशाना बनाया और भारत के उच्च टैरिफ और गैर-मौद्रिक व्यापार बाधाओं को इसका कारण बताया।

ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में वैश्विक व्यापार को प्रभावित करने वाली आक्रामक टैरिफ नीतियों को अपनाया है। 7 अगस्त, 2025 से लागू होने वाले 25% टैरिफ का ऐलान करते हुए ट्रंप ने इसके लिए भारत के रूस से तेल और सैन्य उपकरणों की खरीद को प्रमुख कारण बताया। उनके अनुसार, भारत रूस का सबसे बड़ा ऊर्जा खरीदार है, जो यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान के समय में अस्वीकार्य है। इसके अतिरिक्त, ट्रंप ने भारत के उच्च टैरिफ (जिसे उन्होंने दुनिया में सबसे अधिक बताया) और गैर-मौद्रिक व्यापार बाधाओं की भी आलोचना की। ट्रंप ने पहले 20-25% टैरिफ की संभावना जताई थी, लेकिन अंतिम घोषणा में अतिरिक्त दंड भी शामिल किया गया। यह कदम भारत के फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, रत्न और आभूषण और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है, जो अमेरिका के साथ भारत के व्यापार के महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं।

कांग्रेस नेता और लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ट्रंप के 'मृत अर्थव्यवस्था' वाले बयान का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। कहा, 'हां, ट्रंप सही हैं। हर कोई जानता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मृत है, सिवाय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के। मुझे खुशी है कि ट्रंप ने वह तथ्य सामने रखा। दुनिया जानती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है। भाजपा ने अडानी को मदद करने के लिए अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया।' राहुल ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए, विशेष रूप से नोटबंदी और 'त्रुटिपूर्ण' जीएसटी अर्थव्यवस्था के पतन के कारण बताए। उन्होंने यह भी पूछा कि ट्रंप के भारत-पाकिस्तान सीजफायर को लेकर बार-बार किए जा रहे दावों पर प्रधानमंत्री की चुप्पी क्यों है? कांग्रेस पार्टी ने इस टैरिफ को भारत की विदेश नीति की विफलता के रूप में चित्रित किया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, 'राहुल गांधी ने पहले ही इस खतरे में चेतावनी दे दी थी। यह टैरिफ हमारी अर्थव्यवस्था, निर्यात, उत्पादन और रोजगार पर

असर डालेगा। हम अमेरिका को फार्मास्यूटिकल्स निर्यात करते हैं, और 25% टैरिफ से ये महंगे हो जाएंगे जिससे मांग कम होगी और उत्पादन तथा रोजगार पर असर पड़ेगा।' कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए और टैरिफ को भारत के व्यापार, एमएसएमई और किसानों के लिए हानिकारक बताया। अन्य विपक्षी नेताओं ने भी इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना की। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 'बुरे दिनों की शुरुआत' बताया, जबकि असदुद्दीन ओवैसी ने ट्रंप को 'व्हाइट हाउस का जोकर' कह कर उनकी आलोचना की।

वहीं, अर्थशास्त्रियों ने इस टैरिफ के भारत की अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव को लेकर मिश्रित राय व्यक्त की है। कुछ का मानना है कि इसका प्रभाव सीमित होगा जबकि अन्य ने दीर्घकालिक नुकसान की चेतावनी दी है। इंवेस्टमेंट इनफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया (इक्रा) की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, 'प्रस्तावित टैरिफ और दंड हमारी अपेक्षा से अधिक हैं, और इससे भारत की जीडीपी की वृद्धि पर असर पड़ सकता है। प्रभाव की गंभीरता दंड के आकार पर निर्भर करेगी।' अर्नेस्ट एंड यंग इंडिया (ईवाई) के व्यापार नीति विशेषज्ञ अमनेश्वर सेन ने कहा, 'टैरिफ से समुद्री उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, चमड़ा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होंगे। ये क्षेत्र भारत-अमेरिका व्यापार में मजबूत हैं, और टैरिफ से इनकी प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो सकती है।' फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक डवलपमेंट के राहुल अहलूवालिया ने चेतावनी दी कि टैरिफ भारत को वियतनाम व चीन जैसी अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कमजोर कर सकता है। उनके अनुसार, निर्यात आपूर्ति शृंखलाओं के भारत की ओर स्थानांतरण की संभावना नहीं है।

हालांकि, कुछ विशेषज्ञों ने आशावादी रुख भी अपनाया है। फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल ने कहा, 'हालांकि यह कदम दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे निर्यात पर असर डालेगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि यह अल्पकालिक घटना होगी और दोनों पक्ष जल्द ही एक स्थायी व्यापार समझौते पर पहुंच जाएंगे।' भारत सरकार ने इस मुद्दे पर सतर्क और संयमित रुख अपनाया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में कहा, 'हम राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। भारत ने एक दशक में 'फ्रैजाइल फाइव' से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने का सफर तय किया है।' सरकारी सूत्रों ने संकेत दिया है कि भारत तत्काल जवाबी टैरिफ लगाने की बजाय बातचीत का रास्ता अपनाएगा। एक सूत्र ने कहा, 'चुप्पी सबसे अच्छा जवाब है। हम बातचीत की मेज पर इस मुद्दे को हल करेंगे।'

कुल मिलाकर 25% टैरिफ और अतिरिक्त दंड ने भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में नया तनाव पैदा कर दिया है। राहुल गांधी और विपक्ष ने इसे सरकार की आर्थिक और विदेश नीति की विफलता के रूप में प्रस्तुत किया है, जबकि अर्थशास्त्रियों ने इसके मिश्रित प्रभावों की ओर इशारा किया है। जहां कुछ क्षेत्रों पर तत्काल असर पड़ सकता है, वहीं भारत के पास अन्य बाजारों में विविधता लाने और बातचीत के जरिए समाधान खोजने का भी अवसर है। यह स्थिति न केवल आर्थिक, बल्कि भू-राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक हितों को संतुलित करना होगा। देखना यह है कि आने वाले दिनों में सरकार इस समस्या से कैसे निपटती है।

(लेख में विचार निजी हैं)

युद्ध और विध्वंस की चर्चा और तस्वीरें टीवी स्क्रीनों और मोबाइलों पर देखते में बच्चों में व्यापक भुखमरी दिखने के बाद भी हमारी चेतना कुंद ही बनी रहे और आत्मा चीत्कार न उठे तो जान लीजिए कि आज का मीडिया और प्रौद्योगिकी जनसंहार को सामान्य घटना बनाए दे रहे हैं।

एम.के. वेणु, पत्रकार@mkvenu1

भावना-संवेदना श्रीराम शर्मा आचार्य

और क्या था हमारे पास? हमारे पास थी भावना-संवेदना। यह भी हमने अपने कुटुंबियों के लिए, बेटे-बेटी के लिए नहीं लगाई। हमने अपनी भावना एवं संवेदना को इस संसार में रहने वाले व्यक्तियों के दुःखों के निवारण के लिए हमेशा उपयोग किया। हमेशा सोचा कि किसी के पास दुःख है, तो उसे किस तरह से दूर कर सकते हैं। जो भी धन था, उसे भी भगवान के कार्य में खर्च कर दिया। इससे हमें बहुत मिला, इतना कि आपको बतला नहीं सकते। हमें लोग कितना प्यार करते हैं, यह आपको नहीं मालूम। लोग यहां आते हैं, तो कहते हैं कि हमें गुरुजी का दर्शन मिल जाता तो कितना अच्छा होता। यह क्या है? यह है हमारा प्यार, जो हमने उन्हें दिया है तथा उनसे हमने पाया है। गांधी जी ने भी दिया था एवं उन्होंने भी पाया। हमने तो कहीं अधिक पाया है। मरने के बाद तो कितने ही व्यक्तियों की लोग पूजा करते हैं। भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं। भगवान श्रीकृष्ण की जय बोलते हैं, जबकि उस समय लोगों ने उन्हें गालियां दी थीं। हमारे मरने के बाद कोई आरती उतारेगा कि नहीं, मैं नहीं कह सकता परंतु आज कितने लोगों ने आरती उतारी है, प्यार किया है, इसे हम बतला नहीं सकते। यह क्या हो गया? यह है हमारा 'बोया-काटा' सिद्धांत। यह है हमारी आराधना-समाज के लिए, भगवान के लिए। मित्रो, हमने पत्थर की मूर्ति के लिए नहीं, वरन समाज के लिए काम किया है। समाज को ही भगवान कहते हैं। हमने ऐसा ही किया है। हमें दो मालियों की कहानी हमेशा याद रहती है। एक राजा ने एक बगीचा एक माली को दिया तथा दूसरा बगीचा दूसरे माली को। एक ने तो बगीचे में राजा का चित्र लगा दिया और नित्य चंदन लगाता, आरती उतारता तथा एक सौ आठ परिक्रमा करता रहा। इसके कारण बगीचे का कार्य उपेक्षित पड़ा रहा। बगीचा सूखने लगा। दूसरा माली तो राजा का नाम भी भूल गया परंतु वह निरंतर बगीचे में खाद-पानी डालने, निराई करने का काम करता रहा। इससे उसका बगीचा हरियाली से भरा-पूरा होता चला गया। राजा एक वर्ष बाद बगीचा देखने आया तो पहले वाले माली को उसने हटा दिया जो एक सौ आठ परिक्रमा करता और आरती उतारता था। दूसरे माली का अभिनंदन किया, उसे ऊंचा उठा दिया जिसने वास्तव में बगीचे को सुंदर बनाने का अनथक प्रयास किया था।

रीडर्स मेल

झूठ के पांव नहीं होते

'झूठ के पांव नहीं होते' यह एक बार फिर से सिद्ध हुआ है। मालेगांव विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित सहित सभी सातों आरोपी बरी कर दिए गए हैं। एक सैन्य अधिकारी को जिस प्रकार आतंकवादी घोषित करने का प्रयास किया गया है, वह अक्षम्य है। वास्तव में न्याय तभी पूर्ण माना जाएगा जब निर्दोष लोगों को फंसाने का प्रयास करने वालों के ऊपर कोर्ट का डंडा चले। आखिर, इन निर्दोषों का अपराध क्या था? क्या यही कि वे हिन्दुत्व की बात प्रमुखता से रखते थे या सावरकर की हिन्दुत्ववादी विचारधारा से प्रभावित थे? मात्र राजनीतिक सत्ता की चाह के कारण कथित 'सेक्युलर' लोगों ने एक साध्वी, एक वीर जवान जो अपना समस्त जीवन धर्म और राष्ट्र की सेवा को समर्पित करते हुए होम हो जाता है, से न सिर्फ उनका कर्म जीवन छीन लिया, बल्कि उन्हें उस षड्यंत्र के कलंक में डाला गया जो संभव ही नहीं था। अब न्यायालय का कर्त्तव्य है कि सुनिश्चित करे कि उन्हें उनके जीवन का सम्मान और गौरव भी प्राप्त हो।

युवराज पल्लव, ई मेल से

वोकल फॉर लोकल का आह्वान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बार फिर कहा है कि हमें ज्यादातर वो ही सामान खरीदना चाहिए जो देश में ही तैयार होता है अर्थात हमें वोकल फॉर लोकल की राह पर चलने की जरूरत है। प्रधानमंत्री का कहना है कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह सब जरूरी है। अगर इतिहास के पन्नों पर नजर दौड़ाएं तो पता चलेगा कि स्वदेशी ही हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम का मूल मंत्र रहा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन चला कर देश को आजाद कराने में मुख्य भूमिका निभाई थी। अगर हमारे देश की वस्तुओं और उत्पादों की मांग विदेशों में बढ़ती है तो सरकार को इनका निर्यात और आसान करना चाहिए ताकि छोटे से छोटा कारोबारी भी आसानी से देश की वस्तुओं का निर्यात कर सके। लेकिन ध्यान रखना होगा कि विदेशी कंपनियों के कारण जिन लोगों को देश में रोजगार मिला है, अगर स्वदेशी के कारण उन कंपनियों को नुकसान होगा तो यकीनन वे अपने कर्मचारियों की छंटनी करेंगी। तो यह भी जान लें कि इससे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी?

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

एकतरफा मित्रता दुर्बलता होती है

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शायद अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। आये दिन अपने बेतुके बयान दे रहे हैं। जब से उन्होंने अपना दूसरा कार्यकाल संभाला है, कोई दिन नहीं जाता जब किसी देश को टैरिफ की धमकी न देते हों। उनके टैरिफ रेट प्रति दिन घट-बढ़ रहे हैं। वो नहीं जानते कि व्यापार जब दो व्यक्तियों या देशों के बीच होता है तो उससे दोनों पक्ष प्रभावित होते हैं। कोई देश इतना मूर्ख या कमजोर नहीं होता कि अमेरिका द्वारा थोपा गया टैक्स रेट तो अमेरिका को दे देगा और अपने सामान बिना कुछ लिए-दिए अमेरिका में बेचेगा। ट्रंप के बड़बोलेपन की सीमा तब लांघ गई जब उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को 'मृत' कह डाला जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में सर्वाधिक तेज गति से निरंतर बढ़ने वाली चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान लेने वाली है। अब दिल्ली को भी सारे संकोच छोड़ कर अमेरिका को भी उसी की भाषा में उत्तर देना चाहिए क्योंकि एकतरफा मित्रता दुर्बलता की सूचक होती है।

डॉ. नरेन्द्र ढोंक, मेरठ

letter.editorsahara@gmail.com

वैश्विक चेतना का उपग्रह

'निसार' योगेश कुमार गोयल

श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 30 जुलाई की शाम जीएसएलवी-एफ16 रॉकेट के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी (नासा) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित 'निसार' (नासा-इसरो सिंथेटिक अपरचर रडार) उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। यह उपग्रह न केवल एक तकनीकी चमत्कार है, बल्कि विज्ञान, शोध, वैश्विक सहयोग और मानवीय प्रतिबद्धता का युगांतकारी प्रतीक भी है।

'निसार' को सूर्य-समकालिक ध्रुवीय कक्षा में 747 किमी. की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है, जहां से यह अगले तीन से पांच वर्षों तक निरंतर पृथ्वी की निगरानी करेगा और प्रत्येक 12 दिन में पूरी पृथ्वी का स्कैन करेगा तथा एक बार में 240 किमी. क्षेत्र को कवर करने की अद्वितीय क्षमता रखता है। इस उपग्रह को धरती की गहराइयों और उसकी सतह पर होने वाले बदलावों की सटीक, विस्तृत और सतत निगरानी करने के लिए डिजाइन किया गया है। 'निसार' इसरो और नासा के दस वर्षों के संयुक्त परिश्रम का परिणाम है।

'निसार' उपग्रह की दो प्रमुख विशेषताएं (एल-बैंड और एस-बैंड की दोहरी रडार प्रणाली तथा स्वीपएसएआर तकनीक) इसे अत्याधुनिक उपग्रहों की श्रेणी में खड़ा करती हैं। इस उपग्रह के एल-बैंड रडार को नासा ने विकसित किया है, जो 1.25 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और 24 सेमी तरंगदैर्ध्य पर काम करता है। यह रडार वर्फ, घने जंगलों और धरती की गहराई में होने वाले परिवर्तनों को मापने में सक्षम है। वहीं इसरो द्वारा विकसित एस-बैंड रडार 3.2 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और 9.3 सेमी तरंगदैर्ध्य पर कार्य करता है, जो सतह पर होने वाली सूक्ष्मतम हलचल को भी दर्ज कर सकता है। इस प्रकार 'निसार' का यह दोहरा रडार सिस्टम भूगर्भीय घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं, वनस्पति परिवर्तनों, कृषि गतिविधियों और मानवजनित प्रभावों की निगरानी के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगा।

यह उपग्रह दिन-रात, किसी भी मौसम में, बादलों, अंधकार या घने जंगलों की परवाह किए बिना सतत डेटा एकत्रित करता रहेगा। इसका रिजॉल्यूशन 5 से 10 मीटर के बीच होगा जिससे बड़े क्षेत्र में बहुत सूक्ष्म परिवर्तन भी पकड़

में आएंगे। इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन के अनुसार, 'निसार' से मिलने वाला डेटा न केवल भारत और अमेरिका, बल्कि पूरी दुनिया के लिए अमूल्य होगा। उपग्रह प्रति दिन लगभग 80 टेराबाइट डेटा जनरेट करेगा जिसे पूरी तरह ओपन-सोर्स के रूप में मुफ्त में साझा किया जाएगा। इसका लाभ वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, नीति-निर्माताओं, किसानों और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को समान रूप से मिलेगा। 'निसार' से संबंधित डेटा कृषि के लिए भी उपयोगी होगा। यह उपग्रह फसलों की वृद्धि, मिट्टी की नमी, मौसमी प्रभाव, रोग और कीट आक्रमण, और संभावित नुकसान का पूर्वानुमान लगाने में सहायक सिद्ध होगा। इसके माध्यम से सरकारें कृषि बीमा योजनाओं को अधिक वैज्ञानिक, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से लागू कर सकेंगी। पर्यावरणीय क्षेत्र में 'निसार' जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की सटीक जानकारी प्रदान करेगा। यह समुद्र स्तर में वृद्धि, वर्फ पिघलने, तटीय कटाव, वनस्पति आवरण में परिवर्तन और भूजल स्तर की निगरानी करेगा। इससे पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता, जैव-विविधता संरक्षण, वनों की स्थिति और मानवजनित प्रभावों का अध्ययन किया जा सकेगा। आपदा प्रबंधन की दृष्टि से भी यह उपग्रह क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। इसके जरिए भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी जैसी आपदाओं के प्रारंभिक संकेतों को पहचाना जा सकेगा जिससे समय रहते चेतावनी देकर जान-माल की हानि को कम किया जा सकेगा।

भारत और अमेरिका की साझेदारी ने दिखा दिया है कि जब दो राष्ट्र साझा उद्देश्य, पारदर्शिता और वैज्ञानिक उत्कंठा के साथ एकजुट होते हैं, तब विश्व को अभूतपूर्व उपलब्धियां मिलती हैं। 'निसार' के माध्यम से भारत और अमेरिका पूरे ग्रह को एक साथ देखना, समझना और संरक्षित करना सीख रहे हैं। यह मिशन मानवता के भविष्य की रक्षा, पर्यावरण संतुलन के पुनर्निर्माण और पृथ्वी की बदलती धड़कनों को जानने की दिशा में उठाया गया निर्णायक कदम है। यह उपग्रह वैज्ञानिक शोध एवं नवाचार को नई दिशा देने के साथ-साथ नई पीढ़ी को पृथ्वी और पर्यावरण के प्रति अधिक सजग बनाने में भी मदद करेगा। 'निसार' के माध्यम से विश्व को ऐसा शक्तिशाली उपकरण प्राप्त हुआ है, जो धरती की सतह, उसकी परतों, संसाधनों और संकटों को जानने की हमारी क्षमता को व्यापक और सटीक बनाएगा। यह केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि मानवीय चेतना का विस्तार है, ऐसा वैज्ञानिक यंत्र, जो हमारी पृथ्वी की नब्ज को सुन सकेगा और समय रहते बदलावों के प्रति हमें सचेत करेगा। इसीलिए 'निसार' को 'वैश्विक चेतना का उपग्रह' कहा जाना उपयुक्त होगा।

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया काज़ी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3, 4 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा तथा 1209-1210, बाराखंभा लाल, नवमंत्र हाउस, 21 के.जी. मार्ग नई दिल्ली से प्रकाशित। । स्थानीय संपादक - रत्नेश सिंह*।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 011-23352369, 011-23352372, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 144

जारी रहे बातचीत

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर जो 25 फीसदी शुल्क लगाने का निर्णय लिया है, वह शायद अंतिम दर न हो। अगर वह भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद बढ़ाने पर लगाने वाले जुर्माने की अपनी धमकी पर अमल करते हैं तो यह दर और भी अधिक हो सकती है। वहीं अगर भारत के वार्ताकार अंतिम समय में किसी तरह का व्यापक समझौता कर पाने में कामयाब होते हैं तो यह दर कम भी हो सकती है। यह भी गौर करने लायक है कि इस प्रमुख शुल्क दर के कई अपवाद भी होंगे। कुछ वस्तुएं जो भारत-अमेरिका व्यापार का एक बड़ा हिस्सा तैयार करती हैं जैसे मोबाइल फोन, उनके लिए ट्रंप की घोषणा से परे अलग शुल्क दर हो सकती है। अमेरिकी प्रशासन अपनी शुल्क दरों के मुद्रास्फीति संबंधी प्रभाव को कम से कम करने के लिए उत्सुक है। अमेरिकी बाजारों के लिए तैयार होने वाले आईफोन का अधिकांश हिस्सा अब भारत में असेंबल किया जाता है, चीन में नहीं।

इसके बावजूद भारत पर लगने वाले शुल्क की मौजूदा दर चिंताजनक है। विकसित देश मसलन जापान, कोरिया और यूरोपीय संघ आदि को 15 फीसदी शुल्क दर का सामना करना पड़ रहा है। भारत के अधिकांश समकक्ष विकासशील देश जिनमें बांग्लादेश और वियतनाम आदि शामिल हैं, उन पर 19-20 फीसदी का शुल्क लगाया गया है। भारत पर लगाया गया 5 फीसदी का अतिरिक्त शुल्क देश के निर्यात को प्रभावित कर सकता है। ट्रंप एक चंचल प्रवृत्ति के नेता हैं और यह जरूरी है कि उनके प्रशासन के साथ लगातार संवाद कायम रखा जाए। ऐसा इसलिए आवश्यक है ताकि कहीं बेहतर दर हासिल करने का मौका हमारे हाथ से निकल न जाए।

स्वाभाविक सी बात है, भविष्य में कोई भी समझौता भारत के व्यापक हितों को प्रतिबिंबित करने वाला होना चाहिए। परंतु उन हितों को पहले की तुलना में और अधिक व्यापक ढंग से परिभाषित करना जरूरी है। अमेरिका जैसे बड़े उपभोक्ता बाजारों के साथ व्यापारिक संबंधों के महत्त्व को कम करके नहीं आंकना चाहिए और विदेशी प्रतिस्पर्धा से भारत के उत्पादकों, खासतौर पर कृषि के क्षेत्र में होने वाले खतरे को भी बढ़ाचढ़ा कर नहीं बताना चाहिए।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बुनियादी चुनौती है उत्पादकता और प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाना। केवल तभी वेतन और रोजगार भी टिकाऊ ढंग से और निरंतर बढ़ सकेंगे। हाल के वर्षों में एक किस्म की निराशा का माहौल रहा है जिसके तहत यह माना जा रहा है कि भारत की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धी क्षमता कभी उत्तर-पूर्वी एशिया या दक्षिण-पूर्व एशिया के स्तर पर नहीं पहुंचेगी। इस निराशा को जड़ नहीं पकड़ने देना चाहिए। इसका कोई तार्किक आधार नहीं है। वास्तव में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए व्यापार में खुलापन लाना और प्रतिस्पर्धात्मक अनुशासन जरूरी है।

ट्रंप की आक्रामक और टकराव भरी बातचीत की शैली को लेकर निराशा का भाव स्वाभाविक है लेकिन इसे भारत की अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी जरूरतों के लिए व्यापक नकारात्मकता की वजह नहीं बनना चाहिए। भारत को अमेरिका के साथ व्यापक समझौते की तलाश जारी रखनी चाहिए। इसके साथ ही यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते को भी अंतिम रूप देने की जरूरत है। यह अब ट्रंप के शुल्कों के बाद पहले से भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है। भारत को उन बड़े व्यापार समझौतों पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए जिनका वह संभावित हिस्सा बन सकता है। उदाहरण के लिए व्यापक एवं प्रगतिशील प्रशांत पार साझेदारी समझौता यानी सीपीटीपीपी। एक तरह से देखें तो अमेरिका के बाजार के लिए भारत को अपने सभी प्रमुख प्रतिस्पर्धियों (चीन के अलावा) की तुलना में अधिक शुल्क दर का सामना करना अच्छी बात नहीं है। भारतीय कूटनीति को इस हालत से निपटने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। परंतु वास्तव में सबसे खराब तो यह होगा कि भारत इन झटकों के उत्तर में व्यापार वार्ताओं से ही विमुख हो जाए।

ट्रंप की कूटनीति से बचने में आड़े आते विरोधाभास

देश को अमेरिका के राष्ट्रपति की कूटनीति से बचाने के लिए हमें अपने सत्ता प्रतिष्ठान के भीतर विरोधाभासों का करना होगा अवलोकन

डॉनल्ड ट्रंप का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना इन दिनों चलन में है। भारत में हम भी अपने स्तर पर ऐसा कर रहे हैं। बहरहाल हमें उन्हें दो साल तक और झेलने का तरीका तलाश करना होगा। किसी के पास ऐसी कोई दवा या इलाज नहीं है जिससे उन्हें 'ठीक' किया जा सके। भारत को ऐसे तरीके तलाश करने होंगे जिससे वह खुद को ट्रंप के अतार्किक कदमों से बचा सके।

खुद को सोशल मीडिया पर ट्रंप की कूटनीति से बचाने के लिए सबसे पहले हमें अपने सत्ता प्रतिष्ठान से संबंधित बहस में मौजूद विरोधाभासों पर नजर डालनी होगी। वहां प्रतिष्ठान से तात्पर्य केवल मोदी सरकार से नहीं बल्कि जनमत में उनका समर्थन करने वालों से भी है। इनमें सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन पैनलिस्ट और अखबारों में संपादकीय और विचार लेख लिखने वाले भी शामिल हैं।

हम इसकी शुरुआत 2014 में मोदी के उभार से कर सकते हैं। यही वह समय था जब हमारी व्यवस्था ने 30 साल के लंबे इंतजार का जश्न मनाया था। यह जश्न एक ऐसे मजबूत नेता के आगमन का था जो भारत की सामरिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक ताकत को पूर्णता दे सके। संक्षेप में कहें तो एक व्यापक राष्ट्रीय शक्ति। पहली चेतावनी हमें शी चिनफिंग की ओर से मिली जब चीन के सैनिक ठीक उसी समय दक्षिण लद्दाख के चुमार क्षेत्र में घुस आए जब मोदी अहमदाबाद में उनकी खातिरदारी कर रहे थे। समय के साथ चीन की सेना का रुख और बिगड़ता गया। हालांकि चीन को लेकर भारत दीर्घकालिक नजरिया रखता है।

कुल मिलाकर माहौल उत्साहवर्धक था। नई दुनिया में भारत का आगमन हो चुका था। जिसे वह बहुध्रुवीयता और बहु गुटबंदी का पाठ पढ़ा रहा था। अगर एक पश्चिमी सामरिक विद्वान भारत को एक ऐसा ताकतवर देश बताता जिसकी दिशा बदलती रहती है तो कुछ इस प्रकार की प्रतिक्रिया आतीः अरे समझदारी बरतिए, आप तुर्की या ब्राजील की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक महाशक्ति बन चुके हैं। या बनने वाले हैं। वर्ष 2023 में इसका चरम आया जब जी 20 की बैठक हुई थी। अब तक भारत दुनिया भर में चर्चा का विषय बन चुका था। हम जल्दी ही दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले थे, हम क्वाड के केंद्र में थे बल्कि और भी अधिक महत्त्वपूर्ण थे क्योंकि हम किसी संधि से बंधे नहीं थे। हम उन चार देशों में शामिल थे जो चीन से निगाहें मिलाकर खड़े हो सकते थे। हमने अपनी 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा पर उसके हजारों सैनिकों को व्यस्त कर रखा था।

राष्ट्र की बात
शेखर गुप्ता

आखिरकार भारत अपने कद के मुताबिक काम कर रहा था। भारत मंडपम में जी20 देशों के प्रमुखों का आगमन और मोदी के साथ उनका हाथ मिलाना और गले मिलना दुनिया ने देखा। भारत दुनिया को खासकर, पश्चिम को उपदेश दे रहा था। यूरोप खासतौर पर निशाने पर था। आंशिक रूप से रूस के साथ हमारे संबंधों की रक्षा के लिए लेकिन इसलिए भी क्योंकि उसने अपने समर्थकों के साथ बहुत अच्छा तालमेल रखा। ये सारी बातें सत्ता प्रतिष्ठान की बहस की बहुध्रुवीयता में पहले ध्रुव का निर्माण करती हैं। दूसरा ध्रुव तब उभरता है जब जी 20 शिखर बैठक के समय अमेरिका, कनाडा और कुछ हद तक ब्रिटेन के साथ रिश्तों में खटास उभरती है। निज्जर-पन्नू के मसले की छाया भी पड़ती है लेकिन ट्रूडे के कनाडा को छोड़कर कोई और देश सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहता। पहला स्पष्ट झटका तब लगा जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को जनवरी में क्वाड की बैठक और गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए भारत बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। फ्रांस ने हमें शर्मिंदा होने से बचाया।

इस समय तक, हमारी द्विध्रुवीयता स्पष्ट हो चुकी थी और लगातार बढ़ रही थी। इन सभी कार्रवाइयों को जानबूझकर शत्रुतापूर्ण कार्रवाई माना गया। एक दशक तक यह विश्वास बना रहा कि पश्चिमी देश भारत को एक महत्त्वपूर्ण और अपरिहार्य रणनीतिक सहयोगी के रूप में देखते हैं। यहां तक कि चीन के साथ संकट के दौरान उत्तर-पश्चिमी और पूर्वी दोनों क्षेत्रों में, अमेरिका की मदद को लेकर भी एक शांत स्वीकृति देखने को मिली थी।

अब पश्चिम खिलाफ हो चुका था। उसे आत्मनिर्भर भारत का उभार बरदाश्त नहीं था। वह हमारी जड़ों को खोदना और शाखाओं को छांटना चाहता था ताकि हमारा कद बौना रह जाए। एक दशक तक खुद को अपरिहार्य, अनिवार्य, स्वाभाविक सहयोगी मानने के बाद, इस प्रतिष्ठान का एक बड़ा हिस्सा इंदिरा युग की चुभन की ओर लौट रहा था। रूसी तेल खरीद को भी रणनीतिक स्वायत्तता के प्रतीक के रूप में पेश किया गया जबकि वास्तव में यह प्रतिबंधों के कारण किफायती कीमतों के दायरे में की गई खरीद थी। चतुर कूटनीति के तहत इसे चुपचाप अंजाम देना चाहिए था।

सच कहें तो, पश्चिम को ठेंगा दिखाने और उसकी अवज्ञा करने का दावा हमारे राजनयिकों या राजनेताओं की तरफ से नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के व्यापक तंत्र की तरफ से आया। यह कुछ-कुछ ऐसा था कि देखो, हम भी चीन की तरह उनका मुकाबला कर सकते हैं।

गत वर्ष तकरीबन इसी समय पहले के उत्साह का स्थान पीड़ा ने लेना शुरू कर दिया था। शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के लिए अमेरिका, उदारवादी संस्थानों और 'दुष्ट' क्लिंटन-ओबामा डीप स्टेट को दोषी ठहराया गया। उन्होंने यकीनन उन ताकतों की मदद की जिन्हें वे लोकतांत्रिक मानते थे। वैसे ही जैसे अरब उभार में किया गया था लेकिन इस बार भागीदारी काफी कम थी। इन बातों ने मोदी सरकार को और अधिक नाराज किया क्योंकि यह घटना तकरीबन उसी समय हुई जब भारत के चुनाव नतीजे आए थे और उनका गठबंधन 240 सीटों पर रुक गया था। ऐसा लगा मानो दुनिया दोबारा उनको कमजोर करने की कोशिश में लग गई है।

यह हमें दो तरह से नुकसान पहुंचाता है। पहला, 1998 के बाद के 25 सालों में अमेरिका के साथ रिश्तों में जो निवेश किया गया था, वह बेकार हो गया। दूसरा, हम बहुत नाराज हो गए, बहुत अधिक पीड़ित महसूस करने लगे और यह पूछ ही नहीं सके कि हमारी कूटनीति और हमारी खुफिया प्रणाली कैसे पराजित हो गई। भारत ने बांग्लादेश में काफी कुछ निवेश किया है और वह केवल कारोबार, बिजली या सीमा से जुड़े मसलों के निपटान तक सीमित नहीं है। भारत सालाना 20 लाख बांग्लादेशी नागरिकों को वीजा जारी कर रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि हसीना इतनी अलोकप्रिय हो चुकी हैं। अंदर ही अंदर एक तूफान पल रहा था। तथ्य यह है कि पश्चिम ने ढाका में हमें पछाड़ दिया। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों अमेरिका से हमसे बेहतर ढंग से निपटे। यह तब जब हम प्रवासियों के उभार का जश्न मना रहे थे, भारतीय मूल के शीर्ष सीईओ अमेरिकी राजनीति में उभरते भारतीय मूल के लोगों की गणना करते हुए खुश थे। ये हस्तियां हमारी पैरोकार बनें इसके लिए हमारी कूटनीति को उनको अपने साथ जोड़ना था, लेकिन हम विफल रहे। इसका नतीजा यह हुआ कि हम एक ठुकराए गए प्रेमी की भूमिका में आ गए। इस पूरी कहानी में अमेरिका एक महाशक्ति है जो शत्रु की भूमिका में है और हमें उससे अपने दम पर लड़ना है। पाकिस्तान एक शत्रु है, चीन उसका इस्तेमाल हमारे विरुद्ध करता है और रूस कमजोर पड़ चुका है।

हर कोई हमारे विरुद्ध है। अल्लामा इकबाल ने भी लिखा है, 'सदियों रहा है दुश्मन, दौर-ए-जहां हमारा।' हम अकेले लड़ेंगे। हम पहले भी ऐसा कर चुके हैं। हम बहुत देशभक्त देश हैं। स्वदेशी जागरण मंच पहले ही कह चुका है कि हम लड़ाई को तैयार हैं। ट्रंप को क्या पता?

यह हमारी द्विध्रुवीयता का दूसरा, प्रमुख पहलू है। अफसोस की बात यह है कि हम नई वास्तविकता का आकलन किए बिना और उसके अनुसार प्रतिक्रिया दिए बिना ही इसमें पीछे की ओर कूद पड़े हैं। उदाहरण के लिए, मध्यस्थता का मुद्दा। सरकार इसे आसानी से स्वीकार करके संभाल सकती थी कि 1987 के बाद किसी भी भारत-पाकिस्तान संकट में, विदेशी शक्तियों ने पाकिस्तान पर दबाव डालकर मदद की है। विदेशी भागीदारी हमेशा से रही है, लेकिन शिमला समझौते के बाद, कश्मीर पर मध्यस्थता के लिए कभी नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसके लिए एक बढ़िया शब्द गढ़ा थाः सुविधा।

ट्रंप को झूठा बताने के संकेत देने के बजाय सरकार संसद में ट्रंप का धन्यवाद कर सकती थी कि उन्होंने पाकिस्तान को सदबुद्धि दी।

ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राहुल गांधी ने युद्ध विराम के तत्काल बाद सवाल उठा दिया कि भारत ने मध्यस्थता क्यों स्वीकार कर ली। हम पहले भी लिख चुके हैं कि मोदी सरकार राहुल की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दिए बिना नहीं रह सकती। वे अक्सर सरकार को उसका एजेंडा बदलने को उकसाते हैं। ऐसे में पीछिट होने का भाव प्रबल हुआ। यह तब है जब वास्तविक सत्ता प्रतिष्ठान, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, वाणिज्य मंत्री आदि सभी खामोश हैं। वे समझदारी से ट्रंप की अनदेखी कर रहे हैं और परदे के पीछे बातचीत चल रही है। बहरहाल, इनके समर्थकों के बीच जो धारणा व्याप्त है वह खुद के लिए ही चुनौती खड़ा करने वाली है।

भारत के डेरिवेटिव बाजार का भ्रम

गत माह देश के नियामकों ने एक हाई प्रीक्वेंसी वाली ट्रेडिंग फर्म, जेन स्ट्रीट, को कथित तौर पर बाजार में हेराफेरी करते हुए पकड़ा था। यह एक नियामकीय कामयाबी प्रतीत हो सकती है, लेकिन सच तो यह है कि इसने वर्षों की तेज वृद्धि के बाद भारत के डेरिवेटिव बाजार के मूल में मौजूद गहरी संरचनात्मक खामियों को उजागर कर दिया। एक तो, वायदा और विकल्प यानी एफएंडओ कारोबार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सूचकांक त्रुटिपूर्ण हैं। दूसरा, नीति निर्माताओं का यह दावा पूरी तरह सही नहीं है कि डेरिवेटिव बाजार कुशल मूल्य निर्धारण को सक्षम बनाता है, बाजार में नकदी की स्थिति में सुधार करता है और निवेशकों को जोखिम प्रबंधन की अनुमति देता है। इंडिक्स डेरिवेटिव्स में विशाल मात्रा केवल दो सूचकांकों तक सीमित हैः निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, और कुछ हद तक फिनिफ्टी। आइए दो कारकों पर नजर डालें: सूचकांक संरचना और एफएंडओ बाजार की दक्षता।

असंतुलित सूचकांक

सूचकांक निर्माण को अक्सर एक अजीबोगरीब अभ्यास माना जाता है। इसमें भार, नकदी, मुक्त प्रवाह, क्षेत्रवार प्रतिनिधित्व जैसे कार्यप्रणाली संबंधी मुद्दों पर बहस होती है और फिर सूचकांकों में शेयरों को जोड़ने और हटाने के लिए समय-समय पर इन सबकी समीक्षा शामिल होती है। ऐसे तकनीकी निर्णय ट्रेडिंग और सट्टेबाजी के लिए गौण लग सकते हैं, लेकिन इनके गहरे निहितार्थ होते हैं। इंडेक्स एफएंडओ बाजार पर लगभग काबिज दो सूचकांकों में से, बैंक निफ्टी और भी अधिक विषम है। इसके दो घटक यानी एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक इसके भार का आश्चर्यजनक रूप से 53 फीसदी हिस्सा रखते हैं। सूचकांक के शीर्ष पांच शेयरों का कुल भार 82 फीसदी है।

यदि यह सूचकांक एक ऐसा उत्पाद होता जो केवल बैंकिंग शेयरों की दिशा का संकेत देता, तो यह हानिरहित होता। लेकिन यदि कोई म्युचुअल फंड बैंकिंग क्षेत्र का फंड प्रस्तुत करना चाहता है, तो वह बैंक निफ्टी को मानक सूचकांक के रूप में उपयोग करेगा। समस्या की शुरुआत यहीं से होती है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) चाहता है कि निवेश प्रबंधक मानक सूचकांक को गंभीरता से लें। लेकिन एक ऐसा सूचकांक कितना सार्थक हो सकता है जहां 53 फीसदी भार दो शेयरों में है? यदि एक बैंकिंग क्षेत्र के फंड ने 25-30 शेयरों में निवेश किया है, जिसमें से 10 फीसदी एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को आवंटित हैं, तो ऐसे फंड के लिए मानक सूचकांक कितना सार्थक होगा? इसके विपरीत, क्या एक बैंकिंग फंड को दो शेयरों में 53 फीसदी निवेश करना चाहिए और क्या वे सूचकांक की प्रतिकृति करेंगे?

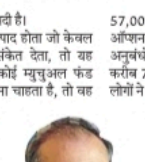

अतार्किक विकल्प
देवाशिष बसु

इससे भी बुरी बात यह है कि सेबी ने नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) को इस अस्थिर सूचकांक पर बैंक निफ्टी वायदा, मासिक विकल्प और फिर भवावह रूप से साप्ताहिक विकल्प लॉन्च करने की अनुमति दे दी। सबसे अधिक नकदीकृत बैंकिंग शेयर एचडीएफसी बैंक है। पिछले गुरुवार को, एक कारोबारी समापन वाले दिन, नकदी बाजार में लगभग 1,900 करोड़ रुपये के शेयरों का कारोबार हुआ। इस बीच केवल 57,000 के एक स्ट्राइक मूल्य पर बैंक निफ्टी कॉल ऑप्शन के कारोबार का कुल आकार 3.98 लाख अनुबंधों का था। इनकी अनुमानित कीमत उस दिन करीब 79,898 करोड़ रुपये थी। जेन स्ट्रीट के चतुर लोगों ने हालात की विचित्रता को भांपा। 12 शेयरों का हानिरहित बैंक निफ्टी सूचकांक साप्ताहिक विकल्प में उनके हाथों का हथियार बन गया। विकल्प में कारोबार बैंक निफ्टी के कम नकदीकृत दिग्गजों की तुलना में 10-12 गुना था। इसका वित्तीय समकक्ष, निफ्टी वित्तीय सेवा सूचकांक (फिननिफ्टी), भी यही कमियां दर्शाता है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का संयुक्त योगदान इसके भारांश में 54.5 फीसदी है। सेबी ने इस सूचकांक पर भी डेरिवेटिव्स की अनुमति दी है, हालांकि यहां साप्ताहिक विकल्प की अनुमति नहीं है।

कुशलता का प्रश्न

बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत का एफएंडओ बाजार कोई वास्तविक उद्देश्य पूरा करता है? वित्त वर्ष 2017-18 (वित्त वर्ष 18) और 24 के बीच, डेरिवेटिव्स का अनुमानित या परिकल्पित कारोबार 1,650 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 80,000 लाख करोड़ रुपये हो गया। भारत अब वैश्विक एक्सचेंज-ट्रेडेड डेरिवेटिव्स कारोबार का आधा हिस्सा रखता है, जिसमें शेयर सूचकांक विकल्प का दबदबा है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत मूल्य निर्धारण, नकदी और हेजिंग के मुक्त बाजार के स्वप्नलोक में पहुंच गया है। यद्यपि यह एक गलत धारणा होगी। इस गतिविधि का बड़ा हिस्सा दो सूचकांकों में केंद्रित है: निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। उनके अस्थिर आकार के पीछे एक कड़वी सच्चाई छिपी है। भले ही एनएसई ने एक दर्जन से अधिक अन्य सूचकांक लॉन्च किए हैं लेकिन उनमें से अधिकांश सक्रिय नहीं हैं।

उन दावों का क्या कि एफएंडओ वॉल्यूम हेजिंग के माध्यम से जोखिम प्रबंधन में मदद करते हैं? म्युचुअल फंड, पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं और व्यक्तिगत निवेशक अपने पोर्टफोलियो का 60-80 फीसदी हिस्सा स्मॉल और मिड-कैप शेयरों में रखते हैं। वे इसे कैसे बचाएंगे? निश्चित रूप से निफ्टी (50 बड़ी कंपनियों से मिलकर) या बैंक निफ्टी (एक क्षेत्रीय सूचकांक) से नहीं। फिर भी स्मॉलकैप 50 या मिडकैप 50 जैसे सूचकांकों के लिए कोई व्यवहार्य विकल्प बाजार नहीं है। डेरिवेटिव ट्रेडिंग में निफ्टी नेक्स्ट 50 भी एक भूतहा शहर जैसा है। यह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि अस्थिर एफएंडओ बाजार में जो कुछ भी होता है उसका नकदी बाजार से कोई लेना-देना नहीं है। मूल्य निर्धारण भ्रामक है। नकदी की स्थिति सतही है। तो हेजिंग यानी जोखिम से बचाव एक सिद्धांत है, व्यवहार नहीं।

आखिर यह स्थिति कैसे बनी? सेबी ने सूचकांक निर्माण में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। इससे विषम मानक के इस्तेमाल की इजाजत मिल गई। इसने एनएसई के सटोरिया प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है। इन उत्पादों को इजाजत देकर नियामक उनके 'उपयोग के मामलों' की निगरानी करने में विफल रहे हैं और इस प्रकार बाजार वाइड पोजिशन लिमिट तय करने और इंट्रा डे ट्रेड निगरानी करने में नाकाम रहा है। कुछ डेरिवेटिव्स में सटोरिया कारोबार गलत स्तर तक बढ़ गया है। जबकि अन्य डेरिवेटिव्स जो अधिक उपयोगी होने चाहिए थे, वे नकदी की कमी से जूझ रहे हैं। जेन स्ट्रीट ने भले ही एक गलत सिस्टम में घोटाला किया हो लेकिन इसका निर्माण उसने नहीं किया है।

आपका पक्ष

अश्लीलता पर अभियोजन को सक्षम बनाना आवश्यक

केंद्र सरकार ने हाल ही में आपत्तिजनक एवं अश्लील कंटेंट प्रसारित करने वाले ओटीटी ऐप्लिकेशन पर लगाम लगाते हुए ऐसे 25 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। यह एक स्वागत योग्य निर्णय है। असल में, हमारे समाज में अश्लीलता पहले कभी इतनी व्यापक नहीं रही जितनी इंटरनेट की वजह से अब है, लेकिन ऑनलाइन अश्लीलता ने नए कानूनी मुद्दे खड़े कर दिए हैं, जिनसे निपटने में अदालतें धीमी रही हैं। अश्लीलता की कानूनी परिभाषा की संकीर्णता और अदालतों द्वारा सफल अभियोजन के रास्ते में खड़ी की गई बाधाओं के कारण, प्रवर्तन एजेंसियां आनलाइन अश्लीलता की विशाल मात्रा पर काबू पाने में असमर्थ रही हैं। रूढ़िवादी क्षेत्रों में मामले बाहर लाने, चार्ज स्टैंकिंग का उपयोग करने, अश्लीलता को कानूनों के तहत एक पूर्वनिर्धारित अपराध के रूप में लाने या यहां तक कि पॉर्नोग्राफी के लिए कॉपीराइट संरक्षण को समाप्त करने के लिए मुकदमे दायर करने जैसी अभियोजन रणनीतियां, अभियोजकों को अश्लीलता के खिलाफ मुकदमा चलाने में अधिक आक्रामक और सफल होने में मदद कर सकती हैं। अश्लीलता के खिलाफ अभियोजन को अधिक सक्षम बनाने के लिए नीति में बदलाव की भी आवश्यकता है। प्रतिबंधात्मक कानूनी उदाहरणों ने अश्लीलता के खिलाफ मजबूत नीति विकल्पों को सीमित कर दिया है। मगर इंटरनेट के लिए कॉमस्टॉक अधिनियम तैयार कर, धारा 230 में सुधार कर, अश्लील सामग्री के लिए कॉपीराइट समाप्त कर और अश्लीलता के खिलाफ कार्रवाई के लिए वर्ग और निजी कारणों की अनुमति देकर हम रास्ता निकाल सकते हैं।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

केंद्र सरकार ने हाल ही में आपत्तिजनक एवं अश्लील कंटेंट प्रसारित करने वाले 25 ओटीटी ऐप्लिकेशन पर प्रतिबंध लगाया है

बिहार में बारिश से नदियां उफनाईं, शहरों में शामत आई

बिहार में लगातार झमाझम बारिश होने से राज्य की कई नदियां उफान पर हैं। बिहार में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने भी बताया है कि दो अगस्त से अब तक बिहार की राजधानी पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, भागलपुर, बांका, भोजपुर, बक्सर, गयाजी, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, मुंगेर, नालंदा और वैशाली समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से शहरी इलाकों में भी लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। रविवार को राज्य की राजधानी पटना में लगातार बारिश के बाद कई प्रमुख सड़कें और कई निचले इलाके जलमग्न हो गए। जानकारों का कहना है कि नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश होने के कारण भी कई स्थानों पर नदियां खतरे के निशान को छू रही हैं या उससे ऊपर बह रही हैं। हर साल बरसात के महीने में बिहार की यही स्थिति हो जाती है। शहर की सड़कों पर पानी जमा हो जाता है और ग्रामीण इलाकों में नदी किनारे रहने वाले लोगों के सामने तौर-ठिकाने की दिक्कतें आनी लगती हैं। सरकार इस पर करोड़ों रुपये खर्च करती है मगर नतीजा सिफर ही रहता है। आमलोगों को भी इसके लिए जागरूक होना होगा।

पुल्कित शर्मा, पटना

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। हालांकि, बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

पायनियर
नई दिल्ली, सोमवार, 4 अगस्त, 2025

ट्रंप ने बढ़ाया टैरिफ

निर्यातों पर ध्यान दे भारत

जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे विश्व व्यवस्था में उथल-पुथल मच गई है। कोई नहीं जानता कि ये फैसले अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उबारने में कितने कारगर होंगे, लेकिन इन फैसलों ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं को तहस-नहस कर दिया है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि अमेरिका अब देशों को अपने टैरिफ कम किए बिना मौजूदा दरों पर अपने माल का निर्यात करने की अनुमति नहीं देगा, लेकिन टैरिफ की मात्रा बहुत ज्यादा है और बदले की भावना और लापरवाह नीतिगत फैसलों की बू आती है।

भारत ने हमेशा अमेरिका को एक विश्वसनीय व्यापारिक साझेदार माना है, लेकिन जब भारत पर टैरिफ लगाने की बात आई, तो ट्रंप ने कोई नरमी नहीं दिखाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की, साथ ही भारत के रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में व्यापार जारी रखने पर अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका विकास पर प्रभाव 0.4 प्रतिशत अंक तक पहुँच सकता है।

भारत की जीडीपी वर्तमान में लगभग 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है, ऐसे में ट्रंप के टैरिफ इसे महत्वपूर्ण 6 प्रतिशत की सीमा से नीचे ला सकते हैं। यह कदम विशेष रूप से विघटनकारी है क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जो इसके कुल निर्यात का लगभग 18 प्रतिशत है। भारत अमेरिका को विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ भेजता है, दवाइयों और मशीनरी से लेकर कपड़ा और पेट्रोलियम उत्पादों तक।

इन पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने से अमेरिकी बाजार में भारतीय वस्तुएँ काफी महंगी हो जाएँगी, जिससे निर्यात में अनुमानित 30-33 अरब डॉलर की गिरावट का खतरा है। भारत के निर्यात-संचालित क्षेत्र, जो पहले से ही नाजुक वैश्विक माँग के माहौल से जूझ रहे हैं, अब दोहरी चुनौती का सामना कर रहे हैं इ अमेरिका में प्रतिस्पर्धात्मकता का नुकसान और संभावित निवेशक अनिश्चितता। मामले को और जटिल बना रहे हैं ट्रंप के बयान, जो अमेरिका-भारत आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के इरादे का संकेत देते हैं। हालाँकि, यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अंत नहीं है।

यह मजबूत और लचीली है। अब समय आ गया है कि विविधता लाई जाए और भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जाए। इस झटके के बावजूद, भारत के पास इसके प्रभाव को कम करने के विकल्प मौजूद हैं। सबसे पहले, कूटनीतिक जुड़ाव को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भारत के व्यापार वार्ताकारों को अमेरिका-भारत संबंधों के रणनीतिक महत्व का लाभ उठाते हुए, द्विपक्षीय समाधान के लिए दबाव बनाना होगा। यह पहले से ही क्षितिज पर है, हालांकि अभी तक कोई ठोस उपलब्धि हासिल नहीं हुई है। दूसरा, भारत अपने निर्यात लक्ष्य को यूरोपीय संघ, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका जैसे वैकल्पिक बाजारों की ओर मोड़ सकता है, जहां भारतीय वस्तुओं की माँग बढ़ रही है और टैरिफ मध्यम बने हुए हैं।

तीसरा, घरेलू नीति को इस प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठाने होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के पास ब्याज दरों को और कम करने की गुंजाइश है, निवेश और उपभोग को समर्थन देने के लिए मौद्रिक गुंजाइश मौजूद है। इसके अतिरिक्त, सरकार प्रभावित क्षेत्रों, विशेष रूप से एमएसएमई, के निर्यातकों को लक्षित प्रोत्साहन दे सकती है ताकि उन्हें अपना कारोबार जारी रखने और नए बाजार तलाशने में मदद मिल सके।

अंततः, यह बदलाव भारत के संरचनात्मक सुधारों को गति देने के लिए उत्प्रेरक होना चाहिए - व्यापार रसद में सुधार, अनुपालन लागत में कमी, निर्यात आधार में विविधता लाना, और गुणवत्ता मानकों में निवेश करना जो भारतीय उत्पादों को केवल कीमत से आगे बढ़कर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाते हैं। जैसे-जैसे भारत इस झटके को झेल रहा है, उसे इसे केवल एक कूटनीतिक या व्यापारिक टकराव के रूप में नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखना चाहिए - एक ऐसा मोड़ जो यह दिलाता है कि अस्थिर वैश्विक व्यवस्था में आर्थिक लचीलापन विविधीकरण, आत्मनिर्भरता और चपलता में निहित है।

धनखड़ का अचानक इस्तीफा

सरकार के दबाव की सुगबुगाहट के बीच, जगदीप धनखड़ के जाने से उत्तराधिकार की तीव्र साजिशों का द्वार खुल गया है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में इस पद के लिए विचार किए जाने की संभावना भी शामिल है।

कल्याणी शंकर
लेखिका, वरिष्ठ पत्रकार हैं।

वर्तमान मानसून सत्र के पहले दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने से राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। उनका कार्यकाल 2027 में समाप्त होना था। वे प्रधानमंत्री की प्रत्यक्ष पसंद थे। धनखड़ ने पहले कहा था, रमैं सही समय पर, अगस्त 2027 में, ईश्वरीय कृपा के अधीन, सेवानिवृत्त हो जाऊंगा। लेकिन परिस्थितियों ने इसे पहले ही कर दिया। हालांकि धनखड़ के इस्तीफे का कारण उनका स्वास्थ्य बताया गया था, लेकिन यह स्पष्ट है कि राजनीतिक दबाव सहित अन्य कारकों ने भी उनके इस निर्णय में योगदान दिया।

एक सूत्र ने सुझाव दिया कि न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ विपक्ष द्वारा प्रायोजित महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद सरकार ने उन्हें इस्तीफा देने का निर्देश दिया होगा। न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ विपक्ष द्वारा प्रायोजित महाभियोग प्रस्ताव, जो वर्तमान मानसून सत्र के पहले दिन 21 जुलाई को पेश किया गया था, ने खलबली मचा दी। धनखड़ का इस्तीफा ऐसे समय में हुआ है जब सरकार लोकसभा में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर महाभियोग चलाने के लिए एक विधेयक पर विचार कर रही है, जिससे दिन के तेज और नाटकीय घटनाक्रम और भी बढ़ गए।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे अपने त्यागपत्र में धनखड़ ने कहा, स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए, मैं संविधान के अनुच्छेद 67(ए) के तहत, तत्काल प्रभाव से, भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया?

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने टिप्पणी की, केवल वही (धनखड़) कारण जानते हैं। हमें इस मामले में कुछ नहीं कहना है। या तो सरकार जानती है, या वह जानते हैं। उनका इस्तीफा स्वीकार करना या न करना सरकार पर निर्भर है। मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि सरकार पहले भी कई कारणों से धनखड़ से नाराज थी। काफी समय से, सरकार धनखड़ द्वारा बिना सलाह-मशविरा किए फैसले लेने से असंतुष्ट थी। भाजपा को उन पर विपक्ष का साथ देने का संदेह होने लगा था, जिसमें न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ हालिया महाभियोग प्रस्ताव भी शामिल है।

अगर बड़ी विपक्ष उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाना चाहता था, तो कोई बात नहीं। न्यायपालिका पर उनका हमला सरकार के लिए भी शर्मिंदगी का कारण बना। धनखड़ ने विपक्षी नेताओं के साथ बैठकें शुरू कर दीं।

कुल मिलाकर, सरकार को लगा कि वह शर्मिंदगी का कारण बन रहे हैं। 21 जुलाई एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम का दिन था। दोपहर 2 बजे, राज्यसभा के सभापति ने विपक्ष द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रात 9:25 बजे तक, धनखड़ ने 11 जुलाई को अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी।

राष्ट्रपति ने 22 जुलाई की आधी रात को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि उपराष्ट्रपति को यह संदेश स्पष्ट रूप से दे दिया गया था कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना... उपराष्ट्रपति के लिए एक तरह की धमकी। धनखड़ अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले इस्तीफा देने वाले पहले उपराष्ट्रपति नहीं हैं; वह वीवी गिरि, बीडी जत्ती, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और केआर नारायणन की श्रेणी में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति चुने जाने के बाद भी इस्तीफा दे दिया था।

राज्यपाल के रूप में धनखड़ का कार्यकाल विवादों से भरा रहा और अक्सर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनकी झड़पें होती रहीं। लेकिन सरकार ने उन पर कोई अंकुश नहीं लगाया। मोदी ने उन्हें 2022 में उपराष्ट्रपति नियुक्त किया था, लेकिन अब लगभग तीन साल बाद उन्हें चुपचाप अपना पद छोड़ना पड़ा है। आम तौर पर ऐसा होता है कि सदन से उनके जाने पर विदाई भाषण नहीं दिए गए।

अपने पूरे कार्यकाल के दौरान, खासकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में, धनखड़ का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ विवादास्पद संबंध रहा। हालांकि, जब एनडीए ने उन्हें संवैधानिक पद के लिए चुना, तो ममता बनर्जी ने उनकी नियुक्ति का विरोध नहीं किया। सत्ता पक्ष तब अचंभित रह गया जब उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा में कहा, श्माननीय सदस्यों, मुझे आपको सूचित करना है कि मुझे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के लिए एक वैधानिक समिति गठित करने हेतु प्रस्ताव का नोटिस प्राप्त हुआ है। इस पर 50 से अधिक विपक्षी सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, जो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक संख्या की आवश्यकता को पूरा करता है। लोकसभा में सत्ता पक्ष से परामर्श किए बिना इस विषय को स्वीकार करने के धनखड़ के कदम से सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी।

सरकार को उपराष्ट्रपति का यह कदम पसंद नहीं आया, जबकि सरकार लोकसभा में आम सहमति बनाने की कोशिश कर रही थी। इससे विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर सवाल उठे।

उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह पद सौंप सकती है, जिससे स्थिति में राजनीतिक साजिश का एक नया आयाम जुड़ जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने हैं। धनखड़ के इस्तीफे के कारणों के बावजूद, उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जल्द ही होंगे, और चुनाव आयोग ने पहले ही इसकी सूचना दे दी है।

इससे एक बार फिर सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। कई प्रमुख नाम पहले ही सुझाए जा चुके हैं, जिनमें मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हैं।

यह भी संभावना है कि भाजपा के किसी करीबी उम्मीदवार को ही इस पद पर नियुक्त किया जाएगा। धनखड़ हाल ही में हुए इन बदलावों से नाराज हो सकते हैं, जो अप्रत्याशित रूप से हुए हैं। वे राजनीतिक उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और काफी महत्वाकांक्षी हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे नेताओं को पसंद करते हैं जो कम चर्चा में रहते हैं।

राज्यपाल के रूप में धनखड़ का कार्यकाल विवादों से भरा रहा और अक्सर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनकी झड़पें होती रहीं। लेकिन सरकार ने उन पर कोई अंकुश नहीं लगाया। मोदी ने उन्हें 2022 में उपराष्ट्रपति नियुक्त किया था, लेकिन अब लगभग तीन साल बाद उन्हें चुपचाप अपना पद छोड़ना पड़ा है। आम तौर पर ऐसा होता है कि सदन से उनके जाने पर विदाई भाषण नहीं दिए गए।

उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लगभग एक महीने में होने की उम्मीद है। एनडीए अपने उम्मीदवार के चयन को गोपनीय रख रहा है। यह अभी भी अनिश्चित है कि अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से होगा या विपक्ष कोई उम्मीदवार उतारेगा। स्थिति जल्द ही स्पष्ट हो जाएगी।

भारत अब पहले जैसा नहीं रहा!

ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के प्रति धारणा को हमेशा के लिए बदल दिया है, और यह अब वैसा नहीं रहेगा जैसा आजादी के बाद से था। गलवान घाटी में हुई झड़प इस रुख में बदलाव की शुरूआत थी।

बंशीधर रुखड़बार
लेखक, राजनीतिक टिप्पणीकार हैं।

ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के प्रति धारणा को हमेशा के लिए बदल दिया है, और यह अब वैसा नहीं रहेगा जैसा आजादी के बाद से था। गलवान घाटी में हुई झड़प इस रुख में बदलाव की शुरूआत थी, जब उसने अपने दुर्जेय दुश्मन चीन से सीधा मुकाबला किया।

पूरी दुनिया उसके धैर्य, दृढ़ संकल्प और लचीलेपन के साथ-साथ इस लंबे, दर्दनाक और तनावपूर्ण गतिरोध की कीमत चुकाने की उसकी आर्थिक क्षमता से अचंभित रह गई।

ऑपरेशन सिंदूर एक तार्किक कदम था क्योंकि इसने पहलगाम नरसंहार के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया और एक डोजियर तैयार करके उसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ले जाने के बजाय, अकेले ही कार्रवाई की - वह भी यह पूर्व चेतावनी देने के बाद कि इस अपराध के दोषियों को न केवल पर्याप्त सजा दी जाएगी, बल्कि उन्हें ऐसा कड़ा सबक भी सिखाया जाएगा जिसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकेगा।

भारत आतंक और पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी दंडात्मक कार्रवाई इसलिए कर सका क्योंकि उसने पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी ढांचे को पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी राष्ट्र का ही विस्तार मान लिया था।

दूसरे, उसने पाकिस्तान के परमाणु हमले का सामना करने का फैसला किया, जिसे अमेरिका और पश्चिमी देशों का भरपूर समर्थन प्राप्त था। यह आतंक के खिलाफ एक सक्रिय कार्रवाई थी। पाकिस्तान से संचालित आतंकवादी ढाँचे को तहस-नहस कर दिया गया, और जब पाकिस्तानी वायु सेना ने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की, तो उसे पूरी तरह से निष्प्रभावी कर दिया गया, और कई पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला करके उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया।

पाकिस्तान के पास इलाज होकर युद्धविराम की माँग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, जो तब हुआ जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से इसका अनुरोध किया। यह युद्धविराम बिना किसी उचित युद्ध घोषणा के हुआ। भारत इसके लिए सहमत हुआ क्योंकि इसने पाकिस्तान में आतंकवादी ढाँचे को ध्वस्त करने के अपने घोषित उद्देश्य को प्राप्त कर लिया, साथ ही यह कड़ा संदेश भी दिया कि उसे आतंकवाद को प्रायोजित करने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

भारत कभी भी पूर्ण युद्ध नहीं चाहता था और उसने पाकिस्तान से कहा कि वह इसे और न बढ़ाए, क्योंकि भारत का एकमात्र उद्देश्य आतंकवादियों को दंडित करना और उनके ठिकानों और प्रशिक्षण शिविरों को नष्ट करना था। इसने पाकिस्तान को एक सबक भी सिखाया - कि भारत उन पर हमला कर सकता है और उन्हें बिना किसी दंड के, जब भी आवश्यकता हो, दंडित कर सकता है। यह अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए एक संदेश था कि भारत विश्व जनमत की परवाह किए बिना अपने दम पर कार्रवाई करने और अपने दुश्मन को दंडित करने में सक्षम है।

भारत वैश्विक मंच पर एक बड़े राष्ट्र के रूप में उभरा है जो अपनी इच्छानुसार अपने दुश्मन पर प्रहार करने में सक्षम है। अमेरिका और पश्चिमी देश पाकिस्तान की इस अपमान से नहीं बचा सके क्योंकि हमारी सभी संचार संरचनाएं और वायु रक्षा निगरानी प्रणालियां या तो स्वदेशी थीं या रूसी। हमारी स्वदेशी तकनीक और मिसाइल प्रणाली ने पाकिस्तानी रक्षा और निगरानी प्रणालियों को, जो अधिकांशतः चीनी और अमेरिकी थीं, मात दे दी। इसने इन प्रणालियों की अभेद्यता के मिथक को ध्वस्त कर दिया, और इसका अंतर्राष्ट्रीय हथियार बाजार पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। भारत निर्मित हथियारों और अन्य रक्षा उपकरणों की बढ़ती माँग इसका प्रमाण है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की क्षमता और कार्य करने की इच्छाशक्ति का प्रकटीकरण है। यह हमारी विदेश नीति में एक आदर्श बदलाव है।

इसके अपने परिणाम होंगे। अमेरिका और पश्चिमी देश भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को स्वीकार नहीं करेंगे जैसा कि वे करते हैं। वे पाकिस्तान का समर्थन करने और उसे भारत के शक्ति और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के विरुद्ध एक ढाल के रूप में क्रियाशील बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे। वे आपके मजबूत नेतृत्व की कमजोर करने की हर संभव कोशिश करेंगे।

ये वस्तुतः कांच की छत तोड़ने की कोशिशें हैं। भारत एक प्रकार से अपने ही परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, और जैसे-जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं, आपका अलगाव पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट होता जाता है।

वैश्विक सहानुभूति उन लोगों के लिए है जो वैश्विक आकाओं के हाथों के औजार हैं। यह उन लोगों के लिए है जो कमजोर और पराजित हैं। भारत को पहले से कहीं ज्यादा सावधानी और दृढ़ता से अपना रास्ता तय करना होगा। उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी - और वह भी चुपचाप।

आप की बात

बढ़े सर्किल रेट, वाच एंड वेट

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नए सर्कल रेट में बढ़ोतरी करके प्रदेश में खत्तासीन सैनी सरकार ने हरियाणा में आर्थिक हलचल शुरू कर दी है। निश्चित रूप से सरकार को धन की आवश्यकता है। उसी के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। इस बार सर्कल रेट में 20 से 50 फीसदी तक की बढ़ोतरी करके सरकारी खजाने में राजस्व कमाई में वृद्धि होने के लिए आवश्यक मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इस प्रस्ताव से हरियाणा के प्रमुख शहरों फरीदाबाद, गुरुग्राम , सोनीपत आदि सभी जिलों के पॉश सेक्टरों में प्लॉट / मकान का क्रय विक्रय करना महंगा हो जाएगा। ग्राहकों को नंबर -2 में लेनदेन के लिए फंड की व्यवस्था आयकर चोरी से बचने के लिए करनी पड़ती है" नायब सिंह सैनी सरकार के इस झटके से प्रॉपर्टी डीलर ज्ञ्ज और फरेब का सहारा लेकर अपनी कमीशन की कमाई तो निकाल कर ही रहेंगे। इसलिए क्रेता विक्रेता को चाहिए कि वे कई जगह से प्रॉपर्टी की कीमतों का समय रहते मूल्यांकन अवश्य करा लें। मार्केट में वास्तु के नाम पर बड़े बड़े सब्जबाग दिखाने वाले सक्रिय हैं" हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम की कार्यशैली से जन समस्याओं के निवारण में वाच एन्ड वेट चल रहा है।

– **युगल किशोर शर्मा** , फरीदाबाद

उपभोक्ताओं के साथ ज्यादती

लोगों की जितनी निर्भरता मोबाइल फोन पर होती जा रही है कंपनियां उपभोक्ताओं को अपने हिसाब से सुविधाओं में कटौती करती ही रही हैं। बिलकुल वैसा ही है जैसे किसी समय हर जगह अमिताभ बच्चन की आवाज गूंजती थी– "दो गज दूरी, मास्क है जरूरी!" तब वह आवाज चेतावनी कम, प्रचार अधिक लगने लगी थी। इस समय ठीक उसी तरह मोबाइल या इंटरनेट बेलेंस खत्म होने के दो-तीन दिन पहले से ही आने वाली बार-बार की सूचना भी अब उपभोगिता की बजाय लोगों में खीझ पैदा करने का कारण बनती जा रही है। हर बार कॉल या मैसेज के बीच बेलेंस संबंधी चेतावनियां आने लती हैं, जो सेवा के नाम पर की जाती हैं। ये प्रवृत्तियां वास्तव में एक अनचाहा हस्तक्षेप बन चुकी हैं।कृत्रिम दबाव बनाकर उपभोक्ता को रिचार्ज करने के लिए मजबूर करने की यह कंपनियों की एक सोची-समझी रणनीति हो सकती है। परंतु यह ग्राहक की स्वतंत्रता में दखल है। जिस तरह पब्लिक स्पेस में जोर-जबरदस्ती का प्रचार हटाया गया, वैसे ही यह डिजिटल उत्पीड़न भी बंद किया जाना चाहिए। सरकार और दूरसंचार नियामक प्राधिकरण -ट्राई को चाहिए कि ऐसे प्रावधान करे कि जिनसे अंतर्गत ग्राहक को विकल्प दिया जाए कि वह इन चेतावनियों को बंद कर सके। सेवा ही नहीं, सुविधा और सम्मान जरूरी है।

– **अमृतलाल मारू 'रवि'**, इंदौर, मप्र

अब ठान ले भारत

भारत ने समय समय पर विश्व के अनेक दंभी चरित्रों का दंभ तोड़ा है। यदि भारत वासी सच्चे मन से ठान लें कि स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना है, तो भारत में अनेक समस्याओं का स्वतः समाधान हो सकता। भारत की विश्व स्तर पर बढ़ती स्वीकार्यता एवं लोकप्रियता के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति का दर्द समझा जा सकता है। भारतीय उत्पादों पर पच्चीस प्रतिशत टैरिफ वसूलने तथा अन्य देशों से तेल खरीदने पर जुर्माना लगाने का ट्रम्प का आदेश अमेरिकी राष्ट्रपति की नीयत पर सवाल उठाता है। आश्चर्य तो तब होता है कि जब भारत के प्रमुख विपक्षी दल ट्रम्प के सुर में सुर मिलाकर अपनी ही सरकार को घेरने का दुस्साहस करते हैं, जैसे उन्हें अपने देश की विदेश नीति तथा देश के स्वाभिमान से कोई सरोकार न हो। अढ़ाकाल भारतीय लोकतंत्र शुरुह है। अन्य देशों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था संतुलित है। सच यही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख बढ़ी है तथा भारत के नकारा विपक्ष के क्रियाकलापों को देश नकार चुका है। यदि ऐसा न होता, तो हताश विपक्षी नेता कुछ नेताओं की मृत्यु के उपरांत घटित घटनाक्रमों में अनर्गल आरोप न लगाते। वस्तुस्थिति यह भी है कि भले ही विदेशी शक्तियाँ अपनी प्रभुसत्तावादी नीतियों के चलते भारत के व्यापार जगत को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास करें, लेकिन भारत मुंहतोड़ उत्तर देने में पीछे नहीं है।

– **सुधाकर आशावादी**, मेरठ

साजिश हुई विफल

मालेगांव विस्फोट का 17 वर्ष बाद जो निर्णय आया उसने विपक्ष द्वारा गढ़े गये "भगवा आतंकवाद" के विमर्श को धराशाई कर दिया। विशेष रूप से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इस विस्फोट के माध्यम हिन्दुओं को भी आतंकवादी सिद्ध कर धर्म विशेष के आतंकवाद से सन्तुलन बनाकर वोट बैंक की जिस राजनीति को परवान चढ़ाने का कुचक्र चला था उसकी हवा निकल गई। सोनिया गांधी, राहुल गांधी,पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह और रा कां पार्टी के शरद पवार ने ए टी एस अधिकारियों और न्यायाधीशों को सत्ता के दबाव में लाकर इनके माध्यम से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और ले कर्नल पुरोहित से भाजपा और आर एस एस के शीर्ष नेताओं के मालेगांव काण्ड में नाम लेने का दबाव बनाया था। इसका खुलासा ए टी एस के तत्कालीन अधिकारी महबूब मुजावर ने डी कर दिया। मुजावर के अनुसार साध्वी प्रज्ञा सिंह को इस कुचक्र में फंसाने के लिए उस बाइक मिसमें पर भी दबाव बनाया गया जिसने साध्वी की बाइक की मरम्मत की थी। इस षड्यंत्र में महबूब द्वारा साथ न दिये जाने पर उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। यही नहीं तत्कालीन ए टी एस उप प्रमुख परमवीर ने महबूब मुजावर को संघ प्रमुख मोहन जी भागवत को भी बन्दी बनाने का आदेश दिया था। किकीलीक्स ने तो एक चौंकाने वाला खुलासा और किया।

– **डॉ नरेंद्र टोंक**, मेरठ

दैनिक जागरण

ऊर्जा का अपव्यय ही अवनति की ओर ले जाता है

थोड़ी तो शर्म करें

चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर जिस तरह यह कहा कि अब तक इस सूची के प्रारूप पर किसी भी दल से कोई आपत्ति नहीं मिली, उससे यही साफ होता है कि विपक्षी दल जानबूझकर इस संवैधानिक संस्था को बदनाम करने के साथ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लज्जा की बात यह है कि यह काम देश पर लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस भी कर रही है। चुनाव आयोग पर उलटे-सीधे आरोप लगाने के मामले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तो सारी हदें पार कर गए हैं। लगता है कि उनकी हताशा कुंठा में बदल गई है। वे लोकसभा में चुनाव आयोग को धमकी देने से भी बाज नहीं आए। उनकी नजरों में आने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता भी बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को चुनाव आयोग को आवश्यक और सुप्रीम कोर्ट को सोर से अनुमोदित पहल पर बेतुके बयान देने में लगे हुए हैं। इसमें नया नाम जुड़ा है पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम का। उन्होंने पहलगाम हमले पर बेतुका बयान देकर कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस और अपनी फजीहत कराई है। अब वे नए सिरे से अपनी फजीहत करा रहे हैं। उन्होंने बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर यह कह दिया कि चुनाव आयोग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है और इसका कानूनी तरीके से भी मुकाबला किया जाना चाहिए। आखिर उन्हें या अन्य विपक्षी नेताओं को चुनाव आयोग की कथित अनावश्यक एवं लोकतंत्र विरोधी पहल के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने से रोका किसने है? क्या वे वही लोग नहीं जो सुप्रीम कोर्ट गए थे और वहां उन्होंने मुंह की खाई?

अब इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि विपक्षी दल लोकतंत्र बचाने का नाटक करके लोकतंत्र की ही जड़ें खोदने का काम कर रहे हैं। उन्हें न तो एक संवैधानिक संस्था को बदनाम करने में शर्म आ रही है और न ही वे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर ध्यान देना पसंद कर रहे हैं। विपक्षी दलों का रवैया चुनाव आयोग के साथ सुप्रीम कोर्ट का अनादर करने और संसद के भीतर-बाहर इस मुद्दे को तूल देकर चर्चा में बने रहने वाला है। क्या देश की औसत जनता इतनी नासमझ है कि उनकी सस्ती राजनीति और चालबाजी को न समझ पा रही हो? इसका पता तो बिहार के आगामी विधानसभा चुनावों के बाद ही चलेगा कि विपक्ष को मतदाता सूची के सत्यापन पर बेवजह आसमान सिर पर उठाने से क्या हासिल हुआ, लेकिन इतना तो है ही कि कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों के नेता मतदाता सूचियों को सही करने के चुनाव आयोग के एक जरूरी काम पर बहुत ही भद्दी और एक तरह से आम मतदाताओं के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली हरकत कर रहे हैं। विडंबना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक चुनाव आयोग के साथ खुलकर खड़े होना आवश्यक नहीं समझा।

जरूरी पहल

प्राथमिक के साथ उच्च शिक्षा को बेहतरी के लिए बिहार सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं। विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी चल रही है। सभी जिलों में मेडिकल कालेज खोलने की सरकार ने घोषणा की है। कई जिलों में यह प्रक्रियाधीन है। प्रदेश के इंजीनियरिंग कालेज से शिक्षा ग्रहण करने वालों को उचित नियोजन मिले, इसको लेकर अभिभावक और छात्र चिंतित रहते हैं। इस पर गंभीरता दिखाते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के सभी सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालयों और पालिटेक्निक संस्थानों में छात्र-छात्राओं के नियोजन के बारे में न केवल जानकारी दी जाएगी, बल्कि तकनीकी शिक्षा पूरी करने वाले छात्र-छात्राओं को रोजगार दिलाने के लिए अभियान भी चलाया जाएगा। इसके मद्देनजर मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र-छात्राओं के लिए पूल कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव चलाया जाएगा। इस दौरान एक अभियान के तहत एक ही जगह पर कई संस्थानों के छात्र-छात्राओं के लिए नियोजन कार्यक्रम आयोजित कर रोजगार दिलाया जाएगा। इसमें मल्टीनेशनल कंपनियां भी भाग लेंगी। अच्छी बात है कि इस अभियान के लिए कंपनी की ओर से ई-मेल के माध्यम से लिखित परीक्षा में भाग लेने के लिए कुल 121 छात्र-छात्राओं का चयन किया गया है। राज्य के सरकारी इंजीनियरिंग कालेज के छात्रों को कोर्स पूरा करने के बाद यदि बेहतर नियोजन मिलेगा तो उन्हें दूसरे राज्यों के कालेजों में नामांकन के लिए नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही, तकनीकी शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों का रुझान भी बढ़ेगा।

तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को बेहतर नियोजन दिलाने का सरकार का प्रयास सराहनीय है

मतदाता सूचियों में घुसपैठ

शिवकांत शर्मा

घुसपैठियों द्वारा मतदान के जरिये जनादेश को प्रभावित करना चुनाव प्रक्रिया में विदेशी हस्तक्षेप जैसा है। वे तमाम योजनाओं का बेजा लाभ भी उठाते हैं

आरेखन साभार

जनतंत्र में जनता चुनावों के जरिये जनादेश देती है। इसलिए चुनाव जनतंत्र की आधारशिला हैं और चुनावों की विश्वसनीयता यह सुनिश्चित करने पर निर्भर करती है कि मतदान में वही लोग भाग लें जो उसकी अर्हता रखते हों। मतदाताओं की अर्हता लगभग हर लोकतांत्रिक देश में मतदाताओं की आयु, नागरिकता और जिस क्षेत्र का चुनाव हो रहा हो, वहां निवास के प्रमाण के आधार पर तय की जाती है और मतदाता सूचियां बनाई जाती हैं। पुनरीक्षण से इन्हें निरंतर अद्यतन रखने के मामले में आस्ट्रेलिया, कनाडा और जर्मनी को विश्व में आदर्श माना जाता है। आस्ट्रेलिया और कनाडा में मतदाता पंजीकरण और मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का काम भारत के चुनाव आयोग की तरह केंद्रीय एजेंसियां करती हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में इसका दायित्व स्थानीय प्रशासन के पास है जो केंद्र सरकारों के निर्देशों के आधार पर उसे निभाते हैं। आस्ट्रेलिया और इटली में मतदान के लिए पंजीकरण कराना और मतदान करना अनिवार्य भी है।

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की बात करें तो निर्वाचन आयोग के अनुसार पिछले साल तक मतदाता सूची में कुल 96.88 करोड़ लोगों के नाम थे। जबकि देश में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों की जनसंख्या केवल 91 करोड़ के आसपास थी। आंकड़ों की इस विसंगति के तीन प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला, पिछले 15 वर्षों से जनगणना न होने के कारण जनसंख्या का अनुमान सही न होना। दूसरा, मतदाता सूचियों में ऐसे लोगों के नाम शामिल होना जिनका निधन हो चुका है। तीसरा, अयोग्य, फर्जी और घुसपैठियों का शामिल होना। उन्हीं के निवारण के लिए चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का काम शुरू किया है, जिसके समय को लेकर आइएनडीआइए के दल मुखर विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वालों का एक तर्क यह है कि नागरिकता का सत्यापन करना गृह मंत्रालय का काम है, चुनाव आयोग का नहीं। हालांकि नागरिकता के सत्यापन के बिना मतदान करने की अर्हता तय नहीं हो सकती और उसे तय किए बिना सही मतदाता सूची नहीं बन सकती। मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का काम चुनाव एजेंसियों का ही है, इसलिए नागरिकता का प्रमाण मांगे बिना वे पारदर्शी मतदाता सूची कैसे तैयार कर पाएंगे? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, आस्ट्रेलिया और कनाडा से लेकर जापान तक हर देश की मतदाता सूची में शामिल होने के लिए नागरिकता का प्रमाण अनिवार्य है। घुसपैठियों द्वारा मतदान के जरिये जनादेश को प्रभावित करना चुनाव प्रक्रिया में विदेशी हस्तक्षेप जैसा ही है। इसलिए बिहार में मतदाता सूची की पुनरीक्षा को चुनौती देने वालों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का कूद पड़ना और यह कहना कि 'यदि बड़े पैमाने पर लोगों को इस सूची से बाहर किया गया, तो वह हस्तक्षेप करेगा' हैरत की बात है। कोर्ट को तो निर्वाचन आयोग से यह पूछना चाहिए कि उसने बिहार में 2003 और बंगाल में 2002 से आज तक मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण क्यों नहीं किया?

जिन फर्जी मतदाताओं और घुसपैठियों को मतदाता सूची से निकालने के लिए निर्वाचन आयोग ने पुनरीक्षा का काम शुरू किया है, उन्हें वोट बैंक बनाकर अब वही दल सबसे कड़ा विरोध कर रहे हैं जो इस समस्या को लेकर कभी सबसे मुखर रहे। मसलन, लालू प्रसाद यादव ने सितंबर 1992 में केंद्र सरकार से कहा था कि वह बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ को रोकने के कारगर उपाय करे। उन्होंने ऐसा कानून बनाने की मांग भी रखी थी जो घुसपैठियों को अचल संपत्ति खरीदने से रोके। सीमावर्ती जिलों में भारतीयों को पहचान पत्र देने की सलाह भी दी थी ताकि घुसपैठियों की पहचान हो सके। इसी तरह 2005 में बंगाल की मतदाता सूचियों में घुसपैठियों की समस्या रेखांकित करने के लिए ममता बनर्जी ने तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को बांग्लादेश और बंगाल के उन दो चुनाव क्षेत्रों की मतदाता सूचियां भेंट की थीं, जिनमें अनेक नाम समान थे।

आस्ट्रेलिया, कनाडा और जर्मनी ने मतदाता सूचियों को अद्यतन रखने के लिए निर्वाचन आयोगों को पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म-मृत्यु पंजीकरण और जनकल्याण जैसी नागरिकों के आंकड़े रखने वाली एजेंसियों से जोड़ रखा है। इसलिए वहां की चुनाव एजेंसियों को अपनी मतदाता सूचियां अद्यतन रखने में कठिनाई नहीं होती। जर्मनी ने अपना पता बदलने पर स्थानीय प्रशासन के दफ्तर में जाकर पंजीकरण कराना अनिवार्य कर रखा है, जिसकी वजह से मतदाता सूची भी अपने आप अद्यतन होती रहती है। ब्रिटेन और फ्रांस में स्थानीय सरकारें डाक और इलेक्ट्रानिक संपर्क के माध्यम से हर साल मतदाता सूची को अद्यतन करती हैं। लोग जब चाहें आनलाइन जाकर भी नाम दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा हर चुनाव से पहले भी इन्हें अद्यतन किया जाता है। स्वीडन, फिनलैंड और नीदरलैंड्स जैसे छोटे यूरोपीय देशों में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर भी हैं, जिससे फर्जी नाम और घुसपैठिए मतदाता सूचियों में जगह नहीं पा सकते। नागरिकता रजिस्टर रखने इसलिए भी जरूरी हैं, ताकि घुसपैठिए मुफ्त स्वस्थ शिक्षा और इलाज, वृद्धावस्था पेंशन और सीमित समय के लिए बेरोजगारी भत्ते आदि का लाभ न उठा सकें। यहां तक कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार जैसे भारत के पड़ोसी देशों ने भी नागरिकता रजिस्टर या पहचान पत्र बना रखे हैं ताकि शरणार्थियों और घुसपैठियों का हिसाब रखा जा सके। क्या ऐसे असफल देशों से घिरे भारत को भी अपनी चुनाव प्रक्रिया को घुसपैठ के प्रभाव से बचाने के लिए नागरिकता रजिस्टर बनाने पर गंभीरता से विचार नहीं करना चाहिए?

भारत अब धीरे-धीरे जनकल्याण सेवाओं का दायरा भी फैला रहा है। नागरिकता रजिस्टर बन जाने से एक तो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग और घुसपैठिए न तो योजनाओं का अनुचित लाभ उठा पाएंगे और न ही जनादेश को भी प्रभावित कर पाएंगे। हालांकि इसके लिए चुनाव आयोग को मतदाता सूचियों के निरंतर और वार्षिक अद्यतनीकरण की व्यवस्था भी शुरू करनी होगी।

(लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं)
response@jagran.com

प्राथमिकता में आए मानसिक स्वास्थ्य

गिरीश्वर मिश्र

स्वास्थ्य सुविधाएं और संपन्नता बढ़ने से आज के समय में आयु तो बढ़ रही, पर आदमी का मन कमजोर होने लगा है

तन के साथ मन की सेहत का ध्यान भी जरूरी। फाइल

स्वस्थ रहना हमारी स्वाभाविक स्थिति होनी चाहिए, पर समकालीन परिवेश में अधिकांश लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पा रहा है। शारीरिक रोगों को तो आसानी से पहचान लिया जाता है, परंतु मानसिक रोगों की पहचान और इलाज के लिए विशेष प्रशिक्षण और अध्ययन की आवश्यकता होती है। मनोचिकित्सा की विषय के रूप में मेडिकल कालेजों में साइकियाट्री के अंतर्गत रखा जाता है। इसी से जुड़े विषय क्लिनिकल साइकोलाजी और काउंसिलिंग भी हैं, जो मनोविज्ञान विषय के अंग हैं। भारत में मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएं जनसंख्या की दृष्टि से बहुत कम और अपर्याप्त हैं। क्लिनिकल साइकोलाजी के अध्ययन की कुछ चुनिंदा संस्थाएं हैं, जहां जरूरी और प्रामाणिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इस दृष्टि से एमए करने के बाद क्लिनिकल साइकोलाजी में एमफिल की एक प्रोफेशनल डिग्री का प्रविधान किया गया है। इसके अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य और उपचार के लिए छात्रों को गहन सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके द्वारा मानसिक रोगियों के उपचार के लिए प्रशिक्षार्थी को थेरेपी देने के लिए योग्य बनाया जाता है। नई शिक्षा नीति में एमफिल की डिग्री को बंद करने का फैसला लिया गया है। इसके फलस्वरूप अन्य विषयों की तर्ज पर क्लिनिकल साइकोलोजी में भी एमफिल डिग्री को बंद करना होगा। इस एमफिल डिग्री की उपादेयता को अन्य विषयों में एमफिल के बराबर रख कर देखना घातक है। इसे बंद करने से मानसिक स्वास्थ्य की देख-रेख के लिए जो भी थोड़े बहुत मानव संसाधन तैयार हो रहे थे, वह क्रम रुक जाएगा। यह समाज के लिए बड़ा घातक होगा। सरकार इस पर पुनर्विचार करे।

मानसिक परेशानी के चलते शारीरिक बीमारियां भी होती हैं। इसी तरह शारीरिक रोग से मानसिक रुग्णता पैदा होती है। शरीर और मन की अलग रखना गलत है, क्योंकि स्वास्थ्य और बीमारी, दोनों ही स्थितियों में ये एक संयुक्त इकाई के रूप में ही काम करते हैं। आज बेरोजगारी, सामाजिक अन्याय, पारिवारिक विघटन, जीवन-हानि और गरीबी जैसी स्थितियां आम आदमी के मानसिक स्वास्थ्य के लिए चुनौती बनती जा रही हैं। कंप्यूटर, इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धि जैसे तकनीकी हस्तक्षेपों के चलते कामकाज अधिकाधिक स्वचालित होते जा रहे हैं। स्मार्टफोन जैसे उपकरणों के नए-नए माडल शान-शौकत के प्रतीक बनते जा रहे हैं। ऐसे उपकरणों के न होने पर आदमी की हैसियत कम आंकी जाती है, जो मानसिक रोग का एक कारण बन रही है।

वैश्विक स्तर पर हुए स्वास्थ्य-सर्वेक्षणों में तुंदियता यानी एंजाइटी, फोबिया, बाई-पोलर डिसआर्डर आदि मनोरोगों से ग्रस्त लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इसके चलते लोग मादक द्रव्य, तंबाकू, मद्यपान और विभिन्न ड्रग्स का सेवन भी तेजी से कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रपटें इकक्कीसवीं सदी में स्वास्थ्य का भयावह चित्रण कर रही हैं। प्रौढ़ जनसंख्या में एक तिहाई लोग अनिद्रा से ग्रस्त हैं। 1999 के बाद आत्महत्या के मामलों में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारत में 2017 में हुए एक सर्वेक्षण में हर सात में से एक व्यक्ति को किसी न किसी मनोरोग से ग्रस्त पाया गया था। आज अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं और आर्थिक संसाधन बढ़ने से शरीर की आयु तो बढ़ गई, पर आदमी का मन कमजोर होने लगा है। अल्जाइमर और डिमेंशिया के रोग लोगों में तेजी से बढ़ रहे हैं। अवसाद, शराब की लत, बाई पोलर डिसआर्डर और सिजोफ्रेनिया आज एक महामारी के रूप में उभर रही है। स्थिति की भयावहता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि अकेले उत्तरी अमेरिका में 2022 में 326 अरब डालर अवसाद के उपचार में खर्च हुआ था। वर्ष 2010 में यह खर्च 210.5 अरब डालर था। इस सदी के तीसरे दशक में वैश्विक स्तर पर 16 लाख करोड़ डालर मनोरोगों से जूझने पर खर्च करने होंगे।

सांसारिक सुख-भोग करना सबको प्रिय है। बाजार और विज्ञापन ने सुख को उपभोग से जोड़कर आग में घी डालने का काम किया है। अब हम अपनी 'सफलता', विकास और सुख अधिकाधिक उपभोग में देखने के आदी हो गए हैं, परंतु उपभोग की वस्तुओं को एकत्र करते रहने के बावजूद हम तनाव, चिंता, दबाव, अकेलापन, व्यसन या लत, असंतुष्टि, कुंठा जैसी समस्याओं से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर स्वस्थ रहने के लिए जरूरी क्या है? इस सवाल के जवाब में समुचित आहार (भोजन), विहार (आचरण), निद्रा और चेष्टा (कार्य) को आवश्यक बताया गया है। पांच महाभूत-पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश हो तो हैं, जो हमें रचते हैं और रचना के बाद आकार पाकर हम भी उन्हें प्रभावित करते हैं। इनके साथ संगति और विसंगति से स्वास्थ्य प्रभावित होता है। हमारे शरीर सथ्य भी है और मानसिक अस्तित्व का सथन भी। इसी तरह महाना बुद्धि अधिक और कम के बीच का मार्ग अपनाने को कहते हैं। लोक-व्यवहार में भी 'अति' वाला आचरण वर्जित माना जाता है। बड़े-बूढ़े अब भी संतुलित जीवन की हिदायत देते हैं। स्वस्थ रहने के लिए जीवनशैली में बदलाव और रोग की स्थिति में उसकी उपेक्षा न कर उसका समाधान करना आवश्यक है। आशा है देश की आवश्यकता को देखते हुए मानसिक स्वास्थ्य के लिए लोक जागरण के साथ उसके अध्ययन की सुविधाओं का विस्तार करने पर भी ध्यान दिया जाएगा।

(लेखक दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर एवं कुलपति रहे हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

धैर्य की शक्ति

धैर्य में अद्भुत शक्ति है। अनेक संकटों का समाधान धैर्य में निहित है। जिन प्रश्नों का उत्तर विद्वान भी नहीं दे सके, उनका हल सहैव धैर्य ने किया है। ऋषि-मुनियों ने धैर्य को भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताया है। वास्तव में सभी उपायों में धैर्य सर्वोत्तम है। संत पथिक जी महाराज का कहना था कि विश्व में जो भी झंझावात हैं, उनका समाधान धैर्य द्वारा सफलतापूर्वक किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। सद्गुणों में धैर्य का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। कठिन से कठिन परीक्षाओं को धैर्य के माध्यम से पार किया जा सकता है। यह एक सिद्ध प्रयोग है। महात्माओं ने धैर्य के चमत्कारी प्रभावों का उल्लेख किया है। ज्ञानार्जन से लेकर जीविकोपार्जन तक, धैर्य की परंपरा अद्भुत और उपयोगी है। यह सबसे सरल साधना के रूप में भी प्रतिष्ठित है। विद्यार्थी, व्यवसायी और राजनेता सभी ने धैर्य से लाभ उठाया है। कभी-कभी धैर्य के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचता। विद्वानों ने समय को धैर्य से जोड़कर विशिष्ट प्रयोजन उद्घाटित किए हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए समय का सम्मान आवश्यक है। समय का समादर ही धैर्य कहलाता है और काल को उचित प्रतीक्षा भी इसे परिभाषित करती है। इतिहास साक्षी है कि बड़े-बड़े महारथी और सम्राट भी समय के अधीन अपनी रणनीतियों को सफलतापूर्वक लागू कर सके। धैर्य धारण करने के बाद ही उनके समक्ष अवसर आए। विपरीत समय ने कभी उनका साथ नहीं दिया। केवल अनुकूल समय ने ही उन्हें विजय दिलाई, जो धैर्य के माध्यम से संभव हुआ।

इस प्रकार धैर्य केवल एक गुण नहीं, बल्कि जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है और हमें सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करता है। धैर्य का अभ्यास करने से हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।

डा. राघवेंद्र शुक्ल

रिश्तों की टूटती डोर

स्वाति

आज देश में तलाक, विवाहेत्तर संबंध, अलगाव, हिंसा और हत्याओं की बाढ़ आ गई है, जिसे देखकर हमें चेतना चाहिए

कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी के एक बयान पर अभी विरोध का स्वर थमा भी नहीं था कि प्रेमानंद महाराज जी का ताजा बयान बहस को आगे बढ़ाता दिख रहा है। हाल में अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा कि लड़कियों को विवाह पूर्व किसी भी ऐसे संबंध में नहीं पड़ना चाहिए जिससे उनका स्त्रीत्व खंडित होता हो। समाज की इस समस्या को आज के परिप्रेक्ष्य में अनदेखा नहीं किया जा सकता। गत दिनों सोनम रघुवंशी मामले ने पूरे देश का ध्यान खींचा। किसी अन्य के साथ प्रेम संबंध में रहते हुए विवाह में प्रवेश करन और फिर अपने पति की हत्या करना विवाह पूर्व संबंधों के कुप्रभाव को दर्शाता है। इस प्रकार की घटनाओं की बढ़ती संख्या सच्च समाज के लिए घातक है।

लिव-इन रिलेशनशिप के लिए देश में कोई विशेष कानून नहीं है। ऐसे रिश्तों में लिप्त हिंसा, बच्चों के अधिकार, संपत्ति में अधिकार आदि मौजूदा कानूनों द्वारा संरक्षित होते हैं। जज अपने निर्णय में रिश्ते को 'प्रकृति और परिस्थिति' को आधार बनाते हैं। उदाहरण के लिए, युगल के एक साथ रहने की अवधि, घरेलू जिम्मेदारियों का बोध और क्रियान्वयन, साझा प्रापर्टी आदि की स्थितियां निर्णायक होती हैं। ऐसे रिश्तों में संबंध-विच्छेद की स्थिति में लड़कियां अक्सर लड़कों पर दुष्कर्म का आरोप लगा देती हैं, जिसे न्यायालयों ने कई मामलों में अस्वीकार किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सितंबर 2023 में लिव-इन को लेकर कड़ी टिप्पणी की थी। जब एक लड़की गर्भवती हुई और लड़के ने संबंध विच्छेद किया, तो लड़की ने दुष्कर्म का केस किया। जस्टिस सिद्धार्थ की सिंगल बेंच ने लड़के को जमानत देते हुए कहा कि जानवरों की तरह हर मौसम में पार्टनर बदलने का चलन एक सभ्य और स्वस्थ समाज की निशानी नहीं हो सकता। हाई कोर्ट ने कहा कि शादी में जो सुरक्षा, सामाजिक स्वीकृति और स्थायित्व मिलता है, वह लिव-इन रिलेशनशिप में कभी नहीं मिल सकता।

इन सबका यह अर्थ नहीं कि पुरुष दोषी नहीं हैं। दोनों कथावाचकों ने भी लड़के और लड़की दोनों के लिए ऐसे संबंधों को अनैतिक और असामाजिक बताया है, जिसका कुत्सित प्रभाव विवाह पर पड़ता है। समाज की संयमित और सुसंस्कृत करने की जिम्मेदारी स्त्री और पुरुष दोनों पर होती है। आज भारत में तलाक, विवहेतर संबंध, अलगाव, हिंसा और हत्याओं की बाढ़ आ रही है, जिसे देखकर हमें चेतना चाहिए। स्त्री अपने ममत्व और स्त्रीत्व के लिए पूज्य होती है। वह अपने दूध और स्नेह से परिवार को सींचती है। अपनी इच्छाओं का त्याग करके प्रेम और समर्पण का भाव रखती है। पुरुषों की प्रकृति न तो समर्पण की होती है और न ही संयम की, जिस प्रकार स्त्रियों की होती है। ऐसे में यदि स्त्रियां भी स्त्रीत्व को ताक पर रखेंगी, तो निःसंदेह समाज का संतुलन, मर्यादा और उनकी स्वयं की सुरक्षा भी प्रश्नचिह्नित होगी।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

बनकर स्वदेशी के मूलमंत्र 'वोकल फार लोकल' को अपनाना ही श्रेयस्कर होगा।
pandeyvp1960@gmail.com

भरोसे के लायक नहीं अमेरिका

'एक चिट्ठा हुआ शासनाध्यक्ष' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में संजय गुप्त ने सधे अंदाज में भारत के प्रति अमेरिका के बदलते रुख का विश्लेषण किया है। अपने मित्र देशों के प्रति अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बेरुखी से उन्हें कुछ हासिल होने वाला तो नहीं, उलटे नुकसान की आशंका ज्यादा है। विशेषकर भारत के संदर्भ में यह माना जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पारंपरिक मित्र रूस के साथ उसके घोर विरोधी अमेरिका से भी मित्रवत संबंध बनाए रखे हैं, जो भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का परिचायक है। विश्व के सक्षम और शक्तिशाली राष्ट्र प्रधानमंत्री मोदी की साफ-सुथरी नीति और नीयत के वशीभूत होकर ही भारत को अपना मित्र बनाने में गौरव की अनुभूति करते हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का अजीबो-गरीब व्यवहार सभी को अचंभित कर रहा है। भारत सहित विश्व के अन्य देशों के साथ अमेरिका द्वारा छेड़ा गया 'टैरिफ वार' वैश्विक स्तर पर आर्थिक अस्थिरता पैदा करने वाला है। बिना किसी नीति-नियम के चोरा देखकर टैरिफ लगाने से अमेरिका विश्व बाजार में अपनी विश्वसनीयता खो रहा है। अब वह किसका भला कर रहा है और किसको हानि पहुंचाने का सोच रहा है, यह समझ पाना मुश्किल है। वर्तमान में फरेबी पाकिस्तान के साथ बढ़ती उसकी नजदीकियां और विश्वसनीय मित्र भारत के साथ उपेक्षित व्यवहार अमेरिका की अविश्वसनीयता का परिचायक है। राष्ट्रपति ट्रंप भरोसे के लायक नहीं रहे। वह किस बात पर कब करवट बदल कर अपना मुंह मोड़ लें, यह समझ से परे है। ऐसे में भारत के लिए आत्मनिर्भर होकर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।

विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

कांग्रेस नेताओं के बचकाना बयान

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसके पीछे बहुत बड़ा योगदान भारतीय चुनाव आयोग का रहा है। भारतीय चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जो देश में हर तरह के चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष कराकर में अपना अहम योगदान देती रही है। भारत में पहले ही लोकसभा चुनाव-1951 को विभिन्न कठिनाइयों के बावजूद सफलतापूर्वक करवा कर चुनाव आयोग ने देश-विदेश में अपनी योग्यता तथा निष्पक्षता का सुबूत सामने रख दिया था। तब से लेकर आज तक चुनाव आयोग ने बिना किसी दबाव के हर तरह के चुनाव स्वतंत्र तथा निष्पक्षता पूर्वक करवाए हैं। भारतीय चुनाव आयोग की उपलब्धियों तथा चुनावी प्रक्रिया का दुनिया लोहा मानती है। ऐसे में राहुल गांधी और पी. चिदंबरम जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं द्वारा चुनाव आयोग और उसके अफसर, कर्मचारियों पर बेतुके आरोप लगाना उनके संकीर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जबकि उनके इन बेतुके आरोपों पर कोई भी आंशिक सुबूत भी उनके पास नहीं है। इस तरह से कांग्रेस के नेताओं द्वारा भारतीय चुनाव आयोग पर लगाए गए बेतुके आरोप एक तरह से भारतीय संवैधानिक संस्था पर हमला है। इसलिए चुनाव आयोग को ऐसे कांग्रेसी नेताओं पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।

विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

स्वदेशी अपनाएं

चीनी उत्पादों के अब भी घरेलू बाजार में बिकने का कारण यही है कि हमारे देश में दिन-प्रतिदिन के सामान बनाने वाले उपक्रम बहुत छोटे स्तर पर हैं। बहुत सीमित पूंजी, पुरानी और लोकल मशीन, परिवार तक सीमित रोजगार देने वाले उपक्रम कभी भी चीन के सस्ते और नए उत्पादों का सामना नहीं कर सकते। यह तो सही है कि हमारे उद्योग व्यापार की आधे से अधिक भागीदारी एमएसएमई क्षेत्र की है और लगभग ग्यारह करोड़ रोजगार भी इसी क्षेत्र में सृजित हैं, परंतु यह भी स्वीकार करना आवश्यक है कि विदेशी उत्पादों को प्रतिस्पर्धा देने में एमएसएमई क्षेत्र सक्षम नहीं है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि घरेलू आवश्यकता की वस्तुएं, विशाल स्तर पर भी निर्मित हों, जो संपूर्ण देश में आपूर्ति शृंखला को पोषित कर सकें और कीमतों में भी विदेशी उत्पादों को प्रतिस्पर्धा दे सकें।

विनोद जौहरी, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

40 बहिशत छात्र डुअल डिग्री जैसे मिकल्पों को अपनाते हैं अमेरिका में, जबकि 45 से अधिक यूरोपीय देशों में यह प्रणाली प्रभावी रूप से लागू है। दरअसल : इससे छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्ति के पश्चात रोजगार तलाशने में अधिक सुविधा रहती है।

आजकल

भविष्य की मांगों के अनुरूप शिक्षा में सुधार

भारत में उच्च शिक्षा एक निर्णायक समय में प्रवेश कर चुकी है, जहां लचीलापन, समावेशिता और गुणवत्ता को केंद्र में रखते हुए संरचनात्मक सुधारों की नींव रखी जा रही है। यूजीसी द्वारा हाल ही में लागू की गई एक सत्र में दो डिग्रियों की मान्यता एवं प्रस्तावित मल्टीपल एंट्री-एक्जिट प्रणाली जैसे ऐतिहासिक निर्णय, उच्च शिक्षा को पारंपरिक जड़ता से मुक्त कर उसे अधिक व्यावहारिक, विद्यार्थी-केंद्रित और समावेशी माडल की ओर ले जा रहे हैं। यह केवल शैक्षणिक ढांचे में बदलाव नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तीकरण और युवाओं की आकांक्षाओं के साथ जुड़ा परिवर्तन है

कजार की आवश्यकताओं के अनुरूप एक समय में दो डिग्री प्राप्त होना छात्रों के व्यापक हित में होगा। फाइल

गजेंद्र सिंह
लोक नीति विश्लेषक

भारत में हर वर्ष लगभग 94 लाख छात्र उच्च शिक्षा में प्रवेश लेते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी, सामाजिक बाधाओं या करियर को लेकर अनिश्चितता के कारण इनमें से अनेक डिग्री पूरी नहीं कर पाते। स्नातक स्तर पर ड्रापआउट दर 12.6 प्रतिशत है, जो कुछ विषयों जैसे इंजीनियरिंग (13.5 प्रतिशत), कृषि (14.3) और सामाजिक विज्ञान (15 प्रतिशत) में और भी अधिक है। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि यह दर ग्रामीण, आदिवासी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में अपेक्षाकृत अधिक है। लड़कियां विशेष रूप से प्रभावित होती हैं- बाल विवाह, घरेलू जिम्मेदारियां, सामाजिक मान्यताएं और सुरक्षा की चिंताएं उनहें शिक्षा बीच में छोड़ने को मजबूर कर देती हैं।

डुअल डिग्री : विश्व स्तर पर डुअल डिग्री (एक ही समयावधि में एकसाथ दो डिग्रियां) कार्यक्रमों की शुरुआत 20वीं सदी के मध्य में अमेरिका और यूरोप में हुई थी। अमेरिका के कुछ प्रतिष्ठित संस्थानों ने विज्ञान, तकनीक, प्रबंधन और विधि के संयोजन वाली डिग्रियों की शुरुआत की। आज अमेरिका में लगभग 40 प्रतिशत छात्र डुअल डिग्री जैसे विकल्पों को अपनाते हैं। इसी तरह, आस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड विश्वविद्यालय और ब्रिटेन के आक्सफोर्ड तथा लंदन स्कूल आफ इकोनमिक्स जैसे संस्थानों में भी संयुक्त डिग्री कार्यक्रमों को वर्षों से मान्यता प्राप्त है। यूरोप में 1989 में इसकी शुरुआत की गई, जिससे छात्र अपनी पढ़ाई विभिन्न देशों और विश्वविद्यालयों में जारी रख सकते हैं। आज यह प्रणाली 45 से अधिक यूरोपीय देशों में प्रभावी रूप से लागू है और छात्रों को बहुस्थीय शिक्षा, चरणबद्ध डिग्री प्राप्ति तथा पढ़ाई में अंतराल लेने की स्वतंत्रता देती है।

भारत में डुअल डिग्री की अवधारणा भले ही थोड़ी देर से आई हो, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और कौशल भारत अभियान ने इसे समय की आवश्यकता बना दिया है। यूजीसी द्वारा प्रस्तावित 'बहुविकल्पीय प्रवेश और निर्गमन' व्यवस्था के अंतर्गत विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक प्रगति के विभिन्न चरणों पर मान्यता प्रदान की गई है। इस प्रणाली के तहत पहले वर्ष के बाद प्रमाणपत्र, दो वर्षों के उपरांत डिप्लोमा, तीन वर्षों पर स्नातक की डिग्री और चार वर्षों के बाद शोध सहित स्नातक (आनर्स विद रिसर्च) डिग्री प्राप्त की जा सकती है। यदि कोई छात्र किसी कारणवश पढ़ाई बीच में छोड़ देता है, तो उसके द्वारा अर्जित शैक्षणिक अंक 'अकादमिक बैंक आफ क्रेडिट (एबीसी)' में सुरक्षित रहेंगे। वह जब चाहे, पुनः उसी स्तर से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकता है, जिससे शिक्षा प्रणाली अधिक लचीली, समावेशी और व्यावहारिक बनती है।

व्यावहारिक कौशल का विकास : वर्ष 2023 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के लगभग 65 प्रतिशत छात्र पारिवारिक या आर्थिक दबावों के चलते बीच में शिक्षा छोड़ने को मजबूर होते हैं। वहीं, नैसकाम की 2021 की रिपोर्ट में यह उजागर किया गया कि हर साल भारत में स्नातक होने वाले लगभग 80 लाख छात्रों में से केवल 45 प्रतिशत ही रोजगार योग्य होते हैं। ये तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि केवल डिग्री प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि विषयों का उपयुक्त संयोजन और व्यावहारिक कौशल का विकास भी उतना ही आवश्यक है। ऐसे में एक साथ दो डिग्री प्राप्त करने का विकल्प छात्रों को न केवल विविधता और बहु-कौशल अर्जित करने का अवसर देता है, बल्कि उनकी रोजगार क्षमता को भी सशक्त बनाता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई छात्र 'समाजशास्त्र' और 'डाटा एनालिटिक्स' दोनों में डिग्री प्राप्त करता है, तो वह सामाजिक व्यवहार का विश्लेषण सांख्यिकी आधारित डाटा से कर सकता है- यह नीति निर्माण और शोध में उपयोगी सिद्ध होता है।

आल इंडिया सर्वे आन हायर एजुकेशन 2021-22 के अनुसार, भारत में लगभग 4.3 करोड़ विद्यार्थी उच्च शिक्षा में नामांकित हैं, जिनमें से करीब 80 लाख छात्र दूरस्थ या आनलाइन शिक्षा के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि देश में बड़ी संख्या ऐसे छात्रों की है जो पारंपरिक रेगुलर पाठ्यक्रमों के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे में बहुविकल्पीय शिक्षा प्रणाली उन्हें पारंपरिक डिग्री के साथ-साथ आजीविका केंद्रित कौशल प्राप्त करने का अवसर देती है।

यूजीसी के 'बहुविकल्पीय प्रवेश और निर्गमन'' प्रस्ताव के तहत, जून 2025 तक 2.5 करोड़ छात्रों के अकादमिक बैंक आफ क्रेडिट बन चुके हैं और 55 करोड़ से अधिक शैक्षणिक अंकों का स्थानांतरण हो चुका है। हर स्तर की डिग्री को ''राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा'' से जोड़ा जाएगा, ताकि वह रोजगार में भी मान्य हो। पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों के लिए सेतु (ब्रिज) और रिमेडियल पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गई है, ताकि वे आसानी से दोबारा जुड़ सकें। इस दिशा-निर्देश में अंतरविषयी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया गया है, जिससे छात्र विषयों का संयोजन कर अपनी रचनात्मकता और रोजगार क्षमता बढ़ा सकें।

इन सुधारों का उद्देश्य शिक्षा को जीवन की परिस्थितियों से जुड़ा, व्यावहारिक और अवसर-सृजक बनाना है। यदि इन नीतियों को डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी प्रशिक्षण व स्थानीय जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक लागू किया जाए, तो भारत ड्रापआउट, बेरोजगारी और कौशल-असमानता जैसी जटिल समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपट सकता है। आज शिक्षा को केवल 'एक बार का प्रयास' न मानकर, 'जीवन भर की यात्रा' के रूप में पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है, और यही उच्च शिक्षा में लचीलापन लाने की नीति का मूल मंत्र है।

सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर बढ़ता देश

वैष्णि मेहरोत्रा
शिक्षा एवं तकनीकी मामलों की जानकार

वर्तमान सदी की तकनीकी क्रांति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) एक ऐसा बदलाव है, जो भारत के भविष्य को बेहतर बनाने की बड़ी क्षमता रखता है। यह केवल एक तकनीकी प्रगति नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा शक्तिशाली साधन है जो भारत की शिक्षा प्रणाली में क्रांति ला सकता है और हमारे युवाओं के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। 'फाउंडेशन माडल'' इस बदलाव के केंद्र में हैं, और यह स्पष्ट संकेत देते हैं कि भारत के लिए आगे बढ़ने का रास्ता क्या है। भारत जैसे बड़े और विविध देश में सभी के लिए एक जैसी शिक्षा देना हमेशा मुश्किल रहा है। लेकिन एआइ फाउंडेशन माडल इस मुश्किल को आसान बना सकते हैं और एक अच्छा समाधान दे सकते हैं।

कल्पना कीजिए कि गांव का एक छात्र अपनी स्थानीय भाषा में एक एआइ ट्यूटर से विज्ञान के जटिल सिद्धांत सीख रहा है, जो उसकी सीखने की गति के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है। फाउंडेशन माडल हर छात्र के लिए व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं, अभ्यास और तत्काल फीडबैक प्रदान कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी छात्र पीछे न छूटे और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एआइ का उद्देश्य शिक्षकों की जगह लेना नहीं, बल्कि उन्हें और अधिक सशक्त बनाना है। यह रोहेंद्रिग, उपस्थिति दर्ज करने और रिपोर्ट तैयार करने जैसे प्रशासनिक कार्यों को स्वचालित कर सकता है, जिससे शिक्षकों का बहुमूल्य समय बचेगा। इस बचे हुए समय का उपयोग शिक्षक छात्रों को मार्गदर्शन देने, उनमें महत्वपूर्ण सोच विकसित करने और उनकी व्यक्तिगत जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कर सकते हैं।

भारत की भाषाएं और सांस्कृतिक विविधता, जिसे अक्सर एक तकनीकी चुनौती के रूप में देखा जाता है, वास्तव में भारतीय एआइ की विशिष्ट और शक्तिशाली बनाने का सबसे बड़ा अवसर है। चूंकि भारत की कई भाषाएं ही उसकी असली ताकत हैं। इसलिए एक प्रभावी भारतीय एआइ माडल को केवल हिंदी या अंग्रेजी ही नहीं, बल्कि तमिल, बंगाली, मराठी और अन्य भारतीय भाषाओं को भी समझना होगा। जब हम भारतीय भाषाओं के लिए एआइ माडल विकसित करेंगे, तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षा हर बच्चे तक उसकी अपनी मातृभाषा में पहुंचे, जिससे सीखना अधिक सहज और प्रभावी हो जाएगा। भारतीय छात्र जब डाटा साइंस, मशीन लर्निंग और एआइ जैसे विषयों में काम करेंगे, तो डिग्री हासिल करने के साथ ही वे दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। भारतीय भाषाओं और डाटा को समझने वाले ये युवा आज तमाम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए कीमती साबित हो रहे हैं। यह हुनर भारत में केवल बेहतर तकनीकी नौकरियां ही नहीं लाएगा, बल्कि हमारे युवा विदेश में भी नेतृत्व वाले पदों पर काम करेंगे।

भारत को तकनीक का मार्गदर्शक भी बनना है। इसके लिए हमें मिशन की तरह काम करना होगा। लिहाजा हमें एक स्पष्ट संकल्प की आवश्यकता है। अनुसंधान, नवाचार और विश्वस्तरीय कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में दीर्घकालिक और ठोस निवेश की आवश्यकता है, जिससे प्रभावी समाधान विकसित किए जा सकें। यह सुनिश्चित करना होगा कि यह तकनीक ओपन-सोर्स के माध्यम से हर भारतीय छात्र और स्टार्टअप तक पहुंचे। अब सवाल यह नहीं है कि भारत क्या कर सकता है, बल्कि यह है कि हम कितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं। अगर हम समय रहते एआइ को अपनाते हैं, तो भारत केवल तकनीक इस्तेमाल करने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया भर के लिए टैलेंट और इनोवेशन का केंद्र बन जाएगा।

फिर से

खोईछा

विवाहित स्त्रियों को 'खोईछा' देने की प्रथा लगभग हर राज्य में प्रचलित है। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नाम हैं इसके। बिहार में इसे 'खोईछा' कहते हैं। शायद उत्तर भारत में 'गोद भरन' कहते हैं। यह परंपरा हमारी भावनाओं एवं धार्मिक महत्व का मिश्रण है। जब भी कोई विवाहित स्त्री मायके जाती है और जब वापस आने लगती है तो मां, भाभी, चाची या बुआ जो सुहागन हो, उसके आंचल में बड़े स्नेह और भावुकता के साथ चावल, हल्दी की गांठ, दूर्वा, सुपारी एवं सामर्थ्यानुसार कुछ पैसे देती हैं।

आंचल में दी जाने वाली वस्तुओं में स्थान विशेष के रिवाज के अनुसार भिन्नता हो सकती है। परंतु भावनएं वही रहती हैं। फिर एक दूसरे की मांग में सिंदूर लगाना, अश्रुपूरित नयनों से एक दूसरे को देखना, चावल के दो चार दाने मां या भाभी के द्वारा निकालते हुए यह कहना कि फिर जल्द ही मायके आना, बेटियों को भावुक बना ही देता है। ग्रामीण समाज में तो यह प्रथा आज भी जीवित है। गांवों में तो कहते हैं बेटियां सब की साझी होती हैं। ग्रामीण समाज में बेटियों को विदा होते समय केवल अपने ही घर से नहीं, बल्कि गांव के सभी खितेदुरों के घर से खोईछा मिलता है। कितनी भावनाएं बंधे होती हैं उन चंद सामग्रियों में। खोईछा देने की प्रथा के पीछे बेटी-बहू की खुशहाली एवं उनके सौभाग्य की मंगलकामना का उद्देश्य ही हो सकता है। खोईछा में दी जाने वाली सामग्री यथा अक्षत, दूब, हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का का हमारे हिंदू धर्म में कितना महत्व है, यह तो हम सब जानते ही हैं।

वैसे दुर्गा को भी नवरात्र के मौके पर अष्टमी या नवमी को सुहागन स्त्रियां खोईछा अवश्य देती हैं। कहते हैं नवरात्र में मां दुर्गा मायके आती हैं। अतः उन्हें खोईछा दे कर विदा करते हैं। अर्थात यह परंपरा बहुत पुरानी है और आस्था से जुड़ी है। अब शायद यह प्रथा कुछ कमजोर होती जा रही है। नई पीढ़ी की महिलाएं इन रिवाजों से ज्यादा बंधे नहीं हैं। समय और सुविधा के अनुसार रीति-रिवाजों में कमी आई है। पर हमारी पीढ़ी की महिलाएं इसे भूल नहीं सकतीं, बहुत सी मधुर यादें जुड़ी होंगी। मायके जाने का एक अहम हिस्सा है खोईछा।

(राजीव पांडे की फेसबुक वाल से संपादित अंश, साभार)

पोस्ट

एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच की सूचना पीड़ा देने वाली है। सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए। सरकार इस पर रोक नहीं लगाती है तो 'हम भारत के लोग' इसका बहिष्कार करें। यह किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

हर्ष वर्धन त्रिपाठी @MediaHarshVT

भारत की इस बात के लिए तारीफ करनी होगी कि वह ट्रंप के आक्रामक रवैये के आगे झुकने को तैयार नहीं। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत में फैसले संस्थागत प्रक्रिया के जरिये हो रहे हैं, न किसी एक व्यक्ति के फरमान पर। याद रहे कि राष्ट्रहित व्यक्तिगत हितों से अधिक संस्थागत प्रतिक्रिया से ही बेहतर पोषित होते हैं। जावेद हसन @javedhassan

एक उद्यमी के रूप में ट्रंप ने अपने कारोबार को कुछ ही दशकों में डुबोकर दिवालियेपन के कगार पर पहुंचा दिया। राष्ट्रपति के रूप में भी वह अमेरिका को नैतिक दिवालियेपन की ओर ले जाने पर आमादा हैं। उनका कार्यकाल अमेरिका को भारी कर्ज और भूराजनीतिक चुनौतियों के साथ छोड़ेगा।

मिन्हाज मर्चेंट @MinhazMerchant

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या भारत को रूस से अधिक से अधिक मात्रा में तेल खरीदना चाहिए?

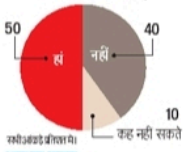

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मैच पर दर्शकों के बहिष्कार से कोई असर पड़ेगा?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

बाबा श्री पीएम रहे पोता बना कलक,
रेवन्ना के नाम से लगता जैसे डाक।
लगता जैसे डाक करे उससे महिलाए,
प्रभु ना ऐसा वंश किसी के गले लगाएं।
करके क्रूर कुकर्म जेल घूंटे पीता जी,
कैसे अपना शीश उठाएं अब बाबाश्री!
- अमिताभ कुमार तिवारी

ऊर्जा मंत्री को 'अंडर करंट' के झटके

भारतीय वसंत कुमार
वरिष्ठ समाचार संपादक, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश डायरी

घटनाक्रम ताजा ही है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा सुलतानपुर के सुरापुर कस्बा पहुंचे थे। हरे रंग का चमकीला कुर्ता पहने, गले में लर्दे गेंदा के फूलों की मालाओं का बोझ उतारते उनका एक वीडियो भी खूब प्रसारित हुआ। वीडियो में लोग ग्रामीण क्षेत्र में बिजली कटौती की शिकायत कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि सरकार ने 24 घंटे बिजली का वादा किया था, पर कटौती बेहिसाब हो रही है। मंत्री इस पर कोई जवाब तो नहीं देते, पर दोनों हाथ ऊपर उठाकर और जय श्री राम... जय हनुमान... का उद्घोष करते गाड़ी में बैठ निकल लेते हैं।

इन दिनों प्रदेश के बिजली विभाग में 'अंडर करंट' कुछ ज्यादा ही झटके दे रहा है। निजीकरण के खिलाफ कर्मचारी संगठनों का आंदोलन, राजनीति में हैसियत और भागीदारी, विभाग के अफसरों का रौब या उन पर मंत्री की हनक जैसे अनेक मुद्दे फाइल से निकल कर 'एक्स' पर पसर चुके हैं। कभी अपने विभाग के कामकाज को खूब तारीफ करने वाले ऊर्जा मंत्री की 28 जुलाई की पोस्ट ने भी खूब पलीता लगाया। पोस्ट थी- 'निहित स्वार्थी तत्वों ने उनके खिलाफ हाथ मिला लिया है।' पोस्ट में कहा गया कि ऊर्जा मंत्री के खिलाफ सुरापी लेने वालों में बिजली कर्मचारी के वेश में कुछ उपद्रवी तत्व भी शामिल हैं। इससे पूर्व शक्ति भवन में हुई बैठक में अफसरों के प्रति तल्ख रवैये ने भी मंत्री को चर्चा में ला दिया।

नौकरशाही से राजनीति में पदार्पण करने वाले एके शर्मा गुजरात कैडर के आइएएस अधिकारी रहे हैं। इस नाते उन्हें दिल्ली दरबार का करीबी माना जाता है। दूसरी ओर उनका यह बखान आता है कि जब ऊर्जा मंत्री एक जेई का ट्रांसफर नहीं कर सकते तो निजीकरण का इतना बड़ा निर्णय अकेले कैसे कर सकते हैं? अभिप्राय सफ है कि विभाग को कहीं और से पोषण मिल रहा है। यही असली टेंशन है। कर्मचारी नेताओं की बार-बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बिजली विभाग की कमान अपने हाथ में लेने की अपील भी उन्हें खलती होगी।

मंत्री यूं ही अस्हज नहीं हैं। उनकी तमाम कोशिश के बाद भी राज्य में अभी तक बिजली के निजीकरण के लिए निविदा जारी नहीं हो पाई है। परामर्शी कंपनी को मार्च के अंतिम सप्ताह में इसके लिए नामित किया गया था और 120 दिनों की मियाद तय की गई थी, परंतु यह हो नहीं सका। मंत्री कहते हैं कि उनका विभाग 'उपभोक्ता देवो भवः' की संस्कृति का पालन करता है। उपभोक्ताओं की उपेक्षा नहीं चलेगी। उपभोक्ता से अमर्यादित भाषा में बात करने वाले बस्ती के अधीक्षण अभियंता को उन्होंने इसी वजह से निलंबित कर दिया। मंत्री जितना हांफ रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभाग की नकेल उतनी ही कस रहे हैं। हाल ही में विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने पूछा कि जब पैसा, संसाधन सब है, तब यह बेहाली क्यों? उधर, झंडा उठाए खड़े कर्मचारी मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग कर रहे। सामने पंचायत चुनाव है। इसलिए सरकार विपक्ष को बिजली को मुद्दा बनाने का कोई अवसर देना नहीं चाहती। जाति की राजनीति में एके शर्मा के बरक्स कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही का कद लोग नापने लगे हैं। तभी तो अपने गृह क्षेत्र में मंत्री जी यह बोलने से नहीं चूकते कि अगर वे भगवान राम की तरह तीर छोड़ देंगे तो दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन भी बचा नहीं सकेगा।

बिजली की समस्या पर हाथ उठाकर जय श्रीराम का नारा लगाते ऊर्जा मंत्री एके शर्मा। फाइल

सपा की पीडीए पाठशाला में अक्षर ज्ञान : प्रदेश में स्कूलों का विलय पहले शिक्षा सदन में हलचल मचाता है, फिर हाई कोर्ट का चक्कर लगाता है। बात यहीं नहीं थमती तो सरकार के फैसले को समझाने के लिए मंत्री संदीप सिंह आगे आते हैं। सूचना विभाग सरकार के इस निर्णय के लीकहित का विज्ञापन भी प्रकाशित करता है, पर इंटरनेट मीडिया पर पीडीए की पाठशाला के रील तैरने लगे तो नौबत मुकदमे तक की आ जाती है। सरकार का दावा है कि एक भी स्कूल बंद नहीं किया गया है। जिन दस हजार स्कूलों का विलय किया गया है, उनमें भी, पांच हजार में बाल वाटिका और पुस्तकालय खुलेंगे। यह बात और है कि पाठशाला के शक्लपट पर राजनीति के अक्षर बड़े-बड़े वाक्यों में बदलने लगे हैं। कानपुर में सपा की महिला नेता रचना सिंह गौतम पर पीडीए पाठशाला के बहाने अफवाह फैलाने का मुकदमा दर्ज होता है तो सहारनपुर में सपा नेता फरहाद आलम बच्चों को ए फार अखिलेश और डी फार डिंपल पढ़ाए जाने का वीडियो पोस्ट करते हैं। दूसरे जिलों में भी मुकदमे का दौर शुरू है। सपा चाहती है कि विलय का मुद्दा जिंदा रहे। भाजपा का अपना तर्क है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी इसे समाजवादी ब्रेनवाश बताते हैं। यह जोड़ते हुए कि ए फार अखिलेश और डी फार डिंपल में भी सपा का परिवरवाद ही छाया है। यह सब माया है बच्चों के कोमल चेतना में राजनीतिक बिच्छेल रोपने की। यह तय है कि पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट ऐसे विवाद और व्यवहार के पनपने के लिए खाद का काम करेगी।

छत्तीसगढ़ डायरी

राजनीतिक हलचल वाली जमानत याचिका

रतीश चंद्र श्रीवास्तव
संपादकीय प्रभारी, रायपुर

प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका अचानक चर्चा में आ गई है। आक्रामक बयानबाजियों के कारण प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डा. चरणदास महंत से कहीं अधिक चर्चा में रहने वाले भूपेश का यह कदम आने वाले दिनों के लिए संकेत भी है। बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। 3,200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले, छह हजार करोड़ के महादेव सट्टा एप घोटाले और 540 करोड़ रुपये के कोयला परिवहन घोटाले में घिरने की स्थिति बन रही है। सुनवाई के बाद आज यदि उन्हें अग्रिम जमानत मिल भी जाती है तो चर्चा जारी ही रहेगी।

पिछला पखवाड़ा भी सांप्रदायिक राजनीति में जमानत के नाम रहा। प्रदेश का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया। मतांतरण और मानव तस्करी के आरोप में 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर दो ननों की गिरफ्तारी के बाद संसद परिसर में प्रदर्शन हुआ। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शीतकालीन सत्र में मतांतरण के विरुद्ध कड़ा कानून लाने की बात की है तो भूपेश बघेल ने 2006 में विधानसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास अटके विधेयक को ही लागू करने की आवाज उठाई है। यहां बघेल ने यह नहीं बताया कि 2004 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उनकी पार्टी ही विधेयक पास नहीं होने देने के लिए जिम्मेदार रही।

विवाद और चर्चा का केंद्र बनी दोनों ननों को हाई कोर्ट से स्वतंत्र जमानत मिली तो समर्थकों ने मिठाइयां बांटीं। साथ ही पूरा घटनाक्रम व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न भी खड़े कर गया है। ननों से मुक्त कराई गई आदिवासी लड़कियों के मतांतरित होने का दावा किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है कि वह लड़कियां आधिकारिक रूप में मतांतरित नहीं थीं। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार मतांतरण से 60 दिन पहले जिलाधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए और मतांतरण के बाद भी सूचना दी जानी चाहिए। नारायणपुर की तीनों लड़कियों के मामले में ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए मतांतरण अवैध है। यहां बार-बार याद दिलाया जाना आवश्यक है कि 2000 से 2003 के बीच अजीत जोगी के सरकार में 232 लोगों ने आधिकारिक तौर पर मतांतरण किया तो डा. रमन सिंह के 2004 से 2018 के कार्यकाल में 131 ने तथा भूपेश बघेल के 2018 से 2023 के कार्यकाल में सिर्फ एक आधिकारिक मतांतरण हुआ। अब यह सरकार की जिम्मेदारी है कि अवैध मतांतरणों का मामला दर्ज कर कार्रवाई करे।

भूपेश बघेल। फाइल

विष्णु देव साय। फाइल

सरकार ने अभी तक पूरे मामले की जांच के लिए कोई पहल नहीं की है तो इसके पीछे अगले वर्ष केरल में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को माना जा रहा है, जहां मुसलमानों की आक्रामकता से परेशान ईसाइयों के मतों के रूप में समर्थन मिलने की भाजपा को उम्मीद है। दुखद पक्ष यह भी है कि दुर्ग स्टेशन पर मुक्त कराई गई लड़कियां ननों को जमानत मिलने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर गंदे और भद्दे आरोप लगा रही हैं। आरोप सही हों तो कार्रवाई आवश्यक है, परंतु सत्ता पक्ष को इस बात की चिंता करनी चाहिए, ताकि धर्म रक्षकों को हतोत्साहित नहीं होना पड़े। पूरे मामले की बिना देरी और समयबद्ध स्वतंत्र जांच आवश्यक है।

ननों की गिरफ्तारी ने दशकों से माओवादी हिंसा का दंश झेल रहे प्रदेश में मिशनरियों, वामपंथी-माओवादियों और उनके समर्थक कोठेसियों का गठजोड़ एक बार फिर प्रमाणित किया है। इसकी भी स्वतंत्र जांच की अपेक्षा की जानी चाहिए कि जब अबूझमाड़ के जंगलों में माओवादी हिंसा के कारण सरकारी कर्मचारी स्वास्थ्य और शिक्षा का काम करने नहीं पहुंच पा रहे थे तो वहां मतांतरण कैसे संभव हुआ। मामला सिर्फ दो ननों का नहीं है। पूरे नेटवर्क का है। राष्ट्रीय के साथ ही अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है। सत्य को सामने लाकर ही चेहरों को बेनकाब किया जा सकता है। इसके लिए आदिवासी नेताओं को भी पूरी मजबूती से आगे आना होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम के नेतृत्व में सर्व आदिवासी समाज सक्रिय हो चुका है कि मतांतरितों को आदिवासियों को मिलने वाली सुविधा से वंचित किया जाए, क्योंकि वह अल्पसंख्यकों को मिलने वाली सुविधाओं का भी लाभ उठा रहे है। इन मामलों में परिणाम सत्तापक्ष के हितों और इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा। संदेह जताया जा रहा है कि राजनीतिक कारणों से यह विषय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विरुद्ध 2017 के सेक्स सीडी कांड की तरह ही लंबे समय तक अटका रह सकता है। 14 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहे बघेल के विरुद्ध जांच सीबीआइ के पास है। सरकार बदलने के बाद सबकुछ अटक गया था। फरवरी 2025 से फिर सुनवाई शुरू हुई है। इतना तो स्पष्ट है कि सत्ता में बैठे शुभचिंतक-गुप्तचर अधिकारियों की तरफ से संकेत और संदेश के बाद ही भूपेश द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई है। बहुत मुश्किल नहीं कि पूर्व मुख्यमंत्री को अग्रिम जमानत मिल भी जाएगी, परंतु भ्रष्टाचार के दाग तो लगे ही हुए हैं। महादेव सट्टा एप को संरक्षण देने के नाम पर 508 करोड़ रुपये लेने के आरोपों को सिद्ध करना अगर ईडी, सीबीआइ और ईओडब्ल्यू जैसी एजेंसियों के लिए चुनौती है तो बेदाग निकलना बघेल के लिए भी मुश्किल भरा रहेगा।

****

तथ्यों के अलावा कुछ भी मायने नहीं रखता। इनके बिना, आपराधिक जांच बस अनुमान का खेल है। -ब्लेक एडवर्ड्स

अमेरिका की धमकियों की परवाह न करते हुए भारत का रूस से तेल खरीदना जारी रखने का निर्णय दर्शाता है कि वह किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करेगा। फिलहाल वही कूटनीतिक कौशल दिखाने का वक्त है, जिससे भारत अपने हितों को प्राथमिकता देते हुए वैश्विक शक्तियों के बीच संतुलन रखता आया है।

राष्ट्रहित सर्वोपरि

हाल ही में रूस से तेल खरीदने के खिलाफ दी गई अमेरिकी चेतावनी के बावजूद भारत का अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूसी तेल की खरीदारी जारी रखने का निर्णय उसकी स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति का परिचायक तो है ही, इससे यह भी साफ है कि भारत वैश्विक दबावों के सम्मुख झुकने के बजाय अपनी संप्रभुता, स्वायत्तता और आर्थिक हितों का ख्याल रख सकता है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है, जो अपनी कुल जरूरत का 85 फीसदी तेल आयात करता है। यूक्रेन संकट के बाद पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण रूसी तेल की कीमतें अन्य स्रोतों की तुलना में काफी कम हो गईं। भारत ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए एक तरफ तो रूस से तेल आयात को बढ़ाया, तो दूसरी तरफ पश्चिमी देशों को भी यह कहते हुए साधा कि यह शांति के पक्ष में है। इस कूटनीतिक कदम से भारत ने वैदेशिक संबंधों में तो संतुलन बनाया ही, आंतरिक व्यवस्था पर पड़ रहे दबाव को भी बेअसर कर दिया। यहां यह भी समझना जरूरी है कि भारत का रूस से तेल आयात केवल आर्थिक लाभ तक सीमित न होकर, देश की रणनीतिक स्वायत्तता का भी प्रतीक है। रूस भारत का पुराना और परखा हुआ सहयोगी रहा है, पर वैश्विक मंच पर भारत ने हमेशा ही एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है, जहां वह किसी गुट के साथ पूर्णतः संरेखित होने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। यह बात सिर्फ रूस से तेल आयात पर ही लागू नहीं होती, इसका प्रमाण भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में हो रही देरी की वजहों में भी मिलता है। दरअसल, अमेरिका, भारत से अपने डेयरी और कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में रियायत चाहता है, जबकि भारत यह कहते हुए इसके लिए तैयार नहीं है कि ये क्षेत्र किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत ने उस एफ-35 फाइटर जेट को खरीदने के प्रति भी अनिच्छा दिखाई है, जिसका प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा

के दौरान खुद ट्रंप ने दिया था। दरअसल, ट्रंप ने भारत पर जो टैरिफ व जुर्माना लगाया है, उसके पीछे उनकी खीज ही ज्यादा दिखती है। वह बार-बार दावा करते हैं कि भारत-पाकिस्तान युद्ध उन्होंने रुकवाया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने यह स्पष्ट किया कि दुनिया के किसी नेता ने उनसे ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा। यही नहीं, ट्रंप के टैरिफ को लेकर घरेलू स्तर पर तो शंकाएं व्यक्त की ही जा रही हैं, उनके अब तक रूस और यूक्रेन का युद्ध न रुकवाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने 85 फीसदी तेल आयात करने वाले पाकिस्तान के साथ भी हैरतअंगेज तेल समझौता किया है। ऐसे में, रूस से व्यापारिक संबंध बनाए रखने का साहसिक निर्णय लेकर भारत ने एक संदेश तो दिया ही है।

आखिर जांच एजेंसियां कर क्या रही हैं

यातना देकर लिए गए इकबालिया बयानों से मीडिया में सुर्खियां तो बन सकती हैं, लेकिन अदालत में मामले को टिकाने के लिए ठोस सबूत पेश करने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष की होती है। किसी को दोषी ठहराने के लिए सुसंगत तथ्य, साक्ष्यों की शृंखला और निर्णायक साक्ष्यों का होना जरूरी है।

विराग गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट के वकील

दीवानी मामलों में नाती-पोतों को न्याय मिल जाए, तो उन्हें भाग्यशाली माना जाता है। आपराधिक मामलों में दशकों बाद फैसला आने पर आरोपी, गवाह, अभियोजन और पीड़ित किसी भी पक्ष को न्याय नहीं मिलता। नए आपराधिक कानून में तीन साल के भीतर मामलों के निपटारे की बात की जा रही है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, साल-2022 में लगभग 58 लाख मामले दर्ज किए गए और 53 लाख से ज्यादा गिरफ्तारियां हुईं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज संजय किशन कौल के अनुसार, अपील के बढ़ते चलन की वजह से लंबित और नए मुकदमों के निपटारे में 500 साल से ज्यादा लग सकते हैं। निठारी कांड, मुंबई बम धमाका और मालेगांव विस्फोट जैसे चर्चित मामलों में सीबीआई, एनआईए और एटीएस जैसी एजेंसियों के लंबे-चौड़े आरोपपत्र के बावजूद आरोपियों को रिहाई से पूरे न्यायिक तंत्र के खिलाफ भरोसा डगमगाने से लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। न्यायिक तंत्र की विफलता को समझने के लिए तमिलनाडु के पूर्व मंत्री बालाजी मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजों की मौखिक टिप्पणियों की झलक काफी है। बालाजी के खिलाफ घूस लेकर नौकरी देने के आरोप में 2,000 आरोपियों और 500 गवाहों को शामिल करने पर जस्टिस सूर्यकांत ने राज्य सरकार को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि ऐसे में तो मुकदमे के ट्रायल के लिए अदालत के कमरे के बजाय क्रिकेट स्टेडियम की जरूरत होगी। जजों के अनुसार, न्यायिक हस्तक्षेप नहीं होता तो राज्य सरकार सैंधल मामले को दफन करना चाहती थी। जजों ने कहा कि मंत्री, नौकरशाह और संपन्न लोगों के मुकदमों में जनता में यह धारणा है कि सिर्फ अभियोजन पक्ष और सरकारी वकील के माध्यम से न्याय मिलना मुश्किल है।

जजों की कठोर टिप्पणी की तस्दीक मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और भाजपा नेता सत्यपाल सिंह के बयानों से होती है। उनके अनुसार, मालेगांव विस्फोट मामले सहित कई मामलों में राजनीतिक लाभ से प्रेरित जांच में सबूतों को गढ़ा जा रहा था। सनद रहे कि संविधान के अनुसार पुलिस का

विषय राज्य सरकारों के अधीन आता है। कानून के अनुसार लाखों अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक निरपराध को सजा नहीं होनी चाहिए। यातना देकर लिए गए इकबालिया बयानों से मीडिया में सुर्खियां तो बन सकती हैं, लेकिन अदालत में मामले को टिकाने के लिए ठोस सबूत पेश करने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष यानी जांच एजेंसी और राज्य सरकार की होती है। बचाव पक्ष की कमजोरी के आधार पर आरोपियों को सजा नहीं दी जा सकती। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषी ठहराने के लिए सुसंगत तथ्य, साक्ष्यों की शृंखला और निर्णायक साक्ष्य जरूरी हैं।

मालेगांव मामले में बरी हुए समीर कुलकर्णी ने कहा कि बचाव और अभियोजन, दोनों पक्ष मुकदमों को लंबा खींचना चाहते हैं। उनके अनुसार, सह-आरोपियों ने वकील नहीं रखा होता, तो मुकदमा 15 साल पहले खत्म हो गया होता। उसी सिलसिले का दूसरा पहलू सुरेन्द्र कोली है। उसने अपने मामले की खुद ही पैरवी करते हुए अभियोजन पक्ष की जांच में खोट को उजागर कर दिया। निरक्षर कोली जेल में रहकर साधर बना और कानून की किताबों की पढ़ाई की। उसने फॉरेंसिक लैब, विकास प्राधिकरण, अस्पताल और पुलिस विभागों में एक हजार से ज्यादा आरटीआई लगाकर सरकारी विभागों के जवाब और सीबीआई की चार्जशीट में विसंगतियों को उजागर किया।

एनआईए की विशेष अदालत के फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार की एटीएस एजेंसी की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अदालत से पहले मकोका के आरोप खारिज हो गए और फिर यूएपीए की मंजूरी को अवैध और खामियों से भरा माना गया। पंचनामे में गलतियां, गवाहियों में विरोधाभास, मूल दस्तावेज गायब होने और चापलूसी के फर्जी प्रमाण-पत्रों पर अदालत ने एटीएस को फटकार लगाई। कॉल डाटा रिकॉर्ड (सीडीआर) के साथ जरूरी 65-बी के सर्टिफिकेट और नार्को टेस्ट रिपोर्ट को पेश नहीं करने का फायदा आरोपियों को मिला। केंद्रीय एजेंसी एनआईए ने राज्य की एटीएस पर सबूत गढ़ने का आरोप लगाया था। उनका धीरे-धीरे खुलासा होने पर यह साफ हो रहा है कि किस तरह नेताओं के इशारे पर जांच एजेंसियां राजनीतिक विरोधियों को फंसा सकती हैं?

मुंबई ट्रेन धमाकों में 19 साल पहले 187 लोगों की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के फैसले को पलटते हुए 12 अभियुक्तों को बरी कर दिया। आरोपियों को जेल से रिहाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। पीड़ितों के अनुसार, यह फैसला जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि सभी आरोपी बेगुनाह हैं, तो इतने बड़े आतंकी कृत्य का जिम्मेदार कौन था?

मालेगांव मामले में अदालत ने मृतक पीड़ित परिवारजनों को दो लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। जिन लोगों को पुलिस और जांच एजेंसियों ने फर्जी तरीके से फंसाया उनकी पीड़ा, अपमान, यातना, पारिवारिक संकट और सामाजिक कलंक की भरपाई कैसे हो सकती है? गलत जांच करने वाले लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून में प्रावधान हैं। अब सीआरपीसी कानून की धारा-250 और नए बीएनएसएस की धारा-193 के तहत आरोपियों के लिए भी रिहाई के बाद हर्जाने की मांग होने लगी है।

आतंकवाद को धर्म से जोड़ने को नकारते हुए मालेगांव फैसले में जज ने कहा कि जन धारणाओं और मीडिया ट्रायल के आधार पर आपराधिक मुकदमों का फैसला नहीं हो सकता। यदि कोई संगठन गैरकानूनी नहीं है तो सिर्फ उससे जुड़े रहने पर किसी को अपराधी नहीं माना जा सकता। बिखरे गवाह, उलझे सबूत और आरोपियों की लंबी लिस्ट वाले मुकदमों के ट्रायल में कई दशक लग जाते हैं। उसके बाद रिहा हुए आरोपियों, थके हुए पीड़ित परिवार और डरे हुए गवाहों के लिए पुलिस और अदालत की यंत्रणापूर्ण लंबी प्रक्रिया सबसे बड़ा दंड है। कई दशकों में मामले की कई जजों की सुनवाई के बाद फैसला तो आखिरी जज ही लिखते हैं। इससे न्यायिक प्रशासन की कार्यपद्धति पर सवाल उठ रहे हैं? संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। विशेष अदालत के हजारों पेज के फैसले और जांचपत्र के लाखों पेज के दस्तावेजों वाले मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट में संक्षिप्त नोट के आधार पर सुनवाई और फैसले को ध्यान में रखते हुए जल्द और सही न्याय की संभावना को तलाशना बेहद जरूरी है।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

फ्रांसिस बेकन

हमारे पास बस यही पल है, जो हमारे हाथ में एक तारे की तरह चमक रहा है और बर्फ के टुकड़े की तरह पिघल रहा है। इसलिए जो लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं, उसे अभी से शुरू करें।

जीवन तारे की तरह चमक और बर्फ की तरह पिघल रहा

जिंदगी एक ऐसी किताब है, जिसके हर पन्ने पर एक नई सीख छिपी होती है। ज्ञान ही शक्ति है। हमारी जिंदगी में अगर कुछ हमें आजादी दे सकता है, तो वह है जानने की ताकत। ज्ञान वह दीया है, जो अंधेरे को चीरता है। लेकिन ज्ञान को सिर्फ किताबों तक सीमित मत कीजिए। जिंदगी की हर घटना, हर मुलाकात एक सबक है। इसे खुले दिल से सीखें। विरोध और खंडन के लिए नहीं पढ़ें, न ही विश्वास करने और मान लेने के लिए, न ही बातचीत और संवाद खोजने के लिए, बल्कि तौलने और विचार करने के लिए पढ़ें। यानी निर्णय लेने से पहले किसी चीज का सावधानीपूर्वक और सोच समझकर मूल्यांकन करने के लिए।

हमारे पास बस जीवन का यही पल है, जो हमारे हाथ में एक तारे की तरह चमक रहा है और बर्फ के टुकड़े की तरह पिघल रहा है। इसलिए जो लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं, उसे अभी से शुरू करें। जिंदगी में सुख और दुख, दोनों आते हैं। खुशहाली में डर और नाउम्मीदी होती है, और विपत्ति में भी सांत्वना और उम्मीदें छिपी होती हैं। जब हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा लगे, तो गर्व में मत डूबें और जब मुश्किलें आएं, तो हिम्मत मत हारें। बुद्धिमान व्यक्ति मौकों को ढूंढने से ज्यादा उन्हें बनाता है। हमारे आसपास हर गली-मोहल्ले में मेहनत और जुनून की कहानियां बिखरी हैं। यह बात कितनी सटीक है कि आशा एक अच्छा नाश्ता है, लेकिन यह एक बुरा रात्रिभोज है। जिंदगी हमें हमेशा तैयार मौके नहीं देगी। अगर हम मेहनत और समझदारी से काम करें, तो अपने लिए रास्ते और मौके बना सकते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को एक नया आकार देते हैं, वैसे ही हम अपनी मेहनत से अपनी तकदीर गढ़ सकते हैं।

अपने प्रियजनों के लिए बलिदान देने को हमेशा तैयार रहें, लेकिन इस बीच खुद को मत भूलें। एकांत में रहें। शांत रहना, ज्ञान और समझ को विकसित करने में मदद करता है, जैसे नींद शरीर और दिमाग को तरोताजा करती है। ऐसा संतुलन बनाएं कि अपने सपनों को भी जी सकें। जिंदगी में समय का बहुत महत्व है। इन्सान की जिंदगी उसकी सांसों से ज्यादा लंबी नहीं। हर सांस कीमती है। हर पल को जिएं। न आने वाले कल के लिए बहुत चिंता करें, न बीते हुए कल में उलझें। वर्तमान में जिएं, क्योंकि यही आपका सच्चा धन है। हर विचार को परखें, हर सवाल को गहराई से समझें। हम जो पढ़ते हैं वह नहीं, बल्कि हम जो याद रखते हैं, वह हमें विद्वान बनाता है। हम जो खाते हैं वह नहीं, बल्कि हम जो पचाते हैं, वह हमें मजबूत बनाता है। हम जो प्राप्त करते हैं वह नहीं, बल्कि हम जो बचाते हैं, वह हमें अमीर बनाता है। और हम जो दावा करते हैं वह नहीं, बल्कि हम जो आचरण करते हैं, वह हमें ईमानदारी प्रदान करता है। यही है जिंदगी जीने का सच्चा तरीका। जिंदगी एक यात्रा है। इसे डर से नहीं, बल्कि हिम्मत और समझदारी से जिएं।

हमेशा ईमानदार रहें

जिस प्रकार हम मिट्टी से कभी दीया, तो कभी सुंदर मूर्ति बनाते हैं। उसी प्रकार अपने जीवन में ज्ञान के सहारे स्वयं को हर पल एक नया और सबसे बेहतर रूप दे सकते हैं। किताबें जरूर पढ़ें, लेकिन सबसे जरूरी है, जिंदगी को पढ़ना। अपने व दूसरों के प्रति हमेशा ईमानदार रहें, जीवन सुंदर हो जाएगा।

सूत्र

दूसरा पहलू

एक-दो नहीं, ऐसे 36 गांव हैं, जिनका नामकरण भारतीय शास्त्रीय संगीत की राग-रागिनी, लय और ताल पर हुआ है।

जब गांवों के नाम रागों पर रखे गए

हरियाणा की जींद रियासत के महाराजा देवराज गीत-संगीत के इतने बड़े शौकीन थे कि किसी ज्ञानी का राग मन को भा जाए, तो नया गांव तो बसा देते थे। इस रियासत में ऐसे एक-दो नहीं, ऐसे 36 गांव हैं, जिनका नामकरण भारतीय शास्त्रीय संगीत की रागिनी, लय और ताल पर हुआ है। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल चुका है, पर ये गांव आज भी आबाद हैं।

नवीन सिंह पटेल

ब्रिटिश गजेटियर के अनुसार, वर्ष 1755 में राजा गनपत सिंह ने जींद और सफीदों परगना पर कब्जा करके जींद शहर को राजधानी बनाया था। हालांकि, उनकी रियासत को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से 1772 में राजा का खिताब मिला। गनपत और उनके बाद के राजाओं को संगीत से लगाव था। इसकी वजह गांवों और रागों पर विशद पड़ताल करने वाले सेवानिवृत्त शिक्षक जगदीश बताते हैं, कि उस दौर में घोड़ाओं के सम्मान में दिल्ली में खूब जश्न रखे जाते थे। दिल्ली के अधीन होने के कारण यहां के राजा उनकी खिदमत के लिए संगीत के मर्मज्ञों को संरक्षण देने लगे। खुद भी लड़ाकों के सम्मान में राग दरबार लगाने लगे। देश के दूसरे हिस्सों से आए उस्ताद दरबार में हुनर दिखाते थे। ऐसी मान्यता है कि 18वीं सदी में जींद के महाराजा देवराज के दरबार में जो भी मधुरता का राग घोल देता, वे उसी राग पर गांव का नाम रखकर गायक को वहीं आबाद कर देते थे। राग आधारित गांवों का नामकरण मुख्यतः इन्हीं के दौर में हुआ।

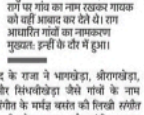

महाराजा देवराज के दरबार में जो भी मधुरता का राग घोल देता, वे उसी राग पर गांव का नाम रखकर गायक को वहीं आबाद कर देते थे।

फुलकियां स्टेट (पटियाला, जींद और नाभा) गजेटियर (1904) के मुताबिक, जींद के राजा ने भागखेड़ा, श्रीरामखेड़ा, पिल्लूखेड़ा, मालसरी, रामकली, भैरोंखेड़ा और सिंघवीखेड़ा जैसे गांवों के नाम विभिन्न रागों पर ही रखे हैं। इसकी पुष्टि राग संगीत के मर्मज्ञ बसंत की लिखी *संगीत विशारद* ग्रंथ से भी होती है। हालांकि, हरियाणवी लोक गायक और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पद्मश्री महाशेर गुड्डू की खोज कुछ अलग है। वह कहते हैं, पंजाबी संस्कृति में फले-फूले हरियाणा में संगीत को कभी ज्यादा जगह नहीं मिली। यह चंद लोगों तक सिमटी हुई थी, जिन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता था। गांवों में स्वरलहरियां बहतीं, तो गीत-संगीत की परंपरा इतनी जल्दी खत्म नहीं हो जाती। यह सच है कि ढाई सौ साल पहले की विरासत के निशां आज इन गांवों में कहीं नहीं दिखते। मगर, जींद के जयंतीदेवी संग्रहालय और कुरुक्षेत्र के म्यूजियम में संरक्षित वाद्य यंत्र जींद रियासत की सांगीतिक समृद्धि की गवाही तो देते ही हैं।

आंकड़े

नए फोन की चाहत

नए फोन खरीदने की चाहत सिर चढ़कर बोल रही है। लोग पुराना फोन होने के बावजूद नया फोन खरीद रहे हैं। इसमें भारत के लोग सबसे आगे हैं।

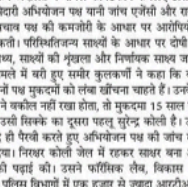

आंकड़े फोन के बावजूद नया फोन खरीदने वालों के प्रतिशत में। चार्ट : Statista

एक साल भयंकर सूखा पड़ा, फसलें सूख गईं, और रामू को अपने दो बैल बेचने पड़े। सावन के आखिरी सोमवार तक उसकी भक्ति ने चमत्कार कर दिखाया।

भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती

अंतर्यात्रा
संकलित

एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था, जो भगवान शिव का परम भक्त था। वह रोज पूजा करता, भक्ति में डूबा रहता। गांव की आजीविका खेती थी, पर एक साल भयंकर सूखा पड़ा। बारिश न होने से फसलें सूख गईं, और रामू को अपने दो बैल बेचने पड़े। गांव वाले हंसते, कहते, 'रामू, भगवान कहां सुनते हैं? जा, कहीं नौकरी कर ले, अब बारिश नहीं होगी।' लेकिन रामू की आस्था अटल थी। उसने सावन के सोमवार को भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। रोज वह शिव मंदिर में जाकर ध्यान करता।

सावन का आखिरी सोमवार आया। रामू रातभर जागकर शिव का नाम जपता रहा। तभी आधी रात को मंदिर में एक दिव्य प्रकाश हुआ। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, 'रामू, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। सच्चे मन की पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती।' उसी रात, रामू के घर दो बैल खड़े मिले, मानो स्वयं शिव ने भेजे हों। सुबह होते ही आसमान में काले बादल छाए, और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव वाले, जो रामू का मजाक उड़ाते थे, अब उसके पास आकर बोले, 'रामू, तुम्हारी भक्ति ने चमत्कार कर दिखाया।' अगले दिन पूरा गांव खेती के लिए निकला। रामू की भक्ति ने सबको सिखाया कि सच्चे मन से की गई भगवान की भक्ति हर संकट को दूर कर देती है। गांव में फिर से हरियाली लौट आई।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 04 अगस्त, 1959

रिजर्व बैंक को व्यापक अधिकार दिए जाएं

संसद की संयुक्त प्रवर समिति ने बैंकिंग कंपनी विधेयक पर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बैंकों पर नियंत्रण हो और वे बेहतर ढंग से चलें, इसके लिए रिजर्व बैंक को व्यापक अधिकार दिए जाएं।

किसको दें दोष, रिसते प्राकृतिक कोष

सबमर्सिबलों के बढ़ते चलन ने भू-जल को भी निजी मिल्कियत बना दिया है। नदियां आज कचरा ठिकाने लगाने का साधन बन गई हैं।

सुरेंद्र बांसल — **पर्यावरण**

हमारे देश में जो कुछ भी सर्वसंपदा है, वह सब नदियों, वनों, पहाड़ों, पशु-पक्षियों और मिट्टी की आत्मीयता के सान्निध्य से ही आया है। यानी हम प्रकृति की अपार अनुकंपाओं के वारिस हैं। इसलिए सदियों से हमारी गिनती प्राकृतिक संसाधनों से संपन्नतम देशों में होती रही है। लेकिन बीते दो सौ वर्षों की आधी-अधूरी और देश विस्मृत शिक्षा व्यवस्था के कारण हमारा समाज आज प्रकृति के इन उपकारों को भूल गया है।

नतीजतन भयंकर वन विनाश के चलते भूक्षरण की घटनाएं होती हैं और वर्षाजल अपने साथ उपजाऊ मिट्टी समुद्र में बहा ले जाता है। तालाब, झील, पोखर और नदियां जैसे सार्वजनिक जलाशयों की दुर्गति ने इस समस्या को बढ़ाया ही है। नलकूपों और सबमर्सिबलों के बढ़ते चलन ने भूमिगत जल को भी निजी मिल्कियत का साधन बना दिया है। हमारी देवी स्वरूपा नदियां आज शहरी और औद्योगिक कचरा ठिकाने लगाने का साधन बन गई हैं।

एक समय ऐसा भी था, जब हमारे शहरों, कस्बों और गांवों में तालाब, पोखर एक पवित्र सार्वजनिक संपदा की तरह संभाल कर रखे जाते थे। प्रतिवर्ष इन जलकोषों की साफ-सफाई और गाद निकालने का काम समाज खुद करता था। लेकिन नीति-निर्माताओं ने पोखर, तालाब, कुओं जैसी किफायती प्राकृतिक परियोजनाओं की भरपूर उपेक्षा कर इन्हें अनुपयोगी ही मान लिया। अब तक किसी सरकार ने ऐसा कोई प्राथमिक सर्वेक्षण नहीं करवाया कि देश में आखिर कितना पानी है? प्रतिवर्ष बिगड़ते हालात के बावजूद हम कभी अपने जल संसाधनों की चिंता नहीं करते, बल्कि उनका उपभोग लापरवाही से कर रहे हैं। कितनी विचित्र बात है कि देश में उपलब्ध जलराशि के बारे सही तथ्य, आंकड़े इकट्ठा करने का हमारी सरकारों के पास कोई प्रबंध ही नहीं है। कुशल नीति बनाने और संसाधनों के उचित प्रबंधन तो दूर की बात है। देश भर में घरेलू उपयोग और सिंचाई के लिए जितना पानी रोजाना खर्च होता है, उससे कई गुना अधिक पानी तो प्रतिदिन हमारे-आपके वाहनों की धुलाई में व्यर्थ हो रहा है, वह भी पीने योग्य मीठा पानी।

अगर हम सिर्फ हरियाणा, पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की जलनीति को देखें, तो रोना आता है। जिस हरियाणा, पंजाब में जंगल आज नाममात्र के बचे हैं, वहां आज लगभग तीस लाख सबमर्सिबल चल रहे हैं। उसमें से अकेले पंजाब में ही साढ़े 18 लाख सबमर्सिबल दिन-रात भू-जल उलीच रहे हैं। इन दोनों राज्यों के लगभग 70 प्रतिशत भू-जल क्षेत्र डार्क जोन में हैं। राजधानी दिल्ली की हालत तो और अधिक दयनीय है। प्रतिवर्ष फरवरी-मार्च में दिल्ली में पानी की खूब किल्लत होने लगती है, लेकिन मजा देखिए कि दिल्ली के अधिकांश नेताओं के घरों में छोटे-बड़े 'स्विमिंग पूल' अवश्य मिल जाएंगे। पानी के टैंकर माफिया तो अब 'संरक्षित माफिया' की श्रेणी में आते हैं। आज देश में उपलब्ध पानी का लगभग 70 प्रतिशत भाग प्रदूषित हो चुका है। इस प्रदूषित पानी के सेवन से कई बीमारियां पैदा होती हैं, जिससे असंख्य कार्यदिवस नष्ट हो रहे हैं। गैर-जरूरी विकास के नशे में धुत हमें इसका जरा भी बोध नहीं कि ये प्राकृतिक संसाधन कितने कीमती हैं।

प्रकृति अपने प्रत्येक सुख-दुख का निदान खुद करती है। देश में बनने वाली प्रत्येक नीति का आधार मात्र इतना होना चाहिए कि वह प्रकृति सम्मत और पर्यावरण के अनुकूल हो। आर्थिक और सामाजिक विकास का रूप कैसा होना चाहिए, यह नीति निर्धारकों को स्पष्ट होना ही चाहिए, क्योंकि इसी पर निर्भर होगा कि हमारे जल संसाधनों में सुधार होगा या नहीं। तथाकथित विकास के नाम पर हमने कुछ ऐसा ढांचा रच लिया है, जो हमें अपने आसपास के पर्यावरण से जोड़ने के बजाय तोड़ता अधिक है। विज्ञान और तकनीक का भले विकास हुआ हो, प्रकृति से तालमेल बिठाने के मामले में हम लगातार पीछे चले गए हैं। विज्ञान और तकनीक भी तभी सार्थक और लाभकारी होते हैं, जब समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध मूल्य अपनाए जाएं।

विकास का व्यापक और विराट अर्थ प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों को निरंतर समृद्ध करना है। विकास यह सतत बहने वाली प्रक्रिया है, जो समाज के हर स्तर को पहले से अधिक स्वावलंबी, सहज, सरल और तनाव रहित बनाए। समाज और देश का स्वावलंबन तब तक संभव नहीं, जब तक भीतर-बाहर के पंचभूत समृद्ध नहीं होते। और ये समृद्धि राज और समाज में दूरी बढ़ाने से नहीं, बल्कि जनभागीदारी से संभव होगी। उपभोग के दांचे के प्रति बेहद सतर्कपूर्ण बरतने से संभव होगी। अपनी अनमोल परंपराओं पर श्रद्धा की पुनर्स्थापना से संभव होगी। मछुआरों, कुम्हारों, आदिवासियों, पशुपालकों, किसानों और मिट्टी पर नंगे पांव चलने वालों की बात सुनने से संभव होगी। लोक व्यवहार के मूल्यों को गाली देने से जो अंधे बीहड़ हमने अपने आसपास रच लिए हैं, उसमें निरर्थक बौद्धिकता और सामाजिक तल्खी के कैक्टस तो उगाए सकते हैं, खिलखिलाते पारिजात नहीं।